हम कर दिखाएंगे

लोकतंत्र में किसी भी राजनेता के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे करना सचमुच विरल है। दुनिया की दिग्गज हस्तियों में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 25 साल सदैव चर्चा और विमर्श का विषय रहेंगे। उनके बारे में यह पहले ही कहा गया था कि वह मात्र शासन करने नहीं, बल्कि राष्ट्र बदलने आए हैं। बहुत कुछ बदल गया, और अब 25वां वर्ष पूरा करते हुए भी वह बहुत कुछ करने के उत्साह से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को फिर से सामने रखते हुए एक आह्वान किया है- 'वी विल डु इट', अर्थात हम इसे करेंगे। 'वी विल डु इट' में विकसित भारत, देश में ओलंपिक का आयोजन और अंतरिक्ष में कदम रखने का लक्ष्य प्रमुखता से शामिल है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में जनसेवा के अपने सफर का विस्तार से हवाला देते हुए स्वीकार किया है कि उनके आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों ने ही उन्हें लोकतंत्र की ताकत सिखाई है। उन्होंने ही उन्हें आत्म-निरीक्षण करना सिखाया है।

प्रधानमंत्री ने जन-शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन में आए अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों का उल्लेख किया है। देश की तेज आर्थिक तरक्की का वर्णन करते हुए उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। देश के संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने भविष्य की एक रूपरेखा सामने रखी है। स्वाभाविक ही, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनावी लाभ के लिए समाज को जाति और समुदाय के आधार पर बांटने की प्रवृत्ति है, जिस पर प्रधानमंत्री ने उचित प्रहार किया है। खेतों में पानी की कमी होती है, तो कोई एक जाति ही प्रभावित नहीं होती है। जब बिजली नहीं होती है, तो केवल एक समुदाय के घर अंधेरा नहीं छाता है। सचमुच, अगर समस्या सबकी है, तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह धारणा हमारे संविधान से प्रेरित है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसी के अनुरूप चलना चाहिए। राजनेताओं के लिए जनता ही भगवान होनी चाहिए। जनता के कष्ट को समझना और समाधान ही नेताओं का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के नाम अनेक उपलब्धियां हैं, पर उन्होंने माना है कि सीखने की लगन उनके जीवन का अंग है और वह खुद को अब भी विद्यार्थी मानते हैं। यहां सबक सबके लिए है- सीखते जाने में बढ़ते जाने का सलीका शामिल है।

भारत के आर्थिक-सामाजिक विकास के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वी विल डु इट' उद्घोष व्यापक और उपयोगी है। वाकई, देश में बहुत कुछ संभव है।

आज आर्थिक-सामाजिक विकास के क्रम में प्रधानमंत्री का यह 'वी विल डु इट' उद्घोष व्यापक और उपयोगी है। भारत में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो यह मानते रहे हैं कि देश अशक्त है। इसमें इतनी कमियां हैं कि यह विकसित नहीं हो सकता। अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो बार-बार एहसास दिलाते हैं कि 'भारत का कुछ नहीं हो सकता।' हार जाने या हतोत्साहित हो जाने की इस प्रवृत्ति से उबरने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के उद्घोष- 'वी विल डु इट' को हर स्तर पर आत्मसात किया जाए, तो स्वाभाविक ही आगे की राह दिखने लगेगी। यह भारत के लिए तेज कदमों से बढ़ने का समय है। देश में बहुत कुछ संभव है। वाकई, कौन मानता था कि अनुच्छेद 370 की समस्या का हल हो जाएगा या नक्सलवाद का अंत हो जाएगा या भारत अपनी सीमा के पार पहुंचकर आतंकियों से बदला लेगा? ऐसे अनेक कार्य हैं, जो नरेंद्र मोदी के शासन को आभा प्रदान करते हैं। संदेह नहीं, चुनौतियों का अभी भी अंबार है, पर सबको संकल्प लेना होगा- 'वी विल डु इट'।



राज कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

अविश्वास खतरनाक मोड़ तक न पहुंचे

चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी पक्षों को इस समय संयम बरतने की जरूरत है। विपक्षी नेताओं को देश की सर्वोच्च अदालत पर संदेह से बचना चाहिए।

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद शुरू आत तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल सभी विपक्षी दल उठाते रहे हैं। इसीलिए दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और एकतरफा फैसलों पर 10 महीने में 14 बार आपत्तियों की बावत मीडिया-खुलासे के बाद आक्रामक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आया है। विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक ने लंबे आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें राष्ट्रपति से मुलाकात से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध संसद में महाभियोग लाना भी शामिल है।

विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध आंदोलन अनहोनी घटना नहीं है, लेकिन मंगलवार को सैकड़ों विपक्षी सांसदों के संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह आकाशवाणी भवन में घुसकर धरने पर बैठ गए, उससे विपक्ष के आक्रामक तेवर के संकेत मिलते हैं। अन्य नेताओं के साथ आठ घंटे से भी ज्यादा समय तक आकाशवाणी भवन में बैठे रहे राहुल-प्रियंका को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर हटाया, तब भी उनके जुझारू तेवर साफ दिख रहे थे।

जिस दिन भाजपा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही थी, ठीक उसी दिन लंच के बाद विपक्षी सांसदों का अचानक जंतर मंतर कूच भी लंबे संघर्ष की विपक्षी रणनीति का संकेत है। 'जेन-जी' आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक बड़े सामाजिक दबाव समूह के रूप में उभरी काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) भी 2 अक्तूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क के बाद अब 10 अक्तूबर को फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का एलान कर चुकी है।

कुछेक विधानसभा चुनावों को अपवाद मान लें, तो 2014 से ही विपक्ष नरेंद्र मोदी की भाजपा से चुनाव-दर-चुनाव मात खाता आ रहा है। साल 2023 में दो दर्जन विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए 'इंडिया' ब्लॉक में भाजपा द्वारा नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के रूप में सेंध लगाने के बावजूद विपक्ष ने उसे अपने दम पर बहुमत से वंचित कर दिया, मगर उसके बाद चुनावी बाजी फिर हाथ से फिसलती गई। ऐसे में, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर मीडिया-खुलासे के बाद गतबंधन को बड़ा मुद्दा और नई ऊर्जा मिलती नजर आ रही है।



विपक्ष में राहुल गांधी के नेतृत्व की चुनौती देती दिख रहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद, अब खुले मन से राहुल के साथ हैं। बीजू जनता दल इंडिया ब्लॉक के साथ तालमेल बिठाता रहा है। जाहिर है, विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, जिस पर न सिर्फ चुनाव आयोग, बल्कि हर बार उसके बचाव में उतरने वाली भाजपा भी कठघरे में है। विपक्षी सांसदों के मार्च वाले दिन भी चुनाव आयोग मौन ही रहा, पर भाजपा प्रवक्ताओं ने चार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष, खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। आखिर क्यों?

मीडिया-खुलासे के बाद से ही सार्वजनिक कार्यक्रमों से परहेज कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरह मीडिया व विपक्ष से दूरी बनाए हुए हैं, उसे उनके दबाव में होने का संकेत तो माना जा सकता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रतिकूल फैसले या टिप्पणी से पूर्व उनके इस्तीफे की उम्मीद नहीं पैदा होती। इसलिए विपक्ष के समक्ष, वांछित परिणाम निकलने तक संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे के बहाने सत्ता पक्ष पर दबाव बनाए रखने की चुनौती होगी। यह आसान नहीं। हां, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाए या सरकार संभावित सियासी नुकसान का आकलन कर प्रधान की तरह ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा दिलवा दे, तो बात अलग है।

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार, दोनों की मुश्किलें बढ़ाने में दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा की गई आपत्तियों के मीडिया-खुलासे की बड़ी भूमिका है। रही-सही कसर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी ने पूरी कर दी कि फॉर्म-6 में किसी भी तरह के बदलाव को उसने कभी मंजूरी नहीं दी थी। ध्यान रहे, दोनों चुनाव आयुक्तों को आपत्तियां मुख्यतः मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर ही थीं, जिसका फॉर्म-6 महत्वपूर्ण अंग है। मीडिया-खुलासे के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध दायर याचिकाओं के अलावा सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग से जुड़ी कई याचिकाओं की भी सुनवाई कर रहा है।

बहरहाल, चहेते चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का आरोप तो हर सत्तारूढ़ दल पर लगता रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के संदर्भ में मनोहर सिंह गिल और नवीन चावला के उदाहरण ज्यादा पुराने नहीं हैं, पर इससे न चुनाव प्रणाली बेहतर बनती है और न ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अभी जिन आयुक्तों के बीच मतभेद से चुनाव आयोग की साख पर सवालिया निशान लगा है, उन तीनों की नियुक्ति वर्तमान केंद्र सरकार ने ही की है। दो चुनाव आयुक्तों- अशोक लवासा और अरुण गोयल के बीच कार्यकाल में इसीलिए से उठे सवाल भी अभी तक अनुत्तरित हैं। इसलिए वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्तों में गंभीर मतभेद से संदेह और सवालों को बल मिलेगा ही।

यह संभव नहीं कि सरकार इन मतभेदों से अनभिज्ञ रही होगी। इसके बावजूद समय रहते चीजों को न संभाल पाने से भी सवाल उठते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एकतरफा फैसले लिए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया-खुलासे के आधार मात्र पर मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन या उनके फैसले लेने पर रोक लगाने से परहेज किया है, मगर कारण बताओ नोटिस जारी करने से साफ है कि आयोग की कार्यप्रणाली और फैसले समीक्षा के दायरे में हैं।

साफ है, एसआईआर में करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जाने के अलावा फॉर्म-6 भी आयोग की आलोचना का एक बड़ा कारण बना है। फिर भी इस मामले में चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। सीजेपी समेत विपक्षी नेताओं को देश की सर्वोच्च अदालत पर संदेह से बचना चाहिए, तो केंद्र सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं को चुनाव आयोग के बचाव से परहेज बरतना चाहिए, ताकि चौतरफा अविश्वास का विस्तार खतरनाक मोड़ तक न पहुंच जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कामयाब कप्तान के रूप में याद रहेंगी हरमनप्रीत



पूर्णिमा राव | पूर्व मुख्य कोच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम

हर खिलाड़ी अपने खेल-जीवन में ऐसा फैसला लेता है, जिसमें वह खुद से अधिक देश के बारे में सोचता है। हरमनप्रीत कौर का भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला कुछ ऐसा ही है। उन पर अगले विश्व कप के लिए टीम और नेतृत्व को तागत देने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि स्थिति उनके लिए प्रतिकूल थी, बल्कि खिलाड़ी के रूप में वह अब भी टीम का हिस्सा बनी रहेंगी, लेकिन उनसे साहस दिखाने की अपेक्षा की जा रही थी।

वास्तव में, यही हिम्मत हरमनप्रीत की पहचान रही है। वह मौके पर दम-खम दिखाना जानती हैं। 20 जुलाई, 2017 का मुकाबला याद कीजिए। वह विश्व कप का सेमीफाइनल था और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी। हरमनप्रीत निर्भीक होकर खेलती रहीं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजती रहीं। 115 गेंदों पर नाबाद 171 रनों की वह पारी न सिर्फ उनके करियर की एक मुकाम दे गई, बल्कि भारत में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता व गंभीरता को बढ़ाने में भी कारगर साबित हुई। जिस तरह 1983 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय क्रिकेट को एक यादगार ऊंचाई दी थी, ठीक उसी तरह का प्रदर्शन हरमनप्रीत ने 2017 में किया था।

हरमनप्रीत कौर पर अब एक वरिष्ठ खिलाड़ी के तौर पर अगले विश्व कप के लिए टीम और नेतृत्व को ताकत देने की महती जिम्मेदारी है।

आलोचक यह कहते हैं कि वह तकनीकी तौर पर दक्ष नहीं हैं। वाकई, स्मृति मंधाना जैसी तकनीक उनके पास नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, और यह वह खूबी है, जो खेल की तस्वीर बदल सकती है। वीरेंद्र सहवाग के पास भी तकनीक का अभाव था, लेकिन उनका दिल बड़ा था, जिस कारण वह भारतीय क्रिकेट का रूप-रंग बदलने में सफल रहे। उनके समय से ही टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में भी पहले ही दिन 300-400 रन बनाने लगी। महिला क्रिकेट में भी ऐसा ही बदलाव हरमनप्रीत के कारण संभव हो सका। इस तरह की क्षमता हर खिलाड़ी के पास नहीं होती।

मैंने बतौर कोच उनको करीब से देखा है। 2014 में जब मुझे महिला टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया था, तब वह एक ऑलराउंडर के रूप में खेल रही थीं। वह बहुत छोटी थीं, लेकिन उनकी 2009 की वह पारी मेरे जेहन में थी, जब नॉर्थ सिडनी ओवल स्टेडियम में विश्व कप के सुपर सिक्स मैच में उन्होंने ऐतिहासिक छक्का मारा था। उस समय मैं मैनेजर के रूप में भारतीय टीम के साथ जुड़ी हुई थी। इससे मुझे पता लगा कि क्रिकेट को लेकर उनमें जबर्दस्त भूख है। साल 2017 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालीफायर के फाइनल मुकाबले में ही आखिर ओवर में छक्का मारकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीतने का दम-खम उनके सिवा कोई दूसरी खिलाड़ी नहीं दिखा सकती थी, वह भी अंतिम विकेट के रूप में और चौथी गेंद पर। सीखने का जज्बा उनके अंदर खूब है, इसीलिए शुरुआत में मिडविकेट पर ज्यादा खेलने वाली हरमनप्रीत बाद में स्वेवायर कट लगाने लगीं और गेंदबाज के ऊपर से भी खेलने लगीं। खुद को इस लायक बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की है। उनकी यह खूबी सिर्फ क्रिकेटर को ही नहीं, हर विधा के खिलाड़ी को सीखनी चाहिए।

अब जब वह कप्तान नहीं हैं और स्मृति मंधाना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो टीम के लिए स्थिति अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी। एशियाई खेल अभी-अभी खत्म हुए हैं और अब नजरें ओलंपिक व विश्व कप पर हैं। ये हल्के मुकाबले नहीं होते। नए कप्तान को इस बावत रणनीति बनानी होगी। हालांकि, उनके लिए राहें बहुत कठिन नहीं होंगी, क्योंकि जीत का फॉर्मूला टीम को पता है। वह जानती है कि कैसे खेलना है और कैसे जीत का स्वाद चखना है।

स्मृति की खासियत यही है कि वह मौचों लेना जानती हैं। फ्रंट पर वह खेलती हैं, जिससे बाकी खिलाड़ी सबक ले सकते हैं। फिर तकनीक के मामले में भी वह तुलनात्मक रूप से अच्छी हैं। उन्हें अब सबको साथ लेकर चलना होगा, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी जैसी होती है। हालांकि, इस दबाव में उनको अपना नैसर्गिक खेल भूलना नहीं चाहिए। हरमनप्रीत पर कप्तान होने का दबाव कभी-कभी दिख जाता था। उम्मीद है, स्मृति इस दबाव को झटकने में सफल साबित होंगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सम्मान देना आना चाहिए

सम्मान देने का भाव बच्चों में शुरू से डालना चाहिए। इसे ही अंग्रेजी में 'प्रोटोकॉल' कहते हैं - क्या किसकी मर्यादा है। आज मैं देखता हूं- पिताजी खड़े रहते हैं और बेटा बैठ जाता है। बतलाइए, कहीं ऐसा होता है क्या कि पुलिस का बड़ा अधिकारी खड़ा हो और छोटा अधिकारी बैठ जाए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कोर्ट में भी नहीं होता। सेना में नहीं होता, बड़े संगठन में ऐसा होगा क्या?

बड़ा जब तक खड़ा है, तब तक छोटा भी खड़ा रहेगा। बड़ा यदि बैठा है, तो छोटा भी बैठ सकता है, किंतु पूछकर बैठेगा। आज सम्मान देने का भाव बहुत ही कम हो रहा है, प्रोटोकॉल लोग समझ ही नहीं रहे हैं।

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः।

चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि किसी को भक्त बनना है, भगवान का भजन करना है, तो मान की इच्छा छोड़ें और मान देने की इच्छा से जुड़ें। हमें दूसरों को मान देना है। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी जय-जयकार करें। मान देने की परंपरा, मर्यादा निभाने की परंपरा बच्चों को शुरू से ही बतलानी चाहिए। जब पिता जी आएं, तो आप खड़े हो जाओ, उन्हें प्रणाम करो, ये शुरू से सिखाना होगा। प्रणाम बहुत बड़ी साधना है। प्रणाम समाज का बहुत बड़ा जोड़ने वाला द्रव है। सम्मान ही आदमी को प्रोटेक्ट करता है, वह भी बतलाना है। जो मर्यादाएं सेना में हैं, जो मर्यादाएं दूसरे संस्थानों में हैं, उसके साथ ही हमें संतत्व की शिक्षा भी देनी चाहिए। जो हमें आदर देता है, मर्यादा के साथ सारे व्यवहार करता है, वही तो संत है। शुरू से ही शिक्षा दो और शिक्षा की जो विवेचना है, वह ऐसे दी जाए कि प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए। रामजी जब सुबह उठते थे, तब सभी बड़ों, गुरुजनों को प्रणाम करते थे।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

जब पिता जी आएं, तो आप खड़े हो जाओ, उन्हें प्रणाम करो, ये शुरू से सिखाना होगा। प्रणाम बहुत बड़ी साधना है। प्रणाम समाज का बहुत बड़ा जोड़ने वाला द्रव है।

नहीं है। यह सिखाना घर के विद्यालय का कार्य है।

अभी तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में बच्चे बैठे रहते हैं और अध्यापक खड़े रहकर पढ़ाते हैं। बतलाइए, अब क्या शिक्षा होगी? अब कक्षा में हाथ नहीं जोड़ना है, बस अपनी जगह खड़े हो जाइए और फिर बैठ जाइए, बेचारा अध्यापक खड़ा रहेगा। उसे देर तक खड़ा रहना है। ऐसा सेना में होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। जितनी बार बड़ा अधिकारी सामने आता है, उतनी बार छोटा अधिकारी सैल्यूट मारता है। सभी लोगों को बच्चों को सैनिक बनाना है। जो सेना में प्रोटोकॉल है, केवल वही नहीं, जो संतों में प्रोटोकॉल है, वह भी बताना है। जो मर्यादाएं सेना में हैं, जो मर्यादाएं दूसरे संस्थानों में हैं, उसके साथ ही हमें संतत्व की शिक्षा भी देनी चाहिए। जो हमें आदर देता है, मर्यादा के साथ सारे व्यवहार करता है, वही तो संत है। शुरू से ही शिक्षा दो और शिक्षा की जो विवेचना है, वह ऐसे दी जाए कि प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए। रामजी जब सुबह उठते थे, तब सभी बड़ों, गुरुजनों को प्रणाम करते थे।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

पोप लियो XIV | ईसाई धर्म गुरु



सच्चा प्यार ईश्वर का तोहफा है। हम इसे खुद पैदा नहीं कर सकते। इंसानी प्यार में अक्सर स्वार्थ की भावना होती है, जबकि ईश्वर का प्रेम निःस्वार्थ होता है। उस प्रेम में सभी प्रकार के गुण होते हैं।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 08 अक्तूबर, 1951

हमारा पौण्ड पावना

भारत स्टर्लिंग क्षेत्र से संबंधित है। वह अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूर्ति के लिए स्टर्लिंग क्षेत्र पर निर्भर करता है। भारत विदेशी व्यापार द्वारा जो धन-राशि कमाता है, वह स्टर्लिंग क्षेत्र के कोषाध्यक्ष ब्रिटेन के पास जमा हो जाती है। यह धन-राशि ही पौण्ड पावना के नाम से जानी जाती है। युद्धकाल में पौण्ड पावना की हमारी राशि काफी बढ़ गयी थी, युद्धोत्तर काल में इसका खासा भाग हम खर्च कर चुके हैं। रुपये के अवमूल्यन के बाद भारत के विदेशी व्यापार की अनुकूल स्थिति रही और उसके फलस्वरूप हमारी पौण्ड पावना की रकम में पुनः वृद्धि हुई है। स्टर्लिंग क्षेत्र के देश यह आशा रखते हैं कि पौण्ड पावना की रकम में से उन्हें सुलभ अथवा दुर्लभ मुद्रा बिना किसी कटिनाई के मिलती रहनी चाहिए किन्तु स्टर्लिंग क्षेत्र के स्वर्ण और डालर के संचित कोष में सितम्बर को समाप्त होनेवाली तिमाही में भारी कमी हुई है। ब्रिटेन के अर्थ मंत्री ने प्रकट किया है कि यह कमी 63 करोड़ 80 लाख डालर की हुई है। इस कमी के लिए ब्रिटेन ही सबसे अधिक उत्तरदायी है। ब्रिटेन के कारण 59 करोड़ 80 लाख डालर की कमी हुई है और शेष 4 करोड़ डालर की कमी के लिए स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य सदस्य राष्ट्र जिम्मेदार हैं। ब्रिटेन के लिए तो यह कमी सबसे अधिक चिन्तनीय है ही, स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों में भी उसके कारण चिन्ता पैदा हो गयी है। ब्रिटेन के अर्थमंत्री ने यह सफाई दी है कि अस्थायी और मौसमी कारणों से यह कमी हुई है किन्तु जानकारों की राय में ब्रिटेन राश्त्रीकरण पर अपनी शक्ति से अधिक व्यय कर रहा है और इसी कारण उसके सामने यह संकट उत्पन्न हुआ है।

इस स्थिति में भारत के लिए यह विचारणीय हो जाता है कि क्या उसके लिए स्टर्लिंग क्षेत्र के साथ अपने भाग्य को बांधे रखना उचित होगा? ब्रिटेन की राजनीति और अर्थनीति के उतार-चढ़ाव के साथ भारत कब तक अपनी अर्थनीति में परिवर्तन करता रहेगा। स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देश ब्रिटेन के शस्त्रीकरण कार्यक्रम के बोझ को अपने साधनों द्वारा कब तक हलका करते रह सकते हैं। भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री डा. जानमथाई ने तो कहा भी है कि भारत को स्टर्लिंग क्षेत्र से अपने को अलग कर लेने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

स्त्रियों की सुरक्षा पर कोर्ट का रुख सही

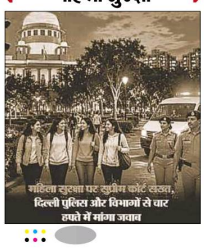
महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी कसौटी होती है। दिन हो या रात, यदि महिलाएं सड़क पर चलने, यात्रा करने या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे सामाजिक तंत्र के सामने गंभीर चुनौती है। दिल्ली और उसके आस-पास महिलाओं तथा बच्चियों के खिलाफ हाल में सामने आई यौन हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इसी व्यापक चिंता को सामने लाती है। गत 5 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने साफ संकेत दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपराध होने के बाद कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध को होने से पहले रोकने की प्रभावी व्यवस्था तैयार करना भी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है, जिसमें राजधानी की कोई महिला रात के समय भी खुद को असुरक्षित महसूस न करे। न्यायालय ने यह सवाल केवल सुनसान सड़कों या निर्जन स्थानों के संदर्भ में नहीं उठाया, बल्कि सार्वजनिक परिवहन, भूमिगत रेलों, सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों तक इसे व्यापक बनाने को कहा है। अदालत की चिंता का मूल आधार यह है कि महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही को समय और स्थान के भय से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई महिला रात 10-11 बजे अपने काम, शिक्षा या किसी अन्य आवश्यक कार्य से घर लौट रही है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन और पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय ने अपराध की रोकथाम को अपनी चिंता के केंद्र में रखा है। अमूमन किसी अपराध के बाद पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना, आरोपी की गिरफ्तारी और जांच पूरी करना आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले का चरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी क्षेत्र को पहले से संवेदनशील माना जाता है, तो यदि वहां पर्याप्त रोशनी नहीं है, वहां की निगरानी व्यवस्था कमजोर है, पुलिस की नियमित गश्त नहीं होती या सुनसान स्थान अपराधियों के लिए सुलभ अवसर पैदा करते हैं, तो इन कमियों को दूर करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। न्यायालय का यह निर्देश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान केवल अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि अपराध संबंधी आंकड़ों, स्थानीय सूचनाओं, पहले प्राप्त शिकायतों और वहां हुई पिछली घटनाओं के आधार पर की जाए।

महेन्द्र तिवारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
महिला सुरक्षा



दिल्ली किसी राज्य से अधिक सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए जो निर्देश दिए हैं, वे बिल्कुल उचित और सतर्कता बढ़ाने वाले है। हालांकि, देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकों का व्यवहार देखें, तो पता चलता है कि यहां के लोग शहर में रात-दिन बड़े निर्भीक अंदाज में जीवन-यापन करते हैं। निस्संदेह, समय-कुसमय कुछ अवांछित घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन केवल इनके आधार पर दिल्ली को पूरी तरह असुरक्षित और यहां के नागरिकों को डरा-सहमा हुआ नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली की अनूठी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को रेखांकित करने के लिए यह कहा जाता है कि 'दिल्ली देश के किसी राज्य से अधिक निर्भीक है' । एक केंद्र शासित प्रदेश और देश की राजधानी होने के नाते, इसका चरित्र भारत के अन्य राज्यों से काफी अलग है। यहां के नागरिक सीधे केंद्र सरकार की नीतियों को करीब से देखते हैं और उन पर अपनी राय रखते हैं। अन्ना हजारे का 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन हो, निर्भया कांड के बाद हुआ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन हो या हाल के वर्षों में हुए किसानों के आंदोलन, दिल्ली हमेशा से बड़े बदलावों और निर्भीक आवाजों का केंद्र रही है। दिल्ली में भारत के हर राज्य, संस्कृति और भाषा के लोग रहते हैं। इस विविधता के कारण यहां के लोगों में एक खास तरह का आत्मविश्वास दिखता है। दिल्ली की संस्कृति और यहां की बोलचाल में एक खास तरह की बेबाकी और जीवंतता मिलती है, जिसे अक्सर 'निर्भीक या निडर' रवैये के रूप में रेखांकित किया जाता है।

इनके अलावा, दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर कई सुधार हालिया दिनों, खासकर निर्भया कांड के बाद हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी पर हुआ है। पुलिस की सतर्कता बढ़ी है, हालांकि इसमें अभी कई स्तरों पर सुधार और बेहतरी की दरकार है। सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था सुधरी है और सड़कों पर हर जगह रात में प्रकाश की व्यवस्था दिखती है। सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शलों का तैनाती एक अभूतपूर्व कदम है, जिससे महिलाएं निडर होकर बसों में सफर कर रही हैं। यातायात के दौरान सुरक्षा की दिशा में 'पिंक बस' और 'पिंक आंटी' सेवा ने भी कई कदम आगे बढ़ाए हैं। इन सुधारों को और बेहतर करने की दिशा में दिल्ली पुलिस को कार्य करना होगा। जरूरत है कि पुलिस तंत्र निर्देश के अनुसार, जांच तथा निगरानी कैमरों की स्थिति का परीक्षण कर उसे ठीक करे, तो व्यवस्था और चाक-चौबंद होगी।

गुड्डी तिवारी, गृहिणी

कृषि व्यवसाय में कैसे बनाएं करियर

कृषि क्षेत्र पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर कारोबार का रूप ले रहा है। खेती में ड्रोन और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। विश्व स्तर पर फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री एवं सप्लाई चेन जैसी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। एग्रीबिजनेस में करियर और कारोबार के विकल्पों का लगातार विस्तार हो रहा है। इस क्षेत्र में कैसे बढ़ें आगे, बता रहे हैं सोनिक सौरभ





उद्यमिता-2

देश में कृषि और इससे जुड़े व्यवसाय का बाजार 2034 तक 252 खरब रुपये पहुंचने का अनुमान है। 9.68 फीसदी की सालाना वृद्धि वाला यह बाजार कृषि से संबंधित बिजनेस की बढ़ती संभावनाएं दिखाता है। साल 2010-11 में संगठित एग्रीबिजनेस, यानी इनपुट सप्लाई, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन आदि का बाजार बेहद शुरुआती चरणों में था। वर्तमान में यह आधुनिक उद्योग बन चुका है। वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का आकार 114.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। बढ़ती शहरी आबादी, स्वास्थ्य जागरूकता और ताजे एवं तैयार खाद्य उत्पादों की मांग से खेती कारोबार से जुड़ रही है।

तकनीक से जुड़े कृषि कारोबार

युवा उद्यमी उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, वित्त, तकनीक और बिक्री तक अलग-अलग क्षेत्रों में कारोबार शुरू कर सकते हैं।

■ **एग्री टेक :** भारत में एग्री-टेक सेक्टर 10-14 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। फसल पर छिड़काव, खेतों की निगरानी व मैपिंग में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्रति एकड़ या तय शुल्क पर इन सेवाओं के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ड्रोन से जुड़े नियमों एवं अधिकृत प्रशिक्षण की जानकारी लेना जरूरी है। **digitalsky.dgca.gov.in** और **agricoop.nic.in** से सहायता मिलेगी।

■ **फूड प्रोसेसिंग व पैकेजिंग:** सरकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सूक्ष्म उद्योगों में प्रोसेसिंग के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जा रही है, जिससे इसमें ग्रामीण भागीदारी तेजी से संगठित हो रही है। खाद्य तेल, पिसे मसाले, डेयरी उत्पाद, मिलेट्स यानी श्री अन्न और उससे बने स्नैक्स और ऑर्गेनिक गुड़ की मांग सबसे ज्यादा है। छोटे स्तर पर स्थानीय उत्पादों से शुरुआत कर ऑनलाइन और रिटेल बाजार तक पहुंच बनाई जा सकती है।

■ **डेयरी बिजनेस :** भारतीय डेयरी बाजार 2024 में 18.98 लाख करोड़ रुपये का था, जो करीब दस साल पहले 4-5 लाख करोड़ रुपये तक ही था। प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों में लिक्विड मिल्क सबसे बड़ा वर्ग है। हालांकि, सिर्फ दूध ही नहीं, पनीर, बटर, चीज, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, दही और प्रोबायोटिक से जुड़े उत्पादों की भी मांग बढ़ी है।

■ **सप्लाई चेन व लॉजिस्टिक्स:** खेत से बाजार और प्रोसेसिंग यूनिट तक कृषि उत्पादों की सुरक्षित पहुंच के लिए कोल्ड-चेन, रेफ्रिजरेटेड वाहन, वेयरहाउसिंग व इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी सेवाओं की जरूरत है। फल, सब्जियों, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की समय पर डिलीवरी इस क्षेत्र में स्टार्टअप के मौके देती है।

■ **ऑर्गेनिक फार्मिंग :** 2014-15 में भारत में पंजीकृत जैविक कृषि कर रहे किसानों की संख्या 5 से 6 लाख थी, जो 2024-25 में 23.6 लाख से अधिक हो गई। जैविक व प्राकृतिक खेती के उत्पाद, ब्रांडिंग और बिक्री कारोबार के अवसर दे रहे हैं। निर्यात के लिए जैविक सोयाबीन, तिल, चाय, औषधीय पौधे, चावल (बासमती), मसाले, और दालों की खास मांग है। वहीं हर्बल फार्मिंग भी अच्छी आय दे रही है।

57
लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है 2033 तक भारत का डेयरी बाजार। 2024 में 18.98 लाख करोड़ रुपये का था।

सरकारी योजनाओं से मदद

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कृषि, डेयरी व पोल्ट्री जैसे छोटे कारोबार के लिए कर्ज मिलता है। पीएमएफएमई से खाद्य कारोबार और एआईएफ से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी कृषि सुविधाओं के लिए वित्तीय मदद मिलती है। इन वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं- **mudra.org.in,pmfme.mofpi.gov.in, agriinfra.dac.gov.in**

पहले कुछ तैयारी जरूरी

कारोबार शुरू करने से पहले तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव जरूरी है। उत्पादन लागत, गुणवत्ता, पैकेजिंग, हिसाब-किताब और बिक्री की समझ के साथ किसी प्रोसेसिंग यूनिट या सप्लाई चेन कंपनी में काम करने से जमीनी अनुभव मिलता है।

कौन-सी पढ़ाई आएगी काम

12वीं के बाद बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। स्नातकों के लिए एमबीए एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट उपयोगी है। ड्रोन पायलटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सप्लाई चेन, हाइड्रोपोनिक्स एवं फूड सेफ्टी से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स भी काम आएंगे।

विशेषज्ञ की राय

कृषि उद्योग भविष्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण मिलेट व हर्बल जैसे पारंपरिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले फूड सेफ्टी और स्वास्थ्य मानकों के साथ कच्चे माल की उपलब्धता और स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने की लागत का आकलन जरूरी है। उत्पाद बाजार में उतारने से पहले लैब टेस्ट, पोषण संबंधी सही जानकारी और शाकाहारी या मांसाहारी होने का स्पष्ट संकेत देना भी जरूरी है।

-अभिषेक कुमार, (एीएम कृषि रत्न सम्मान प्राप्त) संस्थापक, बीजम नर्सरी प्रा. लि.

रोजगार चाहने वालों के लिए

एग्री-कंपनियों में नौकरी से शुरुआत कर सकते हैं। 10वीं के बाद आईटीआई या तकनीकी प्रशिक्षण लेकर एग्री-टेक इंजीनियर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सप्लाई चेन मैनेजर, प्रोक्योरमेंट एजीक्यूटिव और एग्रीकल्चरल लोन ऑफिसर जैसे पदों पर काम किया जा सकता है। अनुभव के साथ बेहतर पद और वेतन के अवसर बढ़ते हैं। नौकरी के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रिक्तियां देखी जा सकती हैं।

चुनौतियां जानें

शुरुआती 3 से 5 साल एग्रीबिजनेस में धैर्य से आगे बढ़ते रहें। पर्याप्त पूंजी, छोटी शुरुआत और ग्राहकों के फीडबैक के साथ यह दौर पार करने वाले कारोबार के लंबे समय तक टिकने और बढ़ने की संभावना अधिक होती है। मौसम एग्रीटेक, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सॉइल टेस्टिंग और आधुनिक बिजनेस मैनेजमेंट के तरीकों से अपडेट रहें। कच्चे माल की गुणवत्ता से समझौता न करें। लाइसेंसिंग, सब्सिडी और एग्री-सर्टिफिकेशन में समय लग सकता है।

प्रमुख संस्थान

■ विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थान ■ राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएम, जयपुर) ■ वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पुणे, ■ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ■ कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर ■ लुधियाना समेत विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय। ■ स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और रिकल इंडिया डिजिटल से भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है।

तकनीकी पढ़ाई की आसान राह पॉलिटेक्निक

एक्सपर्ट टिप्स



डॉ संजीव कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

■ पॉलिटेक्निक में कौन-सा ट्रेड सबसे अच्छा है? कोर्स कितने साल में पूरा होता है? इसके लिए कौन-से संस्थान बेहतर हैं और इसके बाद नौकरी के क्या अवसर हैं?

- अभिषेक सिंह

पॉलिटेक्निक शिक्षा 10वीं के बाद तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण का विकल्प देती है। यह तकनीकी करियर व आगे की पढ़ाई के लिए व्यावहारिक व अपेक्षाकृत तेज रास्ता है। आमतौर पर यह तीन साल का कोर्स होता है। 12वीं (विज्ञान) या आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में सीधे प्रवेश ले सकते हैं।

पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस/ आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रमुख विषय हैं। कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर में रुचि रखने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस या आईटी चुन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर और ऑटोमेशन, जबकि मैकेनिकल व सिविल में ऑटोमोबाइल, मेन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अवसर मिलते हैं।

संस्थान चुनते समय लैब, फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देखें। दिल्ली-एनसीआर में पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों पर भी विचार किया जा सकता है।

आवेदन से पहले पाठ्यक्रम, ट्रेड और प्रवेश प्रक्रिया आदि से अपडेट रहें। डिप्लोमा के बाद छात्र अपने विषय के अनुसार टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, सीएडी-डिजाइन असिस्टेंट, मेंटेनेंस और तकनीकी सहायक जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। निजी कंपनियों, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी विभागों और पीएसयू में अवसर मिल सकते हैं। प्रवेश नियमों के अनुसार लेटरल एंट्री से बीटेक या बीई के दूसरे वर्ष में दाखिला ले सकते हैं।



■ मैंने बीटेक (मेकैनिकल) किया है। फिलहाल एक निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हूं। मैं एमबीए करना चाहता हूं, लेकिन नौकरी के साथ यह आसान नहीं है और डिस्टेंस मोड में एमबीए की डिग्री को ज्यादा महत्व नहीं मिलता। नौकरी छोड़े बिना एमबीए की डिग्री कैसे हासिल करूं?

- प्रियम अग्रवाल

पूर्णकालिक एमबीए करने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बिजनेस स्कूल से पार्ट-टाइम या वीकेंड एमबीए किया जा सकता है। ये कोर्स नौकरीपेशा लोगों के लिए होते हैं और कक्षाएं आमतौर पर सप्ताहांत या ऑफिस के बाद होती हैं। दाखिले से पहले संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक, इंडस्ट्री जुड़ाव, एलुमनी नेटवर्क और करियर अवसर जांचें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बैंकिंग अनुभव को देखते हुए फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस एनालिटिक्स या जनरल मैनेजमेंट जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं। विशेषज्ञता लोकप्रियता के बजाय अपने करियर लक्ष्य के अनुसार चुनें।

एक और विकल्प नौकरीपेशा लोगों के लिए एजीक्यूटिव एमबीए या पीजीडीएम है। ये कोर्स खासकर अनुभवी पेशेवरों के लिए उपयोगी होते हैं। इनमें दूसरे पेशेवरों से सीखने, नेटवर्क बनाने व इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलता है। भविष्य में बैंकिंग, बिक्री, रिलेशनशिप मैनेजमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में वरिष्ठ पद हासिल करना लक्ष्य है, तो प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीए मौजूदा अनुभव को मजबूत कर सकता है। बीटेक की तकनीकी शिक्षा, बैंकिंग अनुभव और मैनेजमेंट की पढ़ाई करियर के नए अवसर खोल सकता है। मान्यता प्राप्त वीकेंड, पार्ट-टाइम या एजीक्यूटिव प्रोग्राम चुन सकते हैं।

(www.sanjibacharya.com)

हिन्दुस्तान क्विज-26

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. हिन्दुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, वे कौन थे?
2. किस हिन्दुस्तानी ने पहली बार साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था?
3. असम की सत्रिया नृत्य शैली की स्थापना का श्रेय किसको जाता है?
4. खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली हिन्दुस्तानी महिला खिलाड़ी कौन थीं?
5. हिन्दुस्तान के किस शासक को 'लाखबख्श' की उपाधि दी गयी थी?
6. हिन्दुस्तान में पहली एटीएम मशीन किस बैंक द्वारा लगाई गई थी?
7. जिस प्रकार दिल्ली का 'राजघाट' महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, उसी प्रकार पटना का 'महाप्रयाण घाट' किस महापुरुष से संबंधित है?
8. हिन्दुस्तान की महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थीं?
9. कलकत्ता नगर निगम के प्रथम मेयर बनने का गौरव किस प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी को प्राप्त हुआ था?
10. रितेश अग्रवाल द्वारा किस मशहूर हिन्दुस्तानी कंपनी की स्थापना की गई?



स्तर : 1. मीनाक्षी दीक्षित 2. अरुंधती रॉय 3. शरत चंद्र 4. अंजलि मोहन 5. कृष्णदेव राय 6. एसबीआई बैंक 7. डी. राजेंद्र प्रसाद 8. मिताली राज 9. कृष्णा हठीसिंह 10. अमृता शेरगिल

जॉब/करियर

■ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद रिक्त हैं। विस्तृत जानकारी कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कुल पद : 250
अंतिम तिथि : 28 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। इस वेबसाइट **sci.gov.in** पर लॉगइन करें।

■ दिल्ली जिला न्यायालयों की ओर से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पर्सनल असिस्टेंट, पियोन सहित अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए कम्बाइन्ड इग्जामिनेशन 2026 का आयोजन किया जाएगा।
कुल पद : 641
अंतिम तिथि : 04 नवंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **dsssb.delhi.gov.in**



■ बैंक ऑफ बड़ौदा में वेल्थ एग्जीक्यूटिव समेत अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
कुल पद : 1100
अंतिम तिथि : 16 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट देखें- **bankofbaroda.bank.in**

■ जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
कुल पद : 252
अंतिम तिथि : 13 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट **upanganwadibharti.in**

■ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कुल पद : 231
अंतिम तिथि : 23 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **btsc.bihar.gov.in**

■ फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) में फार्मासिस्ट, मैनेजर समेत अन्य पदों पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आवेदन डाक के माध्यम से करना होगा।
कुल पद : 178
अंतिम तिथि : 15 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट- **pmbi.co.in**

■ उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा सहायक शिक्षक शहरी एवं संबद्ध प्राइमरी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
कुल पद : 12405
अंतिम तिथि : 15 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है- **upessc.up.gov.in**

■ रेलवे भर्ती बोर्ड में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट समेत अन्य पैरा-मेडिकल पदों पर आवेदन का अवसर है। आवेदन प्रक्रिया जारी है।
कुल पद : 590
अंतिम तिथि : 14 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है- **rrbapply.gov.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayirahheincareer@gmail.com**

रोजनामचा



पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। लाभ में वृद्धि होगी।

वृष : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं।

कर्क : मन परेशान रहेगा। व्यर्थ के क्रोध से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा, परंतु बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

कन्या : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार के लिए माता-पिता से धन मिल सकता है। परिवार में धार्मिक संगीत के कार्यक्रम हो सकते हैं।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। सचेत रहें। कारोबार में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आय में कमी और खर्च में अधिकता हो सकती है। भागदौड़ भी बढ़ेगी।

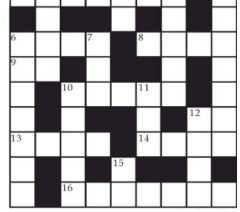
धनु : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे। वरुण उपहार में मिल सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। मित्रों और परिवार का साथ मिलेगा। जीवनसाथी और पिता की सेहत का ध्यान रखें।

मीन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।

वर्गपहेली : 8475



बाएं से दाएं
1. अलग करना; त्यागना; बाहर निकालना; कोई संबंध न रखना; बिरादरी से बाहर करना (4,3)
6. उंगलियों से रगड़ना; जोर से दबाना; जोर से मलना; रौंदना (4)
8. अनुचित कार्य को रोकने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न; निवंत्रण; रुकावट; रोकटोक (4)
9. उदास; झुका हुआ; प्रणाम करता हुआ; विनीत; कोणयुक्त; टेढ़ा; वक्र (2)
10. काम जारी रहना; कार्य सिद्ध होना; जैसे-तैसे काम होना; निर्वाह होना; पर्याप्त होना (2,3)
12. जलाशय; तालाब; सिर (2)
13. शक्ति; सामर्थ्य; साहस (4)
14. भेंट; उपहार (4)
16. पंजी में लिखवाना; नामजद करना; नामित करना; मनोनीत करना (4,3)

ऊपर से नीचे
2. देख रेख में रखा जाना; पूछताछ के लिए रोका जाना; अभिरक्षा; निगरानी; हवालात (4)
3. ऊंचाई; लंबाई; डील-डौल; हैसियत (2)
4. ईश्वर में विश्वास न होना; धर्महीन होना (3,2)
5. खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना; ढूंढ निकालना; बाहर लाना (4,3)
6. इरादा पक्का करना; ठान लेना (2,2,3)
7. असफल; विफल (3)
10. स्वार्थ सिद्ध होना; काम पूरा होना (2,3)
11. खेती बाड़ी पर लगने वाला कर; मकानों का आपस में मिला हुआ भाग (3)
12. आप्लावित; तरबतर; नहाया हुआ (4)
15. कोण; धार; पैना किनारा; शिखर; कोना (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्गपहेली : 8474



सुडोकू : 8429

*मध्यम

		6				9		
	7			4			8	
1	2						5	6
		9	4		2	3		
			3		8			
		8	7		5	2		
8	1						9	4
	6			7			2	
		2				6		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8428

2	9	5	6	1	8	3	7	4
1	8	6	4	7	3	9	5	2
3	7	4	9	5	2	8	1	6
4	2	9	5	3	1	7	6	8
7	6	3	8	4	9	5	2	1
8	5	1	2	6	7	4	9	3
5	1	8	7	2	4	6	3	9
9	3	7	1	8	6	2	4	5
6	4	2	3	9	5	1	8	7

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषुकांत गोस्वामी

08 अक्तूबर, गुरुवार, **शक संवत्:** 16, आश्विन (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग:** 22, आश्विन मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम:** 26, रबि-उल्सानी, 1448, **विक्रमी संवत्:** आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि रात्रि 10.17 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी रात्रि 09.21 मिनट तक पश्चात, शुक्ल योग रात्रि 12.59 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग, चन्द्रमा सिंह राशि में रात्रि 03.18 मिनट तक उपरांत कन्या राशि।
सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत। मास शिवरात्रि व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

घर में जिन्दगी बहुत सामान्य बीत रही है, तो उन्नति के लिए क्या करें-

■ घर में हो सकता है कि कुछ चीजें वास्तु के अनुसार नहीं हों। जैसे घर पूर्व एवं दक्षिण दो दिशाओं के मार्ग वाला हो। इसमें दक्षिणी भाग नीचा हो और उसमें मुख्य द्वार भी बना हो। अगर मुख्य सड़क दक्षिण की ओर ही है एवं बाकी घर ऊंचा है, तो इस कारण उत्तर दिशा पूरी ढंकी एवं भारी हो जाएगी।

■ पूर्व दिशा में एक और द्वार खोल रखा है, जो सीढ़ियों का रास्ता है, परंतु वह बहुत छोटा है। ऐसे में उस द्वार को बड़ा कर लेना चाहिए। दक्षिण भाग को वास्तु विधि के अनुसार अलग कर दें। उत्तर दिशा की दीवारों का रंग हल्का नीला करवा दें।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

परीक्षार्थींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम

'काळ आला; वेळही आली!' हा अग्रलेख (७ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आज भ्रष्ट व्यवस्थेने पूर्णपणे पोखरलेला आहे. सर्वसामान्य परीक्षार्थींची एवढीच अपेक्षा आहे की शासनाने ही भ्रष्ट व्यवस्था बरखास्त करून पारदर्शक प्रणाली प्रस्थापित करावी. अध्यक्षाच्या राजीनाम्याने ही भ्रष्ट व्यवस्था लगेच सुधारेल अशी अपेक्षा नाही, पण किमान यापुढे तरी त्या पदाचा भार सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला अतिशय काळजीपूर्क काम करण्याचे भान राहील.

औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटला त्याची चौकशी कुठवर आली, प्रश्नपत्रिका किती मुलांना कोणत्या पद्धतीने, कोणी कोणी पोहोचवली, याची माहिती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी आणखी कोणत्या परीक्षांचे पेपर फोडले आहेत का, याचीही पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे. चौकशी अहवाल सर्वांसाठी उपलब्ध असले पाहिजेत. अपंगत्वाच्या किंवा क्रीडा कामगिरीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी झाली पाहिजे. आयोगाने परीक्षार्थींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. अशा प्रकारे जबाबदाऱ्या एकमेकांवर ढकलून नेमके कोण कोणाला वाचवत आहे? या साऱ्यात विद्यार्थ्यांचा जो वेळ, ऊर्जा, पैसा खर्च झाला त्याची भरपाई केली जाऊ शकते का?

■ **पूजा शिंदे,** अकलूज (सोलापूर)

मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर

'काळ आला; वेळही आली!' हा अग्रलेख (७ सप्टेंबर) वाचला. मुळात यापूर्वीही राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झालेले आहेत. त्यांचा तपास करण्यासाठी किती तरी वेळा समित्या नेमल्या गेल्या. समित्यांचे अहवाल आले. त्यानंतर दोषींविरोधात काय कारवाया झाल्या, हे सारेच जाणतात. दोषींविरोधात खरोखरच कारवाई करायची असेल, तर ती तत्परतेने केली जाते. आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी भले मोठे विद्यार्थी आंदोलन सध्या पुण्यात सुरू आहे. अशा स्थिती मुख्यमंत्री अध्यक्षांविरुद्ध चौकशी समिती नेमून काय साध्य करणार आहेत? हा दिखाऊपणा कशासाठी? हे तर मी मारल्यासारखे करतो आणि तू रडल्यासारखे कर म्हणण्यासारखेच आहे.

■ **प्रा. सचिन जाधव,** बदलापूर (ठाणे)

कनिष्ठांचा बळी घेऊन काय साधणार?

'काळ आला; वेळही आली' हे संपादकीय (७ ऑक्टोबर) वाचले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नामे यंत्रणेतील गोंधळाविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या प्रकरणात भीमनवार यांचे कनिष्ठ सचिव हरपाळकर यांची उचलबांगडी करण्यात आली, मात्र आयोगाचे प्रमुख भीमनवार यांना अभय देण्यात आल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका पटणारी नाही. कनिष्ठांस बळीचा बकरा करून काय उपयोग. हे केवळ कारवाईचा सोपस्कार पार पाडण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खरोखरच लोकसेवा आयोगात आमूलाग्र बदल करण्याची इच्छा असेल, तर त्यांनी चौकशी समिती वगैरे नेमत न बसता थेट मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून आयोगाच्या प्रमुखास पदावरून दूर करण्याचा ठराव मंजूर करावा आणि तो राज्यपालांकडे स्वीकृतीसाठी पाठवावा, पण त्यासाठीची अपरिहार्य अट म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. आपले ते बाळ आणि इतरांचे ते कार्टे अशी भूमिका अयोग्यच.

■ **अरविंद बेलवलकर,** अंधेरी (मुंबई)

तांत्रिक नव्हे, नैतिक आधार घ्या

'काळ आला; वेळही आली!' हे संपादकीय (७ ऑक्टोबर) वाचले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना तांत्रिकतेचा आधार घेऊन, चौकशी समितीचे देखावे उभे करून वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इतिहासात अनेकांनी जनभावनेचा आदर करत नैतिक निकषांवर राजीनामे दिले आहेत. पद टिकवण्यापेक्षा विवेक जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थीच्या तसेच पालकांच्या मनातील रोष, संशय दूर करायचा असेल तर संपूर्ण लोकसेवा आयोगाचे 'शुद्धीकरण' करावे लागेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाविषयी पुन्हा विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक आधार न घेता नैतिक निकषांवर अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा. कारण कोणत्याही पदापेक्षा आपल्या विवेकाशी, नैतिकतेशी आणि जनतेच्या विश्वासाशी प्रामाणिक राहणे महत्त्वाचे असते.

■ **ज्ञानेश्वर गोरे,** राजगुरूनगर (पुणे)

विवेक जागृत करण्याची गरज

विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या संख्येने अभ्यास सोडून गेले सात दिवस आंदोलन करत आहेत तो उगाचच काहीही कारण नसताना केलेला उपद्व्याप नाही, हे लक्षात घेऊन एकतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या विवेकाला स्मरून आयोगाच्या अध्यक्षांना राजीनामा देण्यास सांगावे. आयोगाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांचा शब्द टाळू शकतील, असे वाटत नाही. नाहीतर अध्यक्ष भीमनवार यांनी आपला विवेक जागृत करून राजीनामा द्यावा. दोघांनीही सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करावा हीच आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे.

■ **अजय गायकवाड,** मुरुम (धाराशिव)

सत्र परीक्षेबरोबरच 'पॅट' घ्या

'दिवाळी सुट्टीनंतर पॅटला विरोध' ही बातमी (लोकसत्ता- ७ ऑक्टोबर) वाचली. दिवाळीपूर्वी अनेक शाळांमध्ये प्रथम सत्र परीक्षा किंवा विविध शैक्षणिक मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात. त्यानंतर दिवाळीची सुट्टी आणि लगेचच 'पॅट'ची तयारी व परीक्षा, असा क्रम ठेवल्यास विद्यार्थ्यांना सातत्याने परीक्षेच्या तणावाखाली ठेवण्यासारखे होईल. परीक्षा आणि मूल्यमापन आवश्यक असले तरी त्याचे योग्य नियोजन विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन होणे गरजेचे आहे. मूल्यमापन निश्चितच महत्त्वाचे आहे; मात्र मूल्यमापनाची वेळ, वारंवारिता आणि पद्धत हीसुद्धा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे 'पॅट'चे नियोजन प्रथम सत्राच्या परीक्षेबरोबर किंवा दिवाळीपूर्वी करता येईल का, याचा शिक्षण विभागाने गांभीर्याने पुनर्विचार करावा.

■ **बाळू बुधवंत,** जिंतूर (परभणी)

मूल्यमापनाशिवाय मार्गदर्शन अशक्य!

'दिवाळी सुट्टीनंतर पॅटला विरोध' ही बातमी (लोकसत्ता- ७ ऑक्टोबर) वाचली. पहिल्या सत्राच्या मूल्यमापनावरूनच दुसऱ्या सत्रात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कसे करावे हे शिक्षकांना समजते. त्यामुळे दिवाळीच्या सुट्टीनंतर परीक्षा घेणे हे सर्वथा चुकीचे आहे. दिवाळी सुट्टीनंतर लगेचच परीक्षा देण्याची विद्यार्थ्यांची मानसिकता नसते. पुढे फेब्रुवारी महिन्यात जनगणनेची टांगती तलवार शिक्षकांवर आहेच. मग दुसऱ्या सत्राची परीक्षा जूनमध्ये घेणार का? तेव्हा अशैक्षणिक कामांमुळे झाला तो बट्ट्याबोळ पुरे झाला. याच सत्रात परीक्षा घेऊन शिक्षक, पालक तसेच विद्यार्थ्यांचा मनस्ताप दूर करावा.

■ **बागेश्री झांबरे,** मनमाड (नाशिक)

पाण्याचा अपव्यय कशासाठी?

'दुष्काळी स्थितीत रस्ते धुण्याचा प्रस्ताव' ही बातमी (लोकसत्ता- ७ ऑक्टोबर) वाचली. या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने मुंबईतील पाणीपुरवठ्यात दहा टक्के कपात करावी लागली. त्यातच मुंबई महानगरपालिकेने प्रदूषणाचे कारण देत मुंबईतील ६५७ किलोमीटर लांबीचे ३७७ रस्ते धुण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून करदात्यांचे ८.२५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. का? कशासाठी? यातून कोणाचे भले केले जाणार आहे? महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. जनतेला पिण्यासाठी पाणी नाही, गायी-गुरे पाण्याविना त्रस्त आहेत. अशा स्थितीत हा अपव्यय कशासाठी?

■ **दत्ताराम गवस,** कल्याण

पाणीच नाही, रस्ते कसे धुणार?

पाण्याच्या काटेकोर नियोजनासाठी महाराष्ट्र राज्यभरात विविध योजना आखल्या जात आहेत. मुंबई-महामुंबई परिसरातही नियोजनाचा एक भाग म्हणून पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. असे असताना एरवी हिवाळ्यात त्रस्त करणारी वायूप्रदूषणाची समस्या यंदा ऑक्टोबरमध्येच भेडसावू लागली आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गतवर्षी बांधकामांच्या ठिकाणी कडक निर्बंध घातले गेले होते, पण त्यांचे काटेकोर पालन झाले नाही. (कारण सांगणे न लगे.) प्रदूषणाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रस्ते-पदपथ धुतले गेले. पण आता पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तो पर्यायही शिल्लक राहिलेला नाही.

■ **किरण चौधरी,** मुंबई

अण्णा भाऊ साठेंचे चित्रपटांतील योगदान दुर्लक्षित!

अण्णा भाऊंच्या साहित्याप्रमाणेच त्यांच्या चित्रपटांमुळेही मराठी चित्रपट विश्वाला एक नवी भाषा आणि उपेक्षित वर्गाच्या जगण्याभोवती फिरणारी कथाशैली लाभली. तमाशा कलाकार, सामाजिक बंडखोर आणि स्थलांतरित कामगारांचे जीवन त्यातून समोर आले. तरीही चित्रपटसृष्टीने त्यांच्या सहभागाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले...



हरीश स. वानखेडे
'जेएनयू'तील सहयोगी प्राध्यापक
enarish@gmail.com

सिनेकारण

आधुनिक मराठी साहित्याचा प्रवास हा प्रामुख्याने जातविरोधी सुधारणा, राष्ट्रवादी प्रेरणा आणि समाजवादी चळवळींच्या सांस्कृतिक प्रवाहांतून घडला आहे. या समृद्ध वाङ्मयीन परंपरेत ज्यांना 'अण्णाभाऊ साठे' म्हणून आदराने साद घातली गेली, त्या तुकाराम भाऊराव साठे यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दलित मातंग समाजात जन्मलेले आणि दारिद्र्याच्या भयंकर वास्तवातून तावून सुलाखून वर आलेले अण्णा भाऊ साठे हे मराठी साहित्याचे एक आद्यप्रणेते ठरले. लोकनाट्याच्या परंपरेला नवी दिशा देत त्यांनी सर्वसामान्य कामगार आणि उपेक्षितांच्या नवीन जाणिवांना वाणी दिली. लोकप्रिय कलावंतांच्या राजकीय अस्मितेला नवी उंची मिळवून दिली.

दिग्दर्शक मिलिंद चंपनेरकर यांचा 'फूटप्रिन्ट्स ऑफ अण्णाभाऊ साठेज लोकनाट्य' हा ९० मिनिटांचा माहितीपट नुकताच प्रदर्शित झाला. त्यात अण्णाभाऊ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लोककला (विशेषतः तमाशा आणि लोककथा) कशी आमूलाग्र बदलली, याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. अभिजात साहित्य आणि उपेक्षितांच्या तोंडी परंपरा यांमधील दरी कशी मिटवली, याचे दर्शन हा माहितीपट घडवतो. मुख्य प्रवाहातल्या साहित्याच्या आणि सांस्कृतिक संस्थांच्या संकुचितपणावर हा माहितीपट प्रकाश टाकतो, मात्र तोही प्रामुख्याने त्यांच्या लोकपरंपरेपुरताच मर्यादित राहतो; मराठी चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या पटकथालेखन आणि कथालेखनाच्या योगदानाकडे मात्र यात दुर्लक्ष झाले आहे.

लोकप्रिय चित्रपटसृष्टीने सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये आकारात आणण्यात नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. परंतु या शक्तिशाली माध्यमाचा वापर नेहमीच प्रस्थापित उच्चभ्रू वर्गाने स्वतःचे सांस्कृतिक आणि वर्गीय हितसंबंध जपण्यासाठी केला. या एकछत्री अमलाला दलित-बहुजन साहित्याने अत्यंत प्रभावीपणे आव्हान दिले आणि आपल्या कथांसाठी एक स्वाभिमानी अवकाश निर्माण केला; तरीही सांस्कृतिक उद्योगात हे विश्व आजही उपेक्षितच राहिले आहे. अण्णा भाऊ साठे यांचा चित्रपटसृष्टीतील प्रवास या अनुभवापेक्षा वेगळा नाही. ते मराठी साहित्यातील एक अजस्र व्यक्तिमत्त्व आणि वैचारिक आयकॉन असूनही, लोकप्रिय चित्रपट संस्कृतीत त्यांच्या सहभागाकडे कायम जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले आणि त्यांना विस्मृतीच्या अंधारात ढकलले गेले.

जात-वर्गाचे अनोखे समीकरण

अण्णाभाऊंचे वाङ्मयीन कार्य अफाट आहे. त्यात पस्तीसहून अधिक कादंबऱ्या, अनेक कथासंग्रह, नाटके, प्रवासवर्णने, चित्रपटांच्या पटकथा आणि सहकाऱ्यांचे लेख यांचा समावेश आहे. त्यांचे साहित्य केवळ उपेक्षितांच्या दुःखाचे दस्तऐवजीकरण करत नाही, तर मानवी मूल्ये, सामाजिक अनुभव आणि वैयक्तिक आकांक्षांना साहित्याच्या केंद्रस्थानी आणून मराठी साहित्याच्या सौंदर्यशास्त्राची पुनर्रचना करते. अण्णाभाऊंच्या साहित्याचा खरा अन्वय लावायचा असेल, तर मार्क्सवादी वर्गप्रश्न आणि आंबेडकरी जातविरोधी विचारसरणीचा त्यांचा अनोखा ताळमेळ समजून घ्यावा लागेल.

ग्रामीण गरिबांना केवळ दयेचे पात्र मानणाऱ्या किंवा दारिद्र्याचे अवडंबर माजवणाऱ्या त्याकाळच्या सरंजामशाही साहित्यापेक्षा अण्णाभाऊंचे लेखन वेगळे होते. त्यांनी गाव आणि शहर हे संघर्षाचे आखाडे म्हणून पाहिले, जिथे जातिभेद आणि वर्गभेद एकत्र नांदत होते. उच्चभ्रू वर्गाकडून ज्या तमाशाला कायम 'असंस्कृत' किंवा 'हलक्या दर्जाचे' म्हणून हिणवले गेले, त्याच तमाशाला अण्णाभाऊंनी आपल्या कलाप्रकाराचे माध्यम बनवले. त्यांनी तमाशाचा सांस्कृतिक दर्जा बदलून त्याला तीव्र राजकीय शिक्षणाचे आणि प्रतिरोधाचे हत्यार बनवले.

श्रमिक वर्गात प्रचंड लोकप्रिय असूनही, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक सत्ताकेंद्रांनी अण्णाभाऊंकडे सतत दुर्लक्ष केले. मुंबईतील कामगार वर्गात ते लोककलेचे सक्रिय सादरीकरण करत होते आणि डाव्या-समाजवादी राजकीय चळवळींशी घट्ट जोडलेले होते. मुंबईत आकारास आलेले हिंदी आणि मराठी चित्रपटविश्वसुद्धा त्याकाळच्या डाव्या-समाजवादी चळवळींनी प्रभावित झाले होते. साहजिकच, डाव्या चळवळींशी असलेल्या संपर्कामुळेच अण्णाभाऊ चित्रपटसृष्टीत दाखल झाले.

मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीत अण्णाभाऊ

मराठी चित्रपटसृष्टीशी अण्णाभाऊंचा संबंध हा त्यांच्या बौद्धिक प्रवासातील एक रंजक अध्याय आहे. १९६१ ते १९७४ या काळात अण्णाभाऊंच्या कादंबऱ्या व कथांवर आधारित सात मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाले (उदाहरणार्थ 'वरणेचा वाघ', 'फकिरा', 'वैजयंता' आणि 'आवडती'). दुर्दैवाने आज त्यातील मोजकेच चित्रपट उपलब्ध आहेत. त्यांच्या साहित्याप्रमाणेच या चित्रपटांमुळे मराठी चित्रपटाला एक नवी भाषा, नवे सौंदर्यशास्त्र आणि उपेक्षित वर्गाच्या जगण्याभोवती फिरणारी कथाशैली लाभली; विशेषतः तमाशा कलाकार, सामाजिक बंडखोर आणि स्थलांतरित कामगारांचे जीवन यातून समोर आले.

व्यावसायिक लाभासाठी असणाऱ्या तकलादू आणि सुटकेच्या मनोरंजनाला नाकारत दलित साहित्याने स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. गिरणी कामगार, विमुक्त भटक्या जमाती, शरीर विक्रय करणाऱ्या महिला, लोककलाकार आणि ग्रामीण गरीब यांच्या जगण्याला अण्णाभाऊंनी साहित्यात केंद्रस्थानी ठेवले. समांतर चित्रपट चळवळीने (श्याम बेनेगल आणि गोविंद निहलानी यांच्यासारखे दिग्दर्शक) काही प्रमाणात अशीच भूमिका घेतली, तरी ती दलित वैचारिक विश्वापासून आणि सांस्कृतिक कलाकारांपासून कायम दूर राहिली.

दुहेरी उपेक्षा

उच्चभ्रू आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या मुख्य प्रवाहातील मराठी साहित्याने अण्णाभाऊंकडे हयातभर आणि मृत्यूनंतरही दुर्लक्ष केले. औपचारिक शिक्षण नसणे, बोलीभाषेचा वापर करणे आणि त्यांचा तडजोड न करणारा मार्क्सवादी-आंबेडकरी बाणा- या सर्व गोष्टी मध्यमवर्गीय, सोज्वळतावादी समीक्षकांना खुपत होत्या. त्यामुळे त्यांच्या साहित्याला 'गंभीर' साहित्याच्या वर्तुळाबाहेर ठेवले गेले आणि त्याला केवळ राजकीय प्रचाराचे साहित्य म्हणून हिणवले गेले.

दुसरीकडे, हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतही अण्णाभाऊंना याच प्रकारच्या दुर्लक्षाचा सामना करावा लागला. विशेषतः १९६० आणि १९७० च्या दशकात मुंबईची हिंदी चित्रपटसृष्टी भरभराटीस आली. डाव्या-उदारमतवादी विचारवंतांच्या प्रभावाखाली या काळात सामाजिक जाणिवांचे चित्रपट आले. राज कपूर, बलराज साहनी, चेतन आनंद, बिमल रॉय यांसारख्या दिग्गजांमुळे या सुवर्णकाळात गरीब कामगार वर्गाचा नायक मध्यवर्ती भूमिकेत आला.

विशेष म्हणजे, अण्णाभाऊ हे या डाव्या सांस्कृतिक प्रवाहाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होते. ते 'इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशन' (इप्टा) चे संस्थापक सदस्य होते आणि १९४९ मध्ये त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्षही झाले होते. गीतकार शैलेंद्र यांच्यासह चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध होते. तरीही विरोधाभास असा की, मुख्य प्रवाहातील हिंदी चित्रपटसृष्टी अण्णाभाऊंच्या साहित्यापासून दूरच राहिली. शोषित वर्ग आणि त्यांची जातिव्यवस्था यांमधील परस्परसंबंध दाखवणाऱ्या कथांना हिंदी चित्रपटसृष्टीने क्वचितच थारा दिला.

दलित साहित्याने अण्णाभाऊंना आदराने आपला पायाभूत पुरुष मानले, पण मुख्य प्रवाहातल्या चित्रपट उद्योगाने त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. चित्रपटसृष्टीने नेहमीच शहरी, उच्चशिक्षित उच्चभ्रूंना प्राधान्य दिले; अण्णाभाऊंचे अवाढव्य आणि लोककलाधिष्ठित विश्व त्यांना समजलेच नाही. कारण अण्णाभाऊंच्या साहित्यात वर्गीय शोषणाबरोबरच अस्पृश्यतेचे दुःसह वास्तवही तितक्याच ताकदीने मांडलेले होते, जे पचवणे मुख्य प्रवाहातील दिग्दर्शकांना कठीण गेले.

आजच्या काळात महत्त्व काय?

आजच्या काळात नागराज मंजुळे, पा. रंजित, नीरज घायवान, शैलेश नरवाडे यांसारख्या सक्षम दिग्दर्शकांमुळे 'दलित सिनेमा' या नवीन प्रवाहाचा उदय होत आहे. परंतु हा प्रवाह येण्याआधी कित्येक दशके अण्णाभाऊंचे साहित्य आणि त्यावर आधारित मराठी चित्रपट या वाटेवर चालले होते. लोकप्रिय दृश्यकला ही सामाजिक जाणिवेचे आणि राजकीय परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम बनू शकते, हे अण्णाभाऊंच्या साहित्याने कैक वर्षांपूर्वीच अधोरेखित केले होते.

शोषितांना आणि उपेक्षितांना केवळ कमकुवत किंवा दयापात्र म्हणून न दाखवता त्यांना वैचारिक खोली आणि विद्रोहाची धार देणारे अण्णाभाऊ हे पहिले शिल्पकार आहेत. आज जेव्हा आपण जात आणि वर्गाच्या प्रश्नांवर गंभीरतेने विचार करतो, तेव्हा अण्णाभाऊंचे विचार आपल्याला दिशा दाखवणारी मशाल ठरतात. मुख्य प्रवाहातील हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीने या महान दलित सांस्कृतिक 'आयकॉन'ला हवे ते मानाचे स्थान दिले नसले, तरी आजच्या तरुण पिढीचे दिग्दर्शक त्यांच्याच पद्धतींचा आणि तत्त्वज्ञानाचा पुनर्शोध घेत आहेत. जात, लिंगभाव आणि वर्ग यांच्यातील गुंतागुंतीचे धागेदोरे ते अत्यंत प्रभावीपणे पडद्यावर मांडत आहेत. त्यामुळे अण्णाभाऊंचे विचार आता केवळ साहित्यापुरते सीमित राहिलेले नसून, त्यातून आता शोषित समाजाच्या आत्मसन्मानाची आणि नव्या, समतावादी सिनेमाची नवी पहाट उजाडण्याची चिन्हे आहेत.

कुतूहल

समुद्रांचे रंग वेगवेगळे का?

हल्ली बरेचजण देश-विदेशात समुद्रकिनारी फिरायला जातात किंवा यूट्यूब इत्यादीवर समुद्राचे व्हिडीओ पाहतात. त्यावेळी समुद्राचं पाणी कधी गडद निळं, कधी हिरवं, कधी निळसर तर कधी पिवळसर तपकिरी दिसतं. कधी स्वच्छ तर कधी गढुळलेलं दिसतं. पण तेच समुद्राचं पाणी जर आपण एका लहान पारदर्शक भांड्यात घेतलं तर मात्र ते रंगहीन दिसतं. असा समुद्राच्या पाण्याच्या रंगात फरक कसा काय होतो?



साधं पाणी हे रंगहीन व पारदर्शकच असतं. पण समुद्राचा रंग हा बरेच ठिकाणी निळा दिसतो, कारण समुद्रावर जेव्हा प्रकाश पडतो त्यावेळी पाण्याचे रेणू प्रकाशाच्या वर्णपटातले लाल, नारिंगी, पिवळा, हिरवा हे लांब तरंगलांबीचे रंग सहज शोषून घेतात. निळा, जांभळा हे लहान तरंगलांबीचे रंग त्या पाण्याच्या रेणूंमधून पुढे जातात किंवा परावर्तित होतात. दुसरं म्हणजे पाण्याचे रेणू आणि पाण्यातले अगदी सूक्ष्म कण इतर रंगांच्या प्रकाशापेक्षा निळा प्रकाश जास्त पसरवतात. म्हणूनच अगदी स्वच्छ महासागराच्या पाण्यातसुद्धा निळ्या प्रकाशाचं विकिरण होतं. जसं आकाशात निळ्या प्रकाशाचं विकिरण झाल्यामुळे आकाश निळं भासतं, त्याचप्रमाणे तो समुद्र आपल्याला निळा भासतो.

परंतु याच समुद्रामध्ये जेव्हा सेंद्रिय पदार्थ, क्लोरोफिल रंगद्रव्य असलेले जिवंत वनस्पती प्लवक, खनिज गाळ इत्यादी मिसळलेले असतात तेव्हा समुद्राचा रंग निळ्यापेक्षा वेगळा असतो. हरितद्रव्याचा (क्लोरोफिलचा) रंग हिरवा दिसतो कारण हे रंगद्रव्य, प्रकाशातला निळा आणि लाल हे रंग शोषून घेतं. म्हणूनच ज्यावेळी पाण्यात क्लोरोफिल रंगद्रव्य असलेले वनस्पती प्लवक जास्त प्रमाणात असतात त्यावेळी समुद्राचा रंग हिरवा दिसतो. विरघळलेले सेंद्रिय पदार्थ किंवा खनिज गाळ किंवा दोन्ही असले तर समुद्र पिवळसर तपकिरी रंगाचा दिसतो. क्वचित जिथे लाल रंगाचं वनस्पती प्लवक आढळतं तिथे समुद्र लालसर दिसतो.

याबरोबरच जेव्हा समुद्र खूप खोल म्हणजे २०० मीटरपेक्षा जास्त खोल असतो तिथे लाल, नारिंगी, पिवळा, हिरवा हे रंग पूर्णपणे शोषले जातात. म्हणून इथे समुद्राचा निळा रंग खूप गडद असतो. पण जर समुद्र कमी खोल अथवा उथळ असेल तर तिथे समुद्राच्या तळाशी असलेल्या पांढऱ्या वाळूमुळे पसरणारा निळा रंग हा फिरोजी निळा होतो.

दाट लोकवस्तीच्या जवळच्या समुद्रकिनाऱ्यावरचं पाणी मातकट गडद तपकिरी दिसतं. वाहून आलेल्या मातीमुळे, नद्यांमधून आलेल्या गाळ आणि सेंद्रिय कचऱ्यामुळे समुद्राचं पाणी गढूळ, प्रदूषित होतं आणि त्याचा रंग करडा होतो. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत समुद्राचे रंग वेगवेगळे दिसतात.

– डॉ. मुग्धा पत्की
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

एका तिरडीचे आत्मकथन

__सर्वात आधी__ छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांना साष्टांग दंडवत. त्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून माझी विटंबना थांबवली. अन्यथा माझ्यावर पहुडलेला तो तथाकथित उमेदवार माझ्यासकट थेट निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कक्षातच पोहोचला असता. आजकाल प्रसिद्धीसाठी कोण कशाचा आधार घेईल हे सांगता येत नाही हेच खरे! ज्यांचे जीवनातले मार्ग संपलेले असतात तेच माझ्यावर पहुडतात. हा महाभाग त्याच्या राजकीय जीवनाचा मार्ग शोधण्यासाठी मला घेऊन निघाला होता. आजचा काळच उफराटा. त्यामुळे या उपटसुंभाला दोष तरी किती द्यायचा? काय तर म्हणे, सगळे नेते मेलेले आहेत. त्यांना जागे करण्यासाठी माझा प्रतीकात्मक वापर करायचा आहे म्हणून. अरे महाभागा, सगळेच नेते मेले असतील तर याच नेत्यांना फोन करून, त्यांच्याशी झालेले संभाषण ध्वनिमुद्रित करून ते समाजमाध्यमावर टाकण्याचा धंदा तरी तू का करतोस? तुझ्या फोनच्या जाळ्यात जे अडकतात ते आत्मे आहेत की हाडामांसाचे जीव? एकदा हे स्पष्ट करून सांग ना जरा! एकीकडे नेत्यांना फोन लावून त्यांना बदनाम करण्याचा धंदा जोमात करायचा व दुसरीकडे ते मेलेले म्हणत निवडणुकीच्या रिंगणात उडीही घ्यायची यातला विरोधाभास तरी कळतो का तुला?

तू या जगातला पहिला माणूस आहेस जो जिवंतपणी मेल्याचे सोंग घेत माझ्यावर आडवा झाला. हा तुझा उपद्व्याप मी का म्हणून सहन करायचा? भलेही दोन मोठे बांबू व दहा-वीस कामट्यांनी मला आकार येत असेल पण मलाही काही इज्जत आहे की नाही? माझे साकार होणे अल्पकाळासाठीचे. माझा मार्गही ठरलेला. मृताच्या घरापासून स्मशानापर्यंतचा. त्यापलीकडे मला भविष्य नाही. मात्र माझे अस्तित्व मुक्तीच्या मार्गाकडे नेणारे अशी तमाम लोकांची श्रद्धा. त्याला तडा देऊन तुला साधायचे तरी काय?

स्वतः मरण्याचे नाटक करून तू व्यवस्थेला जिवंत करण्याचा प्रयत्न करतोस. हा तमाशा आहे, हे तुझ्या लक्षात येत नाही काय? मी मृत्युपर्वात वापरले जाणारे निमित्तमात्र साधन. सर्वसंगपरित्यागानंतरच्या अंतिम प्रवासातले. त्याचा वापर करून तू राजकारणात चैतन्य आणू पाहतोयस, हे कसे शक्य आहे याचा विचार तरी कधी केला आहेस का? माझ्याविषयी तुला एवढेच ममत्व असेल तर त्या शकुंतला परांजपेंची कथा वाच! माझ्यावर लिहिलेली. मग कळेल तुला माझी किंमत व गांभीर्यसुद्धा! अरे, माझे अस्तित्व जरी अल्पकाळासाठी असले तरी लक्ष असते माझे जगरहाटीकडे. निवडणुकीचा अर्ज भरायला लोक कधी हत्तीवर स्वार होतात, तर कधी घोड्यावर. आता रथाची फॅशन आहे. महागडी कार व सजवलेले ट्रक हे तर नित्याचेच. हे सगळे विसरून तुला माझा वापर करण्याची बुद्धी कुठून झाली?

त्या तिकडे पुण्यानगरीत पवारांच्या रोहितने कुणा आयोगाच्या अध्यक्षाची अंत्ययात्रा काढण्यासाठी माझा वापर केला म्हणे! अरे, हे चाललेय काय? माझा वापर करून राजमार्ग गाठता येतो असे अनेकांना वाटू लागले की काय? तुम्हाला तुमचे राजकीय उट्टे काढायचे असेल तर जरूर काढा. माझी काही ना नाही त्याला. पण, उगीच माझ्याभोवती असलेल्या गांभीर्याच्या वलयाची चेष्टा का करताय? थांबवा रे हे उद्योग. कलेवरांना अनंतात विलीन करण्याचे काम सुखाने करू द्या की मला.

राजवाडे विचारविश्व

वाईतील दोन मराठी मोडी ताम्रपत्रे

वि. का. राजवाडे यांच्या विविधांगी कार्यामधील अभिलेखांच्या संशोधनासारख्या काहीशा चाकोरीबाहेरच्या पैलूचा अगदी संक्षिप्त धावता आढावा आवरता घेण्यापूर्वी आणि त्याच क्षेत्रातल्या शेवटच्या उदाहरणाची माहिती सांगण्यापूर्वी त्यांच्यावरील टीकेचा एकच मुद्दा इथे थोडक्यात उल्लेखावासा वाटतो. 'प्राचीन मराठी कोरीव लेख' या वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथाचे व्यासंगी लेखक डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी राजवाडे यांच्या संशोधन पद्धतीविषयीचे काही आक्षेप आपल्या प्रस्तावनेत नोंदवले आहेत. त्यांच्यापैकी एकाचाच येथे उल्लेख करतो.

'राजवाडे शिलालेखाचा वा ताम्रपटाचा ठसा देत नाहीत. शिलालेख सहसा नष्ट होत नाहीत, पण ताम्रपट ही नष्ट वा भ्रष्ट होणारी वस्तु असल्यामुळे त्यांचा ठसा देणे अत्यंत आवश्यक असते', हा डॉ. तुळपुळे यांचा आक्षेप राजवाड्यांवर कसा अन्याय करणारा आहे, हे गुरुवर्य नरहर कुरुंदकर यांनी स्पष्ट केले होते. डॉ. ब्रह्मानंद देशपांडे यांच्या 'शोधमुद्रा' या अभिलेखविषयक ग्रंथाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत त्यांनी म्हटले होते, 'राजवाड्यांचे ऐतिहासिक लेखसंग्रह प्रकाशित होऊ लागले, तेव्हा त्यावर एक टीकाही होती की, हे शास्त्रशुद्ध संपादन नाही, प्रत्येक कागदपत्राचा ठसा हवा. राजवाड्यांनी उत्तर देताना ही गरज मान्य केली होती व असे म्हटले होते की, अशा प्रकारच्या प्रकाशनाचा खर्च कुणी जर सोसणार असेल, तर आपण विनामूल्य सेवेला तयार आहोत. एरवी आमच्या शक्तीत या विदुराच्या कण्या आहेत, त्या गोड मानून घेणे भाग आहे'... आणि डॉ. देशपांडे सरांनी अधिक परखड प्रतिक्रिया नोंदवत लिहिले होते, 'राजवाडे अनिकेत आणि अकिंचन होते, त्यांना राजाश्रय अथवा लोकाश्रयही नव्हता, हे डॉ. तुळपुळे ह्यांना पुरतेपणी ठाऊक आहे. आपला ग्रंथ सिद्ध करताना डॉ. तुळपुळे यांच्या सेवेशी पुणे विद्यापीठाची सर्व साधनसंपदा होती. त्यांनी इतिहासाचार्यांना समजून न घेताच ताशेरे ओढले आहेत.'

राजवाड्यांवरील एका बहुचर्चित आक्षेपाचे असे निराकरण करून झाल्यावर आता फक्त त्यांनी उजेडात आणलेल्या वाईच्या दोन मराठी मोडी ताम्रपत्रांबद्दलची थोडक्यात माहिती घेऊ या. कोल्हापूरहून प्रकाशित होणाऱ्या 'विश्ववृत्त'मधून १९०६ साली त्यांनी या ताम्रपत्रांबद्दलचा प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध केला होता. त्या लेखात ताम्रपत्रांबद्दलची प्राथमिक माहिती देत त्यांनी लिहिले होते, 'ही दोन ताम्रपत्रें वाई येथील श्रीमंत तात्यासाहेब पंत, राजाज्ञा, यांच्याकडची आहेत. पहिलें ताम्रपत्र शक १४६३मधलें (इसवी सन १५४१मधले) आहे, तर दुसरें शक १४५२मधलें (इसवी सन १५३०मधले) आहे. पहिल्याचे दोन पत्रे असून पहिल्या पत्र्याच्या पोटावर लिहिलें आहे, पाठ रिकामी आहे आणि दुसऱ्या पत्र्याच्या दोन्ही बाजूंवर लेख आहे. दुसऱ्या ताम्रपत्राचा एकच पत्रा असून तें दोन्ही बाजूंनीं कोरलेलें आहे. दुसऱ्या ताम्रपत्राचा पत्रा तीन ठिकाणीं आडवा फुटून त्याचे लहानमोठे चार भाग झाले आहेत. पहिल्या ताम्रपत्राच्या तीन पृष्ठावर एकंदर ५२ ओळी आहेत, तर दुसऱ्याच्या दोन पृष्ठांवर मिळून ४९ ओळी आहेत. अक्षरांचे वळण मुसुलमानी रियसायतींतील वळणासारखे आहे...'

आपल्या लेखनातून राजवाडे वेळोवेळी समाजात पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजुतींचे कसे साधार निराकरण करीत, याचे एक चांगले उदाहरण म्हणजे त्यांनी या दोन ताम्रपत्रांवरील लेखाचा केलेला समारोप. कुणा तरी रा. रा. गुप्ते नामक गृहस्थांनी 'मोडीची कल्पना प्रथम बाळाजी आवजी चिटणीस याने काढिली, ती हेमाडपंतानें काढिली हें वर्तमान कोकणस्थांनी उठविले आहे', असे विधान दोन-तीन ठिकाणी केले होते. त्याचे खंडन करताना राजवाड्यांनी लिहिले, 'ही दोन्ही ताम्रपत्रें अस्सल असून तीं अनुक्रमें शक १४५२ व १४६३ ह्या सालांतील आहेत... शिवाजीच्या जन्माअगोदर ९७ व ८६ वर्षे ही तामपत्रें कोरून झालीं होतीं. शक १५७१च्या सुमाराला शिवाजीने बाळाजी आवजीला कोकणातून आपल्याजवळ आणिलें. म्हणजे बाळाजी शिवाजीच्या पदरीं राहण्यापूर्वी हीं मोडी ताम्रपत्रें होऊन अनुक्रमें ११९ व १०८ वर्षे लोटली होती. अर्थात् मोडीची कल्पना बाळाजी आवजीच्या पूर्वीची आहे, यात काडीचाहि संशय नाहीं...'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

दुष्काळी दरवाढ!

चलनवाढ डोळ्यासमोर असताना व्याज दरवाढ न करणे हे शहामृगाने वाळूत मान खुपसून वास्तवाकडे पाठ फिरवण्यासारखे ठरले असते.

बराच काळ कळ सोसल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने अखेर 'रेपो' दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. 'रिपर्चेस' या शब्दाचे 'रेपो' हे लघुरूप. रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना सरकारी रोख्यांच्या तारणावर ज्या व्याज दराने कर्ज देते त्यास 'रेपो रेट' असे म्हणतात. एकदा का या व्याज दरात वाढ झाली की संबंधित सर्वच व्याज दर वाढू लागतात. पक्ष कोणताही असो आणि देशदेखील कोणताही असो. स्वतःच्या सत्ताकाळात व्याज दर वाढवलेले कोणालाच आवडत नाही. अमेरिकेत या संदर्भात अलीकडे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि तेथील मध्यवर्ती बँकेचे 'फेडरल रिझर्व्हज ' (फेड) प्रमुख केविन वॉर्श यांच्यात झालेला जाहीर वाद अनेकांस आठवेल. हे वॉर्श ही ट्रम्प यांची अलीकडची नियुक्ती. त्यांचे पूर्वसुरी जेरोम पॉवेल हे ट्रम्प यांस आवडेनासे झाले. कारण 'फेड'चे प्रमुख या नात्याने पॉवेल देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी त्या पदावरील व्यक्तीने जे करणे अपेक्षित आहे ते करत होते. तसे करताना आपल्या अध्यक्षांस काय वाटते याची फिकीर त्यांनी कधी केली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांची त्यांच्यावर खप्पा मर्जी झाली. ते जाहीरपणे पॉवेल यांच्याविषयी वचावचा बोलत. पण पॉवेल आपल्या अध्यक्षाच्या तोंडास कधी लागले नाहीत. त्यांनी स्वतःला हवे तेच केले. अखेर त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्याची संधी अध्यक्ष ट्रम्प यांस मिळाली आणि त्यांनी वॉर्श यांस या पदी आणले. तथापि या पदी आरूढ झाल्यानंतरच्या पहिल्याच संधीचे सोने या वॉर्श यांनी केले आणि ट्रम्प राग भरत असतानाही त्यांनी व्याज दरवाढ जाहीर केली. यूरोपीय मध्यवर्ती बँक, इंग्लंड अशा अनेक देशांतील बँकांसही व्याज दरवाढ करावी लागली. तीस पर्याय नव्हता.

म्हणून अखेर चार वर्षांनी का असेना आपल्या रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरवाढीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या एकट्याचा नसतो. या विषयावर साधक-बाधक चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती असते. बँकेच्या या पतधोरण समितीच्या बैठकीत याबाबत सगळ्यांचे एकमत झाले. परिणामी संजय मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून पहिली व्याज दरवाढ जाहीर झाली. हे अपरिहार्य होते. इम्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांनी इराणवर लादलेले युद्ध, त्यात अमेरिकेने अकारण घेतलेली उडी आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या युद्धाचा शेवट काय याचा संबंधितांस कसलाही अंदाज नसणे आदी कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अकारण अस्थिर झालेली आहे. आखातातील या संघर्षामुळे खनिज तेलाचे दर ११५ डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत गेल्यानंतर, त्यामुळे होणारी चलनवाढ डोळ्यासमोर असताना व्याज दरवाढ न करणे हे शहामृगाने वाळूत मान खुपसून वास्तवाकडे पाठ फिरवण्यासारखे ठरले असते. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबाबत सध्या बरेच काही बोलले जात आहे. बँकेच्या लाभांशाची घसघशीत वार्षिक दक्षिणा रिझर्व्ह बँक मान खाली घालून इमाने-इतबारे केंद्राच्या हवाली करत असतेच. गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कमाईतील अनुक्रमे दोन लाख ६८ हजार कोटी रुपये, त्या पुढील वर्षी दोन लाख ८७ हजार कोटी रुपये इतका लाभांश केंद्राच्या झोळीत टाकला. रिझर्व्ह बँकेचे केंद्रास असे निधी पुरवणे गेल्या काही वर्षांत कसे वाढत गेले ते पुढील आकडेवारीवरून लक्षात यावे. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या वर्षात ६५ हजार ८९६ कोटी रु. (२०१५), ६५ हजार ७७५ कोटी रु. (२०१६), ३० हजार ६५९ कोटी रु. (२०१७), ५० हजार कोटी रु. (२०१८), १ लाख ७५ हजार ९८८ कोटी रु. (२०१९), ५७ हजार १२८ कोटी रु. (२०२०), ९९ हजार १२२ कोटी रु.

ही व्याज दरवाढ याहीवेळी टाळली गेली असती तर रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबाबतच्या शंका-कुशंकास अधिक समर्थन मिळते. तो धोका टळला.

(२०२१), ३० हजार ३०७ कोटी रु. (२०२२), ८७ हजार ४१६ कोटी रु. (२०२३), दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रु. (२०२४), दोन लाख ६८ हजार ५९० (२०२५) आणि यंदा दोन लाख ८६ हजार ५८८ कोटी रु. असा निधी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत केंद्रास पुरवला आहे. त्यामुळे बँकेच्या अभिप्रेत आहेत आणि युद्धात ज्यांची होरपळ होत आहे त्यांनाही ते संपण्याची घाई आहे असे अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे जग अशा विचित्र कात्रीत सापडलेले आहे. ही अशी अस्थिरता अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येते.

आपल्या रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ मर्यादा चार टक्क्यांवर निश्चित केलेली आहे. म्हणजे या मर्यादिपर्यंतची चलनवाढ काळजी निर्माण करणारी नाही. तथापि गेले तीन महिने चलनवाढीचा दर या मर्यादेपेक्षा जास्त आणि ऑगस्टमध्ये तो ४.८२ टक्के इतका राहिलेला आहे. तो लवकरच धोकादायक असा पाच टक्क्यांचा टप्पा ओलांडेल अशी चिंता रिझर्व्ह बँकच व्यक्त करते. आगामी काळात ही चलनवाढ ५.२ टक्के इतकी असेल असे आपल्या मध्यवर्ती बँकेस वाटते. ते वाटणे प्रत्यक्षात आले तर आर्थिक परिस्थिती अधिकच आव्हानात्मक होईल हे उघड आहे. त्यात पश्चिम आशियातील युद्धझळांत जग होरपळून निघत असताना भारतावर दुष्काळ-दाह सहन करण्याची वेळ आलेली आहे. देशभरात सरासरीच्या कित्येक पट कमी पाऊस पडला. त्यामुळे खरिपाची पिके तर हातातून गेल्यात जमा आहेतच; पण हा दुष्काळ रब्बीचा घासही घेतो की काय, अशी चिन्हे दिसतात. सरकारी पातळीवर अधिकृतपणे अशी चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी उधळपट्टीस आवर घालून उपलब्ध निधीतील पै-न-पै उत्पादक कामी होईल याचा विचार आणि तसा प्रयत्न सरकारला करावा लागेल. दुष्काळातील ही दरवाढ अशीच सुरू राहिली तर ते अर्थव्यवस्थेस आणि परिणामी राजकीय स्थैर्यासही आव्हान देणारे ठरेल.

एल निनो आणि महाराष्ट्रावर रुसलेला मान्सून

एल निनो आणि मान्सून म्हटलं की राज्यासह देशातील अनेकांच्या मनात एकच भीती निर्माण होते; ती म्हणजे दुष्काळाची. ३० सप्टेंबर रोजी नैऋत्य मान्सूनचा ऋतू संपला, आणि शेवटी ज्याची भीती होती, तसंच यंदा घडलं. यंदाच्या नैऋत्य मोसमी पावसावर एल निनोचा मोठा प्रभाव पडला असून महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांसमोर दुष्काळाचे संकट उभे राहिले आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या मान्सूनच्या अधिकृत कालावधीत देशात सरासरीपेक्षा सुमारे १३ टक्के कमी पाऊस झाला, तर महाराष्ट्रात ही तूट सुमारे १९ टक्के आहे. मराठवाड्यात ४० टक्के, विदर्भात २३ टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ११ टक्के, तर कोकण आणि गोव्यात १४ टक्के कमी पाऊस झाला आहे.

जिल्हानिहाय चित्र आणखी चिंताजनक आहे. सोलापुरात सरासरीपेक्षा ५८ टक्के, बीडमध्ये ५१ टक्के आणि नंदुरबारमध्ये ३९ टक्के कमी पाऊस झाला. नेहमीच भरपूर पावसासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोकणातील सिंधुदुर्गातही पावसाची तूट ३६ टक्के आहे. पुणे, मुंबई परिसराचा काही भाग, नाशिक आणि गोंदिया वगळता जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. परिणामी किमान २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे, आणि जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कुठे ना कुठे दुष्काळाची परिस्थिती आहे. काहींच्या मते, यंदाची परिस्थिती १९७२च्या मान्सूनसारखी किंवा त्याहूनही अधिक गंभीर आहे. कारण खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत विकट झाली आहे.

मग यंदाच्या पावसाचं वैशिष्ट्य काय? एल निनोमुळे मान्सूनवर इतका परिणाम का झाला? यंदाचा दुष्काळ १९७२ सारखा गंभीर आहे का? आणि वापूर्वीच्या एल निनो वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात काय परिस्थिती होती? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात असतील.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर दर दोन ते सात वर्षांनी प्रशांत महासागराच्या विषुववृत्तीय पूर्वेकडील भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा लक्षणीय वाढते. समुद्र आणि वातावरणातील परस्परसंवादामुळे या स्थितीचा परिणाम जगभरातील हवामानावर, त्यात भारतीय मान्सूनवरही होतो. या स्थितीला एल निनो म्हणतात. एल निनो आणि महाराष्ट्रातील मान्सूनचा

लेख
डॉ. अक्षय देवरस
वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक,
रिडींग विद्यापीठ, इंग्लंड
akshay.deoras@reading.ac.uk

यंदा महाराष्ट्राकडे मान्सूनने पाठ फिरवल्याने दुष्काळाची चिंता अधिक गडद झाली आहे. पावसाची मोठी तूट, दीर्घ कोरडे कालखंड आणि खरीप पिकांचे नुकसान यामुळे राज्यासमोर पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे संकट उभे राहिले आहे. ही परिस्थिती नेमकी किती गंभीर आहे आणि तिच्यामागे एल निनोचा किती प्रभाव आहे?

पावसामध्ये निश्चितच संबंध दिसून येतो. १९७१ते२०२० हा सरासरीचा कालावधी धरल्यास, १९५१ ते २०२५ या ७५ वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात ३७ वर्षे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यापैकी १९ वर्षे एल निनोची होती. म्हणजे या कालावधीत एल निनोच्या वर्षात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता निम्म्याहून अधिक होती. या शतकातील निवडक एल निनो वर्षांकडे पाहिल्यास २००६ वगळता इतर वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. या वर्षांमध्ये राज्यात सरासरीच्या तुलनेत १२ टक्के पावसाची घट दिसते. मात्र यंदाचे चित्र काहीसे वेगळे आहे.

मराठवाड्यातील नेहमीची पावसाची तूट कायम असली, तरी यंदा विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्येही पावसाने मोठी ओढ दिली. दुसरीकडे नाशिक परिसरात सरासरीपेक्षा सुमारे ३३ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. आपल्याला आठवत असेल तर जुलैच्या सुरुवातीला काही दिवस नाशिक आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत मुसळधार पाऊस झाला होता. काही भागांत भूस्खलनाच्या घटनाही घडल्या. त्यापूर्वी जूनमध्ये मान्सूनचे उशिरा झालेले आगमन, विदर्भात १५ जूननंतर ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक नोंदले गेलेले कमाल तापमान आणि एकूणच विक्रमी पावसाची तूट यामुळे सर्वांची चिंता वाढली होती. खानदेशातील काही भाग तर संपूर्ण महिना कोरडा गेला होता.

जुलैमध्ये पावसाचा लपंडाव सुरू झाला. महिन्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्यानंतर पुन्हा पावसात घट पाहायला मिळाली. मात्र, जुलैच्या अखेरीस बंगालच्या उपसागरातून आलेल्या एका कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भ, राज्याच्या उत्तर भागातील काही क्षेत्रे तसेच मुंबईसह कोकणात परिस्थिती काहीशी सुधारण झाली. मात्र, त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पाऊस जणू काही गायबच झाला आणि अनेक भागांत सप्टेंबरमध्येही अशीच परिस्थिती कायम राहिली. अगदी शेवटच्या टप्पात काही भागांत वादळी पाऊस झाला, तर एका कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पूर्व विदर्भाला काहीसा दिलासा मिळाला. परंतु, सुमारे २६ सप्टेंबरपासून पावसाने पुन्हा पाठ फिरवली. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, मान्सूनने अधिकृतपणे राज्यातून माघार घेतलेली नसली, तरी प्रत्यक्षात त्याने महाराष्ट्रातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे.

यंदाच्या मान्सूनची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पावसाचे दिवस कमी होणे आणि दीर्घ कोरडे कालखंड. जून ते सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्रात सरासरी केवळ ४० दिवस पाऊस झाला आणि राज्याच्या जवळपास ९३ टक्के क्षेत्रात पावसाचे दिवस सरासरीपेक्षा कमी राहिले. हवामान विभागानुसार एका दिवसात किमान २.५ मिमी पाऊस झाला तर तो 'पावसाचा दिवस' मानला



जातो. मागील काही एल निनो वर्षांशी तुलना केली तर २०२३ मध्ये सुमारे ४६, २०१८ मध्ये ४४, तर २००२ मध्ये ४१ पावसाचे दिवस होते. यंदा मात्र अनेक भागांत दीर्घ कोरडे कालखंड पाहायला मिळाले. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत सलग सुमारे ५९ दिवस दरोज २.५ मिमीपेक्षा कमी पाऊस झाला. २०२३ मध्ये हा कालावधी ५६ दिवस, २०१८ मध्ये ६५ दिवस, तर १९७२ मध्ये तब्बल ७८ दिवस होता. म्हणून यंदाची परिस्थिती १९७२ सारखी आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. या वर्षी महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा सुमारे ३७ टक्के कमी पाऊस झाला होता. यंदाची तूट त्यापेक्षा कमी आहे. मात्र २०१५ नंतर प्रथमच राज्यात इतकी मोठी पावसाची तूट आणि दीर्घ कोरडे कालखंड दिसत आहेत. यंदा बंगालच्या उपसागरातून निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या प्रणालींचा अपेक्षित फायदा अनेक भागांना झाला नाही आणि त्यामुळे विदर्भासह राज्यातील इतर भागांमध्येही पावसाची कमतरता राहिली.

महाराष्ट्रासाठी मान्सून हा पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. मान्सूननंतर बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारी चक्रीवादळे, उत्तर भारतात येणारे पश्चिमी विक्षोभ (हीरश्शेख्ल ऋश्३४ह्लह्वे) आणि इतर वादळी पावसाच्या घटना हे पाण्याचे दुय्यम स्रोत आहेत. म्हणजेच, मान्सून राज्यातून माघार घेतल्यानंतर साधारणपणे महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि सर्वदूर पाऊस पडत नाही की ज्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकेल. अर्थात, याला काही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, २०२५ च्या मे महिन्यात झालेला मुबलक पाऊस किंवा २०१३ ते २०१५ या कालावधीत उन्हाळ्यात झालेला वादळी पाऊस. मात्र, ऑक्टोबरपासून पुढील वर्षीच्या जूनपर्यंत आणि पावसाच्या घटना किती आणि कुठे घडतील, हे सध्या सांगणे शक्य नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत दुष्काळाचा सामना करण्याची तयारी करण्याशिवाय दुसरा ठोस पर्याय दिसत नाही.

अन्वयार्थ
हेही नसे थोडके!

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी उड्डाण करणाऱ्या विमानांची संख्या कमी करण्याच्या योजनेला सध्या तरी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने स्थगिती दिली आहे. येत्या २६ ऑक्टोबरपासून ही संख्या कमी करण्याचे नियोजित होते. यापायी मुंबईतून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या ३३ टक्क्यांनी कमी होणार होती. विमान कंपन्यांनी याला केलेल्या विरोधाची केंद्राने दखल घेतली, हे बरे केले.

मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन अदानी एअरपोर्ट्स होल्डिंग्ज लिमिटेड ही कंपनी करते. या विमानतळावरील 'टर्मिनल १'वर सध्या टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकासाचे काम सुरू करायचे आहे. त्यात 'टर्मिनल १ बी' या विभागातील उत्तरेकडील काही बांधकाम पाडून तो भाग पुनर्विकसित करायचा आहे. या भागात उभ्या राहणाऱ्या विमानांतून ०० वर्षाला ५० लाख प्रवासी देशांतर्गत प्रवास करतात. ही संख्या 'टर्मिनल १'वरील एकूण प्रवासी संख्येच्या एक तृतीयांश इतकी आहे. आता हाच भाग कामासाठी बंद होणार म्हटल्यावर येथून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची आणि त्यांना नेणाऱ्या विमानांची दुसरीकडे सोय करणे आले. तो करण्यासाठी 'टर्मिनल २'वरील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये कपात करायची, असे हे नियोजन.

आता हे कसे साधावे? तर, त्यासाठी कंपनीने योजना केली, की 'टर्मिनल २'वरून आठवड्याला होणाऱ्या ७७० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांपैकी २६५ येत्या २६ ऑक्टोबरपासून रद्द करून टाकायची. कशी? तर, विमान कंपन्यांनी स्वेच्छेनेच कोणती उड्डाणे रद्द करायची, ते ठरवावे, अशी कंपनीची सूचना. पण, त्यांनी तसे ६ ऑक्टोबरपर्यंत न केल्यास कंपनीच ते उपलब्ध वेळांप्रमाणे करून टाकेल, असा त्यात इशारादही. जी २६५ उड्डाणे रद्द होणे प्रस्तावित होते, त्यात सर्वाधिक फटका बसणार होता, तो इंडिगो (७४), एअर इंडिया (३३), अकासा एअर (११) आणि एमिरेट्स या ऐतिहाद एअरवेज (प्रत्येकी १०) आदींना. विमान कंपन्यांनी साहजिकच याला विरोध केला.

विरोधाचे दोन प्रमुख मुद्दे. एक म्हणजे विमान संचालनात हे सगळे असे इतक्या झटपट करणे व्यावसायिकदृष्ट्या गैरसोयीचे. एवढ्या मोठ्या संख्येने उड्डाणे कमी करणे याचा आर्थिक फटका मोठा बसणार हे साहजिकच. दुसरा मुद्दा तांत्रिक आणि उड्डाणांच्या स्थलांतराशी निगडित. तो म्हणजे मुंबईतील बरीचशी उड्डाणे नवी मुंबईच्या नव्या विमानतळावर हलविणे. 'टर्मिनल १'वरील देशांतर्गत उड्डाणे 'टर्मिनल २'वरून करायची आणि त्या बदल्यात 'टर्मिनल २'वरून सध्या होणारी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे नवी मुंबईला न्यायची, अशी खरी विस्तृत योजना.

विमान कंपन्या या बदलाला सहजासहजी राजी नाहीत. कारण, तसे करण्यापूर्वी नवी मुंबई विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांकरिता आवश्यक मालवाहतूक सुविधा, विमानांचे तंदुरुस्ती परीक्षण, विमान कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था, विमानतळापर्यंतची रस्ते वा अन्य मार्गांनी जोडणी, सुरक्षा तपासणी, सामान हाताळणी आणि अन्य अनेक प्रवासी सुविधा पूर्वविण्याबाबतच्या क्षमतांची नीट चाचपणी करावी लागेल.

दुसरा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी मुंबई विमानतळ जितके सोयीचे आहे, तितके नवी मुंबईतील विमानतळ प्रवाशांना सोयीचे पडेल का, हा. हे दोन्ही मुद्दे थेट विमान कंपन्यांच्या व्यवसायाशी, पर्यायाने आर्थिक बाबींशी निगडित असल्याने विमान कंपन्यांचा घाईने स्थलांतर करण्याला विरोध साहजिकच. किंबहुना इंटरनॅशनल एअर ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनने (आयएटीए) सक्तीने स्थलांतर न होता, चर्चेतून राजीखुशीने व्हावे, अशीच भूमिका मांडली आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने या प्रश्नात लक्ष घालणे स्वागतार्ह ठरते. त्यामुळे अदानी एअरपोर्ट्सला आता नवी सुधारित योजना राबविण्यापूर्वी ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (बीसीएएस), नागरी विमान वाहतूक संचालनालय (डीजीसीए) आणि राज्य सरकारशी संबंधित परवानग्या घ्याव्या लागतील.

मंत्रालयाने लक्ष घातल्याने या प्रश्नावर तोडगा काढून नवी सुधारित योजना तयार करण्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत आहे. या अवधीत अदानी एअरपोर्ट्स कंपनी, विमान कंपन्या आणि अन्य भागधारकांनी एकत्र चर्चा करून 'सर्वांना संमत होईल' अशी स्थलांतर योजना तयार करावी, असे मंत्रालयाने म्हटले. 'टर्मिनल १'च्या पुनर्विकासाच्या योजनेबाबत अदानी एअरपोर्ट्सने योजना सादर करावी, असेही मंत्रालयाने नमूद केले. बाकी काही असो, यानिमित्ताने केंद्रीय मंत्रालय तरी चर्चेने मार्ग काढावे, असे किमान म्हणते आहे, हेही नसे थोडके.

फ्रान्समधील विद्यार्थी का संतापले? निदर्शनांचे काय परिणाम होतील?

फ्रान्समधील विद्यार्थी निदर्शने का करत आहेत?

गेल्या काही दशकांमध्ये न दिसलेली विद्यार्थ्यांची निदर्शने सध्या पॅरिसच्या काही उपनगरांमध्ये सुरू आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील शिक्षणाची स्थिती आणि अस्थिर भवितव्याची चिंता यातून विद्यार्थी संतप्त झाल्याचे मानले जात आहे. सध्या तेथील शालेय विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षकांची कमतरता, वर्गांमधील विद्यार्थ्यांची गर्दी आणि शाळांमधील कमी दर्जाच्या पायाभूत सुविधा या प्रमुख समस्या आहेत. फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद झाल्यामुळे या समस्या उद्भवत असल्याचे दिसते. परिणामी अनेक हायस्कूलमध्ये एकेका वर्गात सध्या ४० विद्यार्थी असल्याची तक्रार केली जात आहे. आधी ही संख्या ३० पर्यंत असे. भारतात ही संख्या सामान्य मानली जात असली तरी कमी लोकसंख्येच्या फ्रान्ससारख्या देशामध्ये ही आकडा खूप मोठा आहे.

अन्य तक्रारी कोणत्या?

फ्रान्समधील हायस्कूल खूप वेळ चालतअसल्याचे दिसत आहे. काही शाळांचे नियमित कामकाज सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच म्हणजे नऊ तास इतके चालते. इतका वेळ शाळेत घालवण्याची किशोरवयीन विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे का हा बाब विचारात घेतल्याचे दिसत नाही. याशिवाय, शाळांमध्ये पुरेशा वैद्यकीय सोयी नसल्याचा मुद्दा आहे. अपल्याबाबत भेदभाव होत असल्याचाही निम्न आर्थिक परिस्थितीमधील विद्यार्थ्यांचा दावा आहे.

ही निदर्शने कशी सुरू झाली?

पॅरिसच्या क्रेतेई या उपनगरामध्ये २१ सप्टेंबर रोजी एका हायस्कूलमध्ये शिक्षकांची संख्या वाढवण्याच्या मागणीवरून उत्स्फूर्त निदर्शने सुरू झाली. त्याआधी १७ सप्टेंबर रोजी क्रेतेईमधील सेंट-एक्सपेरी हायस्कूलच्या शिक्षकांनी कमी कर्मचारी संख्या आणि अपुरी संसाधने



याविरोधात निदर्शने केली. त्यामध्ये विद्यार्थीही सहभागी झाले. या निदर्शनांचे लोण आधी आजूबाजूच्या परिसरांमध्ये आणि नंतर संपूर्ण फ्रान्समध्ये पसरले. या निदर्शनांचा भडका १० दिवसांनंतर आणखी वाढला. १ ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थ्यांनी बंद पुकारला, त्यामध्ये देशातील ३,६०० हायस्कूलपैकी जवळपास ३० टक्के शाळा सहभागी झाल्या. त्यानंतर दर दिवशी वाढत्या संख्येने शाळांमध्ये निदर्शने वाढू लागली. लहान-मोठ्या शहरांमध्ये हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी त्यांना शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा मिळाला. एकट्या पॅरिसमधील १६० हायस्कूल सोमवारी ५ ऑक्टोबर रोजी बंद होती. आकडेवारीत सांगायचे तर त्या भागातील एक

विश्लेषण
निमा पाटील
nima.patil@expressindia.com

आपल्या देशात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू असतानाच फ्रान्समधूनही अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या बातम्या येत आहेत. फरक इतकाच की आपल्याकडील आंदोलने जेन-झींनी हातात घेतली आहेत, तर फ्रान्समध्ये जेन-अल्फा रस्त्यावर उतरली आहे.

तृतीयांश शाळा बंद राहिल्या. तर संपूर्ण देशातील ४०० ते ५०० शाळांवर बंदचा प्रभाव जाणवल्याचे शैक्षणिकमंत्री एडुआर्ड जेफ्रे यांनी मान्य केले, पण हळूहळू शाळा पूर्ववत होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

निदर्शनांदरम्यान काय घडले?

सोमवारी झालेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. विद्यार्थ्यांनी शाळा बंद केल्या. कचऱ्याचे डबे पेटवून दिले आणि काही ठिकाणी शाळांचे फर्निचर, दरवाजे आणि खिडक्यांचीही तोडफोड करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ४० शाळांमध्ये या प्रकारच्या घटना घडल्या. त्यामध्ये जवळपास ३० लाख युरोंचे (३२.५ कोटी रुपये) नुकसान झाले. यादरम्यान विद्यार्थ्यांचा पोलिसांशी संघर्ष झाला. विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि रबरी गोळ्याही चालवल्या. या संघर्षात विद्यार्थ्यांसह हायस्कूलचे ४० मुख्याध्यापक आणि अन्य २५ कर्मचारी जखमी झाले, अशी माहिती शैक्षणिक मंत्रालयाने दिली. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारपासून चार हजार लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

ही निदर्शने ऐतिहासिक का मानली जात आहेत?

या निदर्शनांचे स्वरूप आणि व्याप्ती, दोन्ही पाहता, ही देशातील किशोरवयीन मुलांच्या सर्वात मोठ्या चळवळींपैकी एक ठरू पाहत आहे. येत्या काही काळात हे प्रमाण आणखी वाढू शकते आणि त्यामुळे फ्रान्सला एखादी ऐतिहासिक चळवळ पाहावला मिळेल. या संकटावर उपाय करण्यासाठी कठोर प्रयत्न करावे लागतील असा अंदाज एसएनईएस-एफएसयू या फ्रान्समधील शिक्षक संघटनेच्या प्रमुख सोफी व्हेनेटिटे यांनी व्यक्त केला आहे. फ्रान्सचे अधिकारीही अशा निदर्शनांसाठी पुरेशा तयारीत नसल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

राजकीय प्रतिसाद कसा?

या आंदोलनांतील विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी हिंसाचार खपवून घेणार नाही, ही अपेक्षित भूमिका सरकारने घेतली आहे. तर पोलिसांनी बळाचा अतिरिक्त वापर केल्याचा विद्यार्थी आरोप करत आहेत. फ्रान्समध्ये पुढील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत. अशा वेळी राजकीय नेत्यांनी या निदर्शनांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा या निदर्शनांना राजकीय वळण न मिळणे हे अशक्य होते. त्यामुळार शिक्षणमंत्री जेफ्रे यांनी आता हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभिप्राय उपक्रमाची घोषणा केली आहे. हा विद्यार्थ्यांची नाराजी जाणून घेण्याचा आणि कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. त्याबरोबरच तातडीने शिक्षकभरती सुरू करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

दैनिक जागरण

आत्मज्ञान ही नैतिक द्वंद्वों से मुक्ति दिलाता है

साकार हो रहे नव-निर्माण के सपने



श्री माता अमृतानंदमयी देवी

यह देखकर मन अत्यंत आनंदित होता है कि विगत एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन के कितने ही विविध आयामों को छुआ है



अवधेश राजपूत

मोदी शासन के 25 वर्ष

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रशासनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का संकल्प व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि वे विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे, वह एक कठिन लक्ष्य अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इसका कारण यह है कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस राज्य की तस्वीर बदलने में ऐसी सफलता प्राप्त की कि उनके गुजरात माडल ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसी कारण वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने मनमोहन सरकार की नीतिगत पंगुता से उपजे निराशाजनक माहौल को दूर किया और शासन के तौर-तरीके में खूबियां बदलाव लाए। अपने 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि उसकी कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। उन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक एक साथ कई मोर्चों पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और देश को प्रगति पथ पर तेजी के साथ अग्रसर किया। उनकी जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं के चलते आज देश की भी तस्वीर बदल चुकी है। यह संभव हुआ उनकी प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति और साहसिक फैसले लेने की क्षमता के कारण। उनकी कार्यशैली ने देश के साथ दुनिया का भी ध्यान अपनी ओर खींचा तो इसीलिए कि उन्होंने अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से अमल में लाकर किसी न किसी रूप में हर भारतीय के जीवन को प्रभावित किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी विदेश नीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का मान भी बढ़ाया। इसी कारण वे पिछले एक दशक से अधिक समय से विश्व के लोकप्रिय शासकों में शीर्ष पर अपना स्थान बनाए हुए हैं।

इतने लंबे समय तक किसी शासक का देश-विदेश में लोकप्रिय बने रहना अपने आप में एक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लिए गए ऐसे फैसलों की एक लंबी सूची है, जिन्होंने उन्हें एक सक्षम शासक के रूप में स्थापित करने के साथ ही वह भी सिद्ध किया कि वे कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना और उनसे पार पाना जानते हैं। उनके शासन की एक विशेषता यह भी रही कि उन्होंने देश के स्वाभिमान और संस्कृति को भी शिखर पर ले जाने का काम किया, लेकिन अब जब वे विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं, तब यह भी ध्यान रखना होगा कि इस लक्ष्य के सामने कुछ बाधाएं हैं। इनसे पार पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि देश की नौकरशाही अपना रवैया बदले। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि तमाम प्रगति और परिवर्तन के बावजूद कुछ मामलों में भारत अभी कुछ प्रमुख विकासशील देशों जैसा भी नहीं बन पाया है। इसके कारणों को पहचान कर उनका सही तरह निवारण करना मोदी शासन की पहली प्राथमिकता बननी चाहिए।

जवाबदेही तय हो

अपनी शिकायतों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में किसी प्रभावित का बार-बार आना प्रशासनिक कामकाज की स्थिति को असहज करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में आने के बाद भी सुनवाई की गति मंथर हो, तो ऐसी पहल का उद्देश्य प्रभावित होता है। ताजा प्रसंग मुख्यमंत्री के उस निर्देश से जुड़ा है, जिसमें उन्हें यह कहना पड़ा कि जनता दर्शन में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों का निस्तारण बस औपचारिकता भर न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जवाबदेही का ही संदेश दिया है। आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों की सुनवाई के प्रति प्रशासनिक तंत्र संवेदी और तत्पर हो। समयबद्ध समाधान मिलने से जिला या तहसील स्तर की शिकायतें मुख्यालय तक नहीं आएंगी। पीड़ित को संतुष्टि तभी होगी, जब समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण प्रशासन स्तर पर हो। आवश्यक है कि कामकाज में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर उन पर कार्रवाई हो। शिकायतों की नियमित निगरानी हो और कार्रवाई का परिणाम फरियादी तक पहुंचे। शिकायतों के पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण से शासन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता है और वे लोग हतोत्साहित होते हैं, जो आडंबर दबंगई की चेष्टा करते हैं। शिकायतों के समयबद्ध समाधान से कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ठीक बनी रहती है। इसलिए जनता दर्शन तभी सार्थक होगा, जब वहां पहुंचने वाले व्यक्ति को आश्वासन नहीं, न्याय और वास्तविक राहत मिले।

अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ नेता ही राष्ट्र और उसकी जनता का मार्गदर्शन अपनी पारंपरिक जड़ों से विमुख हुए बिना कर पाता है। ऐसा नेतृत्व यह भलीभांति समझता है कि देश की समृद्धि के लिए उसकी पुरातन संस्कृति का संरक्षण कितना आवश्यक है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भौतिक समृद्धि और देश की समृद्ध विरासत के बीच संतुलन साधने की है। प्रधानमंत्री मोदी यही सिद्ध करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके लिए भारत केवल भूमि का कोई टुकड़ा मात्र नहीं है। यह उनके विचारों में है और वे इसी के लिए जीते हैं।

मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले से जानने के कारण मैं यह कह सकती हूं कि समाज सुधार पर उनका बल, राष्ट्र के प्रति उनके उस प्रेम से जुड़ा है, जो सदैव एक तेज ज्योति की तरह जलता रहा है। इसके बाद उन्होंने जो भी दायित्व संभाला, वह ज्वाला और अधिक प्रखर ही हुई है। उन्होंने केवल भारत माता की सेवा ही नहीं की है, अपितु अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। दिन-रात, बिना थके और बिना रुके, वे हमारे राष्ट्र की भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक जागृति के लिए अनवरत परिश्रम कर रहे हैं।

दशकों से मैंने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा है, जो अधिक स्वच्छ हो, अधिक करुणामय हो और धर्म की जड़ों के साथ गहराई से जुड़ा हो। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशभर में जो परिवर्तन आकार ले रहे हैं, वे उन्हीं संकल्पों और दृष्टियों का ही प्रतिबिंब हैं, जिन्हें मैंने लंबे समय से संजो रखा था। यह बदलाव हमारे गांवों से अधिक स्पष्ट कहीं और दिखाई नहीं देता। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। बहुत कुछ बदला है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

मेरा जन्म और पालन-पोषण एक छोटे से तटीय गांव में हुआ, जहां के परिवार पूरी तरह से समुद्र और मछलियों को पकड़ने पर निर्भर थे। एक छोटी बच्ची के रूप में भी मैंने अपने आसपास के लोगों के कष्टों को बहुत निकट से देखा। उन आरंभिक अनुभवों ने मेरे भीतर निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने और सभी के प्रति करुणा भाव रखने की गहरी अभिलाषा को जन्म दिया। मेरी समझ के अनुसार अनासक्ति ही निःस्वार्थता की आधारशिला है। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी में यह गुण नैसर्गिक रूप से विद्यमान है और यही उन्हें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है।

विगत 35 वर्षों में मैंने पश्चिमी देशों का व्यापक भ्रमण किया है। वहां के अनुभव से यह आकांक्षा जगी कि हमारी सड़कें और नदियां भी उतनी ही स्वच्छ हों और जहां लोग सार्वजनिक स्थलों को साफ-सुथरा रखने में गर्व का अनुभव करें। हम अपने मंदिर परिसरों को तो स्वच्छ रखते हैं, किंतु ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए इस धरा का प्रत्येक इंच ईश्वर का ही स्वरूप है और उसी आदर एवं देखभाल का अधिकारी है। मेरी यह चिर अभिलाषा रही है कि यह चेतना हमारे विद्यालयों से ही आरंभ हो। मुझे इसका अपार हर्ष है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता के इस महायज्ञ को देश के कोने-कोने तक ले जा रहे हैं।

मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूं, जहां बेटियों को बोझ समझने के बजाय लक्ष्मी के रूप में देखा और स्वीकारा जाए। मैं एक ऐसे देश का स्वप्न देखती हूं, जहां प्रत्येक स्त्री किसी भी सड़क पर, किसी भी समय, बिना किसी भय के चल सके और जहां राष्ट्र-निर्माण में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हों। जब महिलाएं नेतृत्व करने और प्रबंधन संभालने के लिए आगे आएं, तो पुरुषों को केवल उनके लिए मार्ग ही प्रशस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके मार्ग में अनावश्यक बाधाएं डालने से भी बचना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच वास्तविक समता और समानता स्थापित होनी चाहिए। इस दिशा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

युवा पीढ़ी के नशे के दलदल में भटकने को लेकर मैं लंबे समय से अत्यंत चिंतित रही हूं-चाहे वह मादक द्रव्यों और मदिरा का नशा हो या फिर आधुनिक गैजेट्स का। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त युवा अभियान के माध्यम से इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। मैं एक ऐसे भारत का स्वप्न देखती हूं, जहां गाय, वन्यजीव, वन, पर्वत और हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रेमपूर्वक संरक्षण हो। पीएम मोदी ने इन विषयों पर भी ध्यान देते हुए हमारी प्राकृतिक विरासत, वन्यजीवों तथा हमारी देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किया है।

प्रधानमंत्री को राम राज्य के आदर्शों को स्थापित करते देखना अत्यंत हृदयस्पर्शी है। इस आदर्श की भी प्रभु भावना उन प्रश्नों में समाहित है, जो प्रभु श्रीराम ने भरत से राज्य की स्थिति के विषय में पूछे थे: क्या किसान प्रोत्साहित हैं? क्या नदियां, गोवंश और वन सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं और बच्चे भयमुक्त एवं सुरक्षित हैं? इन सबके मूल में मेरा एक अटूट आत्मीय विश्वास निहित है कि स्थायी सुधार केवल कानूनों से नहीं, बल्कि परिवर्तित हृदयों से आता है। प्रत्येक नागरिक को 'अपने में स्वयं दीप प्रज्वलित करना होगा।' इसके लिए सच्चे मानवीय प्रयास और ईश्वरीय कृपा-दोनों की आवश्यकता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत एक बार पुनः विश्व-गुरु और विश्व-मित्र के रूप में प्रतिष्ठित हो।

यह देखकर मेरा मन अत्यंत आनंदित होता है कि विगत एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन के कितने विविध आयामों को छुआ है। उनके अनवरत प्रयास हमारे राष्ट्र की प्रगति को गति प्रदान कर रहे हैं। मैं उन्हें स्वार्थ-रहित और ऐसे अनासक्त नेता के रूप में देखती हूं, जो केवल एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं-भारत के खोए हुए वैभव को पुनर्स्थापित करना। अंतर्मन से वे एक संन्यासी हैं और कर्म से एक कर्मयोगी तथा समाज सुधारक।

(अम्मा के नाम से लोकप्रिय लेखिका विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक एवं मानवीय मार्गदर्शक हैं)

response@jagran.com

संकट बने दवाओं के मनमाने मूल्य



प्रणव मार्गव

जब दवाएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती हैं तो फिर एमआरपी की मूल्य व्यवस्था क्यों ही बनी हुई है?



उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों गुणवत्तापूर्ण दवाएं। फाइल

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) और सरकारी खरीद मूल्य के बीच बड़े अंतर को अजूबा करार दिया। यह अंतर 10 गुना से भी ज्यादा है। 2,700 रुपये की खुदरा बिक्री मूल्य वाली कैंसर की दवा पर एमआरपी 27,000 रुपये अंकित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसे 'दिन-दहाड़े' डकैती कहा और फिर अगली सुनवाई में इस भारी अंतर को दो टूक शब्दों में 'कत्लेआम' यानी 'सामूहिक-संहार' तक कहने में संकोच नहीं किया। दवा कारोबारी, निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद करने वाले जिम्मेदारों के लिए इससे तीखी टिप्पणी और कोई हो नहीं सकती। अदालत ने यह सवाल भी खड़ा किया कि इतना पैसा कहां जा रहा है और फायदा किसे हो रहा है? यह टिप्पणी सीधे-सीधे फार्मा कंपनियों, निजी अस्पतालों के मालिकों एवं चिकित्सक तथा सरकारी खरीद में लिप्त जिम्मेदारों का संवेदनहीन चेहरा सामने लाती है। यह विडंबना तब है, जब केंद्र सरकार एक दवा, एक मूल्य और एक गुणवत्ता नीति से जुड़ा कानून फरवरी 2025 में पूरे देश में लागू कर चुकी है। इस नियम के तहत दवा विक्रेताओं और ई-फार्मेसी को दवाओं की मूल्य-सूची को सार्वजनिक रूप से दिखाना अनिवार्य है, ताकि रोगियों को तय दामों पर ही उचित गुणवत्ता की मानक दवाएं मिल सकें, परंतु शीर्ष न्यायालय की इस तीखी प्रतिक्रिया से साफ है कि दवा विक्रेताओं और सरकारी दवा खरीद से जुड़े अधिकारियों ने इस कानून को बटोरे खाते में डाल दिया है।

अधिकांश कारपोरेट अस्पताल अब सेवा नहीं उद्योग बन गए हैं। ये अस्पताल के भीतर स्थित मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यदि कोई रोगी बाहर से दवा लाने की कहता है तो उपचार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने की बात कहते हैं। जबकि इनमें से ज्यादातर अस्पताल आयुष्मान भारत और अन्य सरकारी लाभदायी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी उपचार करते हैं यानी दवा उत्पादकों और अस्पतालों की मनमानी कानून अस्तित्व में आने के बाद भी बनी हुई है।

कुछ समय पहले कंपनी मामलों के मंत्रालय की एक सर्वे रिपोर्ट ने सरकार को आगाह किया था कि दवाएं आम आदमी की पहुंच से जानबूझकर बाहर की जा रही हैं। इस रिपोर्ट ने बताया था कि दवाओं की महंगाई का कारण दवा में लगने वाली सामग्री का महंगा होना नहीं है, बल्कि दवा कंपनियों के मुनाफे का लालच है। इस लालच के चलते कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के नियमों का भी पालन नहीं करती हैं और दवाओं की कीमत कई गुना तक अधिक रख देती हैं। यहां तक कि नामी-गिरामी दवा कंपनियां भी दो सौ से पांच सौ गुना ज्यादा कीमत अपने दवा उत्पादों की रख रही हैं। महंगी दवा सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के बूते खपाई जाती हैं। इसके पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी देसी-विदेशी दवा कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इन कंपनियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ तो लिया, लेकिन दवाओं की कीमतों में कटौती नहीं की? यह गोलमाल प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के साथ तो हो ही रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ राजस्व सेंध के रूप में भी हो रहा है। इसे लेकर कैग ने सरकार को दवा मूल्य नियंत्रण अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया था। ऐसे ही सुझावों को मानते हुए सरकार ने देशभर में फैले सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के 1,200 अस्पतालों, 200 जांच केंद्रों, 500 वेलनेस सेंटर और 8,000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों पर एक दवा, एक मूल्य लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। हालांकि इस योजना पर प्रभावी अमल की दृष्टि से सरकार को मजबूत और पारदर्शी नेटवर्क बनाना होगा, जिसके लिए प्रभावी डाटा भी जरूरी है। दवा वितरण में बोली के आधार पर भागीदारी करने वाले विक्रेताओं की तकनीकी योग्यता से कहीं ज्यादा ईमानदारी के मानदंडों की जरूरत है। दवा क्रय समिति को भी उन दवाओं को खरीदने की जरूरत है, जो उपचार में प्रभावी और कीमत में सस्ती हों, क्योंकि अंततः सरकार का उद्देश्य आम आदमी को सस्ती, असरकारी और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना ही है।

चूंकि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उन्हें भी यदि इस योजना में भागीदार बनाया जाए तो दवा वितरण के साथ ही लाभार्थी रोगियों का दायरा भी बढ़ जाएगा। चिकित्सा का व्यवसाय जीवन रक्षा का पेशा है। वह मनुष्यता की संवेदना की सुरक्षा का नैतिक व्यवसाय है। लाचार मरीज चिकित्सक के पास स्वास्थ्य लाभ लेने की उम्मीद से जाता है, न कि दवा उद्योग के लालच की बढ़ाने की दृष्टि से? किंतु पैसा कमाने की अनैतिक होड़ का ही परिणाम है कि रोगी अब चिकित्सक को धरती का भगवान मानने से हिचक रहा है। इस अविश्वास के चलते ही अस्पतालों में चिकित्सक और रोगियों के परिजनों के बीच निरंतर मारपीट और ज्यादा धन वसूलने के विवाद सामने आ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शीर्ष न्यायालय की डकैती और सामूहिक संहार जैसी टिप्पणियों को बेवजह की प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिचय से मुक्ति

मनुष्य अपने जीवन का जितना बड़ा भाग संसार को समझने में लगाता है, उससे कहीं अधिक संसार को यह समझाने में लगा देता है कि वह क्या है? उसे अपनी अच्छाइयों का गुणगान चाहिए, अपने दुखों की मान्यता चाहिए, अपने साथ हुए अन्याय की कोई ऐसी सार्वजनिक स्वीकृति चाहिए, जिससे उसे यह विश्वास हो सके कि उसके अस्तित्व में पर्वत सी गुरुता है। वह कहता है कि मैं ऐसा इसलिए हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं इतना कठोर इसलिए हूं, क्योंकि मुझे बहुत चोट मिली। मैं इतना मौन इसलिए हूं, क्योंकि मुझे कभी समझा नहीं गया। जबकि सत्य यह है कि आत्मज्ञान का अर्थ अपनी निर्मिति की उस कथा से ही मुक्त हो जाना है, जिसे हम जीवन भर अपना परिचय समझते रहे। नदी की धारा के किनारे खड़े होने पर पता चलता है कि कितना जल बह गया और वह वापस नहीं आएगा, परंतु वैसा ही जल आता रहेगा। किंतु जब मनुष्य अपने पुण्य का लेखा रखने को निष्प्रयोज्य समझने लगे, अपने दुखों को अपनी पहचान बनाना छोड़ दे, अपने त्याग को स्मारक की तरह होना बंद कर दे, तब जीवन की घटनाएं स्वाभाविक रूप से लहर की भांति टकराती हैं, ज्वार की तरह बिखलित नहीं करतीं।

आत्मज्ञान का पहला संकेत यह है कि मनुष्य को अपने बारे में कितना कम सिद्ध करना पड़ता है। जिस दिन भीतर का मन दूसरों से यह सुनने के लिए व्याकुल नहीं रहता कि "तुम सही थे", उसी दिन उसके भीतर किसी गहरी स्वतंत्रता का जन्म होता है। जिस दिन वह अपने दुख को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण, अपने त्याग को अपनी महानता का प्रमाण और अपनी चुप्पी को अपने महान चरित्र का प्रमाण बनाकर प्रस्तुत करना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर "मैं" की वह कठोर परत थोड़ी पारदर्शी होने लगती है, जिसके पीछे अब तक वह स्वयं को भी ठीक से देख नहीं पाया था।

एविकल तोमर सिंह

संस्कारों की नई पौध को सींचने का प्रयास

डा. वेद प्रकाश टंडन

बच्चों में संस्कार और जीवन-मूल्यों की सीख देने का माध्यम भी बनती है रामलीला

रामलीला भारतीय संस्कृति और परंपरा का ऐसा जीवंत माध्यम है, जो पीढ़ियों को भगवान श्रीराम के आदर्शों और जीवन-मूल्यों से जोड़ता है। इसे परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन द्वारा आयोजित बाल रामलीला बच्चों के लिए मंच, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। बाल कलाकार जब राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जैसे पात्रों की भूमिका निभाते हैं तो वह केवल अभिनय नहीं होता, बल्कि उनके भीतर सत्य, त्याग, अनुशासन, कर्तव्य और मर्यादा जैसे मूल्यों को समझने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। यही बाल रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता है। वर्तमान में बच्चों का जीवन तकनीक और डिजिटल माध्यमों से तेजी से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना महत्वपूर्ण हो जाता है।

बाल रामलीला का प्रभाव केवल सांस्कृतिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहता। मंच पर संवाद बोलना, अभिनय करना, समूह के साथ अभ्यास करना और निर्धारित भूमिका को जिम्मेदारी से निभाना बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन बढ़ाने में सहायक होता है। सामूहिक प्रस्तुति के दौरान बच्चों में सहयोग और नेतृत्व की भावना भी विकसित होती है। अंतरराष्ट्रीय रामलीला से जुड़ी गतिविधियों में बच्चों और विद्यार्थियों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि रामकथा को नई पीढ़ी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बाल रामलीला की खासियत यह है कि इसमें बच्चे केवल दर्शक नहीं रहते, बल्कि स्वयं संस्कृति के वाहक बनते हैं। जब कोई बाल कलाकार राम या हनुमान की भूमिका निभाता है तो वह पात्र के संवाद के साथ उसके चरित्र और मूल्यों को समझने का प्रयास करता है।

किसी भी परंपरा की वास्तविक शक्ति तभी बनी रहती है, जब अगली पीढ़ी उससे जुड़ती है। बाल रामलीला इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चों को रामकथा से जोड़कर उन्हें भारतीय संस्कृतिक विरासत की जानकारी देने के साथ ही उसके मानवीय संदेशों से परिचित कराया जा सकता है। बाल रामलीला के आयोजन की पहल इसी दिशा में एक सांस्कृतिक प्रयास के रूप में सामने आती है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे आयोजनों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़े और रामलीला को उनके लिए सीखने, रचनात्मकता दिखाने तथा अपनी संस्कृति को समझने का माध्यम बनाया जाए। रामलीला का मंच भले ही कुछ घंटों के बाद शांत हो जाए, लेकिन वहां मिले संस्कार बच्चों के जीवन में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यही बाल रामलीला की सार्थकता है।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं)

सभी पहलुओं का रखें ध्यान

'जोर सुधार पर हो' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में यह तो माना गया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में विसंगतियों को भी दूर किया जाना भी उतना ही जरूरी है। व्यापक सुधार इसलिए आवश्यक हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे और न ही उसे किसी अनुचित प्रशासनिक जटिलता का सामना करना पड़े। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एसआइआर को चुनाव आयोग का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार माना है। भारतीय लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने और अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल होने से रोकने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, पुनरीक्षण के लिए तय की गई अत्यधिक कड़ी शर्तें और सीमित समयसीमा पात्र नागरिकों के लिए भारी असुविधा का कारण बन रही हैं। आज भी कई वैध मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, फार्म-6 में किए गए बदलावों को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिना समुचित संसदीय चर्चा, सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान या चुनाव आयुक्तों की पूर्ण सहमति के किए गए बदलाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। चूंकि यह मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए उम्मीद है कि शीर्ष अदालत इन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर न्यायसंगत निर्णय लेगी।

पैथर तेमर, किशनगंज (दिल्ली)

मेलबाक्स

आर्थिकी से जुड़ी चुनौतियां

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक दिलचस्प, लेकिन चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। एक ओर विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में वृद्धि के लिए मजबूर किया है। यानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत है, लेकिन कीमतों का दबाव यह संकेत दे रहा है कि विकास की इस गति को बनाए रखना आसान नहीं होगा। विश्व बैंक की ताजा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी और चालू वित्त वर्ष में भी 7.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है। मजबूत घरेलू मांग, निवेश और निर्यात ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू महंगाई है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 4.82 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 5.95 प्रतिशत रही। ये आंकड़े बताते हैं कि कीमतों का दबाव अब केवल कुछ खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं रह गया है। सात अक्टूबर को आरबीआइ ने रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। यह फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। दूसरी ओर जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत किया गया है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूद स्थिति का सबसे बड़ा विरोधाभास है- वृद्धि के अनुमान में सुधार और महंगाई के अनुमान में भी वृद्धि। आम तौर पर तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मांग बढ़ने पर महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में समस्या पूरी तरह मांग आधारित नहीं है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था में बाहरी झटकों को सहने की क्षमता पहले से अधिक है। चुनौती यह है कि खाद्य और ऊर्जा जैसी आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान केवल मौद्रिक नीति से नहीं हो सकता। सरकार को कृषि आपूर्ति श्रृंखला, भंडारण, परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था पर समानांतर काम करना होगा।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, अई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : (0120)-4615600, E-mail: delhi@mda.jagran.com. R.N.I. No. DELHIN/2017/71721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

आजकल



मनु त्यागी
manu@nda.jagran.com

नारी शक्ति : नए भारत का नया क्षितिज

एशियाई खेल 2026 की खेल पट्टी पर जब भारतीय बेटियां पदक तालिका में तिरंगे को शिखर की ओर ले जा रही थीं, तब वे केवल पदक नहीं जीत रही थीं, समूचे भारतीय समाज को एक युगांतकारी संदेश दे रही थीं। जापान में भारत द्वारा जीते गए 85 पदकों में से आधे से अधिक महिला एथलीटों के शौर्य, एकाग्रता और परिश्रम का परिणाम हैं। भारतीय महिला हाकी टीम ने 44 वर्षों बाद जीता ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हो या तीरंदाजी में बेटियों का अचूक निशाना- ये सभी तथ्य इसके जीवंत प्रमाण हैं कि भारत की बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं



आइची-नागोया एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला हाकी टीम ने हासिल किया स्वर्ण पदक। फाइल

इक्कीसवीं सदी का भारत एक युगांतकारी परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। यह परिवर्तन किसी कूटनीतिक गलियारे, राजनीतिक मंच या केवल आर्थिक आंकड़ों की फाइलों तक सीमित नहीं है, इसकी जीवंत गूंज खेल के मैदानों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों, कारपोरेट जगत और युद्धक विमानों के काकपिट से सुनाई दे रही है। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल 2026 इस बात का साक्षात प्रमाण हैं कि भारत की बेटियां केवल समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को ही नहीं तोड़ रहीं, अपनी प्रतिभा और अदम्य साहस के बल पर वैश्विक पटल पर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रही हैं।

नागोया के खेल मैदानों पर जब-जब भारतीय तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान की धुन गूंजी, तब-तब उसके पीछे भारतीय नारी शक्ति के पसीने, त्याग और संकल्प की एक लंबी गाथा छिपी थी। परंतु, इस स्वर्णिम सफलता का वास्तविक मूल्यांकन केवल खेल के मैदान की सीमाओं के भीतर नहीं किया जा सकता। यह सफलता एक व्यापक सामाजिक चेतना की मांग करती है। जब हम नारी शक्ति के इस वैश्विक उभार को देखते हैं, तो समाज का एक हिस्सा इसे 'स्त्री बनाम पुरुष' के पारंपरिक द्वंद्व या प्रतिद्वंद्विता की दृष्टि से आंकने देखता है। आधुनिक भारत के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यह समझना आवश्यक है कि नारी शक्ति पुरुष की कभी प्रतिद्वंद्वी थी ही नहीं, हर धार्मिक ग्रंथ इसका प्रमाण भी है कि नारी तो पुरुष की सहचरी और पूरक है। समाज रूपी रथ को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों पहियों का एक समान गति, गरिमा और गौरव के साथ चलना अनिवार्य है।

समाधान और आगे की राह : भेदभाव से मुक्त और पूरकता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। लैंगिक समानता की शुरुआत संसद या खेल के मैदानों से नहीं, घर के ड्राइंग रूम और रसोई से होनी चाहिए। बेटों को बचपन से ही यह सिखाना होगा कि बहन या महिला मित्र उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं, उनके सुख-दुख की सहयात्री और पूरक हैं। इसके साथ ही, कार्यस्थलों और खेल अकादमियों में महिलाओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित और संवेदनशील माहौल तैयार करना राज्य और समाज दोनों का प्राथमिक दायित्व है। सरकार की 'खेलो इंडिया' और महिलाओं की उद्यमिता के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं जैसी पहलों को और अधिक विस्तार देना होगा, ताकि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं बिना किसी वित्तीय और सामाजिक बाधा के अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।

इस वैचारिक परिवर्तन के लिए शिक्षा व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। हमारी पाठ्यपुस्तकों में केवल महापुरुषों की ही नहीं, उन वीरांगनाओं और महिला वैज्ञानिकों की कहानियों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आइची-नागोया एशियाई खेल में बेटियों का शानदार प्रदर्शन इस बात का उद्घोष है कि भारत की नारी शक्ति अब अपने अधिकारों के लिए याचक नहीं, अपनी योग्यता के बल पर राष्ट्र की नियति की संचालक बन चुकी है। जब देश की बेटियां बिना किसी भय, भेदभाव और हीनभावना के पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक-दूसरे की पूरक बनकर खड़ी होंगी, तभी भारत सही मायनों में 'विश्वगुरु' और एक सशक्त विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने संकल्प को सिद्ध कर पाएगा। भारत में खिलाड़ियों का एक सच ये भी है। अक्सर होता है, जब भी हमारे देश का कोई भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर पदक जीते, चाहे पुरुष खिलाड़ी हो या महिला। हम इस बात से बेखबरी अक्सर होते हैं कि खेलों से जुड़ी तमाम राष्ट्रीय योजनाओं के बावजूद हमारी खेल व्यवस्था ऐसी ही है कि खेल प्रतिभा को हमारे खेल जगत का सिस्टम तलाशकर अवसर नहीं दे पा रहा। ये प्रतिभाएं जिद्दोजहद करके ही पदकों तक पहुंच रही हैं। इसीलिए आज भी किसी खिलाड़ी के घरवाले गाय-बैल बेच रहे हैं, कोई अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहा है, तो कोई पैसे उधार ले रहा है, ताकि उनके बच्चे खेलों में बने रहें। महिला खिलाड़ियों के लिए खेलों की डगर और भी कठिन है, क्योंकि उन्हें मैदान में खुद को साबित करने के साथ-साथ सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बेटलिफ्टर मीराबाई चानू आज बहुत बड़ी स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उनके लिए भी खेल में बने रहना बड़ी चुनौती थी। नागोया में मीराबाई ने वह पदक भी हासिल किया, जिसकी कमी उन्हें बहुत अखरती थी।

बाक्सर मैरी काम की तरह मीराबाई भी अपनी मां की मदद करने के लिए जंगल से लकड़ियां बटोरती थीं, ताकि उन्हें चूल्हे में जलाकर तेल के कुछ पैसे बचाए जा सकें। कबड्डी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में निकिता की बहुत बड़ी भूमिका रही। हिसार जिले के हसनगढ़ गांव की रहने वाली निकिता के पिता अनिल नयन एक साधारण किसान हैं और उनकी मां विनोद कुमारी घर संभालती हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता-पिता ने उन्हें यह सहारा दिया। जिस हरियाणा से आज देश में सबसे अधिक बेटियां खेल जगत में आगे आ रही हैं। सरकार भी खूब प्रोत्साहित कर रही है, वहां भी वैश्विक पदक तक पहुंचने वाली हर खिलाड़ी की ऐसी ही कहानी है, जिससे अन्य प्रदेशों की स्थिति भी स्वतः स्पष्ट होती है।

अपेक्षाओं का भारीपन और पोडियम का सच

इस बार एशियाई खेल 2026 के समापन के साथ ही भारतीय खेल जगत एक बार फिर आत्ममंथन के मोड़ पर है। इस खेल महाकुंभ में भारत की बेटियों ने जिस असाधारण जज्बे और प्रतिबद्धता का परिचय दिया, वह पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। इस बार भारत की झोली में कुल 85 पदक आए हैं, जिनमें 21 स्वर्ण पदक शामिल हैं। यद्यपि पिछले खेलों के 106 पदकों के ऐतिहासिक शिखर की तुलना में यह संख्या कम हुई है, परंतु कुल स्वर्ण पदकों में से 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी अकेले महिला खिलाड़ियों की है।

इस गौरवशाली सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जो खेल प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को गंभीर चुनौती दे रहा है। आज भारत का खेल बजट अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, 'टाप्स' यानी टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएं सीधे खिलाड़ियों के खातों और विदेशी प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं और खेल विज्ञान का एक व्यापक सहयोगी स्टाफ (मनोवैज्ञानिक, फिजियोलाजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट) हर दल के साथ साए की तरह चल रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जितना भारी बजट और विश्वस्तरीय सुविधाएं देश के खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं, उसके अनुपात में पदकों की कुल संख्या और उनकी चमक (विशेषकर स्वर्ण पदक) में अपेक्षित गुणात्मक उछाल क्यों नहीं आ पा रहा है? आखिर वह कौन सी बुनियादी कमियां हैं जो हमें पोडियम की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचने से रोक रही हैं? वस्तुनिष्ठ और पुष्ट तथ्यों के आधार पर इसका गहराई से विश्लेषण करना अब अनिवार्य हो चुका है।

हांगझाऊ (2023) में भारत को अकेले शूटिंग से सात और एथलेटिक्स से छह स्वर्ण मिले थे। लेकिन नागोया (2026) में शूटिंग का स्वर्ण ग्राफ सिमटकर तीन पर आ गया और 7s से अधिक सदस्यों वाले विशाल एथलेटिक्स दल के बावजूद ट्रैक एंड फील्ड में भारत को केवल एक स्वर्ण पदक (9 रजत, 14 कांस्य के साथ) से संतोष करना पड़ा। इसके विपरीत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे खेल महाशक्तियां तैराकी, जिम्नास्टिक, डाइविंग, टेबल टेनिस और साइकिलिंग खेलों में हमेशा अपना एकछत्र साम्राज्य स्थापित रखते हैं। भारत जब तक इन बहु-पदक वाली स्पर्धाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, तब तक बजट का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा खेलों की सीमित प्रतिभाओं को चमकाने में खर्च होगा।

खेल विज्ञान और मनोवैज्ञानिकों की भारी-भरकम फौज रखने के बावजूद मैदान पर खिलाड़ियों का 'नर्वस ब्रेकडाउन' यह दर्शाता है कि हमारी मानसिक अनुकूलन प्रणालियां अभी भी सतही स्तर पर काम कर रही हैं। करोड़ों रुपये के बजटीय आवंटन के बावजूद भारतीय खेल महासंघों की आंतरिक कार्यप्रणाली आज भी नौकरशाही के पुराने ढर्रे से मुक्त नहीं हो पाई है।

भारत में खेल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल उन चुनिंदा 400-500 एथलीटों पर केंद्रित कर दिया जाता है जो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके हैं। यह नीति तात्कालिक रूप से कुछ पदक तो दिला सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से एक मजबूत खिलाड़ी तैयार करने में विफल रहती है। जब तक कोई खिलाड़ी एलीट श्रेणी में नहीं आता, तब तक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उसे बुनियादी ट्रैक, सही पोषण और स्थानीय स्तर पर योग्य कोच तक नहीं मिलते। खेल अकादमियां और 'खेलो इंडिया' जैसी पहलें सराहनीय हैं, लेकिन राज्यों के स्तर पर बुनियादी खेल ढांचे का अस्मान वितरण आज भी एक कड़वी सच्चाई है। समय आ गया है कि खेल बजट के पाई-पाई के खर्च की जवाबदेही तय की जाए, ताकि निवेश किए गए जनधन का वास्तविक परिणाम देश के गौरव को पदक तालिका में शीर्ष देशों के समकक्ष स्थापित करके मिल सके।

(मनु त्यागी)

खरी-खरी

दिल्ली हिली और वाट्सएप हिला

निर्मल गुप्त

दिल्ली हिली। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर तक सब डगमगाया। पता लगा कि भूकंप आया। यह नहीं मालूम कि यह किसी आंदोलन के चलते आया या नहीं, पर आते ही सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लुटिया छलकी। सब एक-दूसरे से पूछने लगे- क्या हुआ? महसूस किया कुछ? वाट्सएप पर चिंताओं की चीलें चिंघियाने लगीं। फेसबुक गुलजार हो उठा।

भूकंप रात में आया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह भरी दोपहरी में आया होता तो कुछ और बात होती। लंच टाइम के बाद आता तो शहर की महिलाएं टीवी के रिमोट से घरेलू राजनीति के दांव-पेच सीखती मिलतीं- सास ने बहू को कैसे हिलाया। आदमी अपने-अपने दफ्तरों में खाना खा कर ऊंघने के साथ-साथ इसका लुत्फ उठाते।

सबको पता लग गया कि अच्छा समय और भूकंप कभी भी आ सकता है। इसलिए मोबाइल की बैटरी हर समय फुल रखनी चाहिए, ताकि फेसबुक पर स्टेटस फटाफट अपडेट किया जा सके- दिल्ली हिली, पर हम नहीं हिले। लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर धड़ाधड़ स्टेटस लगाए।

ऐसे मौकों के लिए अनमोल वचनों का रेडी स्टाक डेस्कटाप पर हिफाजत से रखा होना जरूरी है। यही मौका होता है जब किसी को भी सराहा या गरियाया जा सकता है। भूकंप आने की भनक मिलते ही कुछ लोगों को तुरंत पता लग गया कि इसमें धार्मिक असहिष्णुता का हाथ है। कुछ ने कहा- ये विकास का भूकंप है। कुछ ने कहा- ये विनाश का भूकंप है।

भूकंप से राजधानी हिली है तो पूरे देश के भीतर वैचारिक स्तर पर कुछ न कुछ विचलन हुआ ही होगा। भूगर्भ शास्त्रियों ने कहा- टेक्टोनिक प्लेटें टकराईं। वाट्सएप शास्त्रियों ने कहा- नहीं, ये टेक्टोनिक नहीं, टेक्टिकल है। किसी ने जानबूझ कर हिलाया है।

सरकार ने कहा- हम स्थिति पर नजर रखे हैं। विपक्ष ने कहा- हम हिलने वालों के साथ हैं। और जनता ने कहा- हमने तो पहले ही कहा था, कुछ तो हिलेगा। दिल्ली हिल कर फिर यथास्थान बैठ गई। वाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी तक रह-रह कर हिल रही है।

ट्विटर पोस्ट

राज्यसभा के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश से जिन चेहरों पर दांव लगाया है, उनमें से हर एक लगातार जनता के बीच रहा, जमीन पर काम किया, लोगों की समस्याओं को करीब से समझा और संगठन के लिए भी पूरी निष्ठा से खड़ा रहा। ऐसे जमीनी और योग्य कार्यकर्ताओं को भी कभी न कभी उस जिम्मेदारी का अवसर मिलना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं।

मीनाक्षी चिरयान@Minakshishriyan



सवाल यह नहीं कि एसआइआर क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि हमारी मतदाता सूची इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि हर पैत्र मतदाता का वोट सुरक्षित रहे और कोई अपात्र नाम लोकतंत्र के जनादेश को प्रभावित न करे? लोकतंत्र में शोर से ज्यादा जरूरी है सही मतदाता, सही सूची और सही प्रक्रिया।

डा. अवनींद्र कुमार राय@avanindra43

दिल्ली पुलिस में दस हजार से ज्यादा महिलाएं हैं। ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। पिछले कुछ दिनों में रील बनाने वालों की गालिया उन्होंने सुनी हैं। भीड़ की मार खाई और साबित किया है कि वे धैर्य और शौर्य दोनों की स्वामिनी हैं। ड्राउज कंट्रोल के लिए वे न्हितली ही उतरीं। राष्ट्र उनका आभारी है।

दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना को नई कप्तान बनाना चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार को शामिल करने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

'सेवा' और 'संकल्प' के बीते वर्ष पचीस,
रहे विपक्षी पर सदा मोदी जी इक्कीस।
मोदी जी इक्कीस मुसीबत कम ना आई,
अटल रहा संकल्प एक भी टिक ना पाई।
एक तरफ 'परिवार' रहा रहे मिलकर मेवा,
मोदी जी बस आए जाहर करते सेवा!

-ओम प्रकाश तिवारी



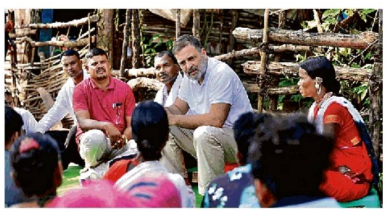
धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

कांग्रेस के लिए आसान नहीं आगे की राह

जो चेहरे आजकल राष्ट्रीय राजनीति की धुरी हैं, उनका मध्य प्रदेश में बार-बार दिखना सहज नहीं, बल्कि कहा जा सकता है कि यह वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बीते एक महीने में दो बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं और अब उज्जैन का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। वहीं भोपाल दौरे के बाद अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ग्वालियर आएंगे। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए संजीवनी के समान है, जबकि 2028 की संभावित चुनावी तस्वीर के मद्देनजर भाजपा के 'चाणक्य' अमित शाह अभी से व्यूह रचना कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ नई दिल्ली में मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन उनकी एक नजर मध्य प्रदेश में संभावनाएं भी टटोल रही है। 19 सितंबर को उन्होंने इंदौर पहुंचकर युवाओं से बात की, वहीं एक अक्टूबर को बालाघाट के उस गांव का दौरा किया, जहां पिछले महीने बच्चों की मौत हुई थी। राहुल के दौरे स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वह 2028 के लिए कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए शिक्षा और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। आदिवासियों की बदहाली को भी मुद्दा बना रहे हैं। उन्हें मध्य प्रदेश से बड़ी उम्मीद होने की वजह वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस का बनवास तोड़कर सत्ता तक पहुंचना और वर्ष 2023 में भाजपा को कड़ी चुनौती देने की कोशिश है। हालांकि वर्ष 2023 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में चले जाने से कमल नाथ सरकार को डेढ़ साल में ही विदा होना पड़ा था और वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना के चलते कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी।



बीते दिनों बालाघाट के एक गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते राहुल गांधी। फाइल

इस पराजय में भी राहुल गांधी यह समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जमीन मौजूद है, केवल उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने पिछली शताब्दी के आठवें दशक से कांग्रेस पर काबिज रहे वरिष्ठ नेताओं को धीरे-धीरे मुख्यधारा से बाहर किया है। इनमें कमल नाथ, दिग्विजय सिंह सहित सत्यव्रत चतुर्वेदी, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी जैसे कई कद्दावर नेता हैं। अब उनकी जगह प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। आदिवासी वर्ग के विक्रांत भूरिया को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इसी समुदाय से आने वाले उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

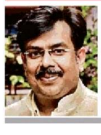
अजय सिंह का विंध्य क्षेत्र में दबदबा है और कांग्रेस उन्हें भरपूर सम्मान भी दे रही है। पुरानी पीढ़ी को विदा कर नई पीढ़ी को मौका देने के प्रयास में कांग्रेस राज्यसभा की अपनी एक सीट भी गंवा चुकी है। दिग्विजय सिंह की खाली सीट पर कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजना चाहा था, लेकिन गलत नामांकन के चलते यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई।

कांग्रेस की इन कोशिशों पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। राहुल गांधी को प्रदेश में अचानक बढ़ी सक्रियता से भाजपा सतर्क है। स्वयं मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव आरोप-प्रत्यारोप का मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है और अगले साल एमपीपीएससी की परीक्षाएं दो बार कराने की घोषणा की है। यह परीक्षा नियमित न होने से युवाओं में खासी नाराजगी थी। वर्षों बाद पदोन्नति मिलने से कर्मचारी खुश हैं। वर्ष 2026 किसान वर्ष घोषित है और फार्मर आइडी से लेकर भावांतर योजना तक मोहन सरकार ने किसानों की तमाम सुविधाएं दी हैं। जहां तक सामान्य वर्ग की लेकर आगे चलने की बात है, डा. मोहन यादव सरकार अपने स्तर पर कई प्रयास कर चुकी है। मोहन यादव स्वयं आदिवासी क्षेत्रों में अपना प्रवास बढ़ा रहे हैं और इस समुदाय के लिए रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं में एक लाख पदों पर भर्ती के लिए भी मोहन यादव काम कर रहे हैं।

इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2028 का विधानसभा चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें भाजपा के पास लाड़ली बहना जैसी कोई योजना नहीं होगी। वहीं कांग्रेस विकास और सुशासन के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के लिए भी अपनी पार्टी में ही गुटबाजी से निपटते हुए जनता के बीच भरोसा जगा पाना आसान नहीं होगा।

मंथन

पूरे होने चाहिए छात्रों के सपने



ब्र. धनंजय गिरि
सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक

यह सही है कि छात्रवृत्ति किसी विद्यार्थी की राह आसान कर सकती है, परंतु शिक्षा व्यवस्था की सफलता तब मानी जाएगी, जब आर्थिक कमजोरी किसी बच्चे के सपनों की सीमा तय न करे

शिक्षा किसी भी समाज और राज्य के भविष्य की बुनियाद होती है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके सपनों को आगे बढ़ाने का माध्यम भी बनती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि पैसों की कमी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करता है। हाल ही में एक छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार हर छात्र को शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक कठिनाई आज भी बड़ी संख्या में परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा जारी रखने में बाधा बन सकती है। फीस, किताबें, यूनिफार्म, परिवहन और अन्य शैक्षणिक खर्चों का बोझ कम होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सकती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाना इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन शिक्षा का सवाल केवल छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं है। किसी बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध कराना, आधुनिक पाठ्यक्रम और तकनीक से जोड़ना, स्कूलों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना और उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों तक उसकी पहुंच बनाना- शिक्षा व्यवस्था की सफलता को इन्हीं व्यापक कसौटियों पर परखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह चुनौती और बड़ी है।

एक ओर महानगरों और बड़े शहरों में आधुनिक शिक्षण संस्थानों का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता पर निरंतर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक सहायता तभी पूरी तरह प्रभावी होगी, जब उसके साथ स्कूलों की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में भी सुधार दिखाई दे। वर्ष 2017 से पहले विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी, भवन जर्जर थे। बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रापआउट रेट 19-20 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने इस समस्या का संज्ञान लिया तो पता चला कि अधिसंख्य बालिकाएं इसलिए स्कूल छोड़ती थीं, क्योंकि वहां टायलेट व पेयजल आदि की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद इसमें सुधार किया गया। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार का यह संदेश कि धन के अभाव में किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकने चाहिए, अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे नीति के स्तर पर आगे बढ़ाते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई बच्चा गरीबी, सामाजिक परिस्थितियों, भौगोलिक दूरी या संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर न हो।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक बाधाओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। कैंट की विधिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में भी डीबीटी और आनलाइन प्रक्रिया के जरिये पारदर्शिता तथा समय पर सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को मिले अधिक अवसर : इस पूरे परिदृश्य में असली सवाल यह नहीं है कि कितनी राशि वितरित हुई, बल्कि यह है कि उस सहायता का असर विद्यार्थियों के भविष्य पर कितना पड़ा। कितने बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी? कितनों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की? कितने उच्च शिक्षा तक पहुंचे? और कितने युवा शिक्षा के बाद रोजगार या उद्यमिता के अवसरों से जुड़ सके? राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के 33,401 पदों पर शिक्षकों की भर्ती पूरी की है। बच्चों की आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 14,429 प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य हो रहा है। सरकार ने समान अवसर की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब इस प्रतिबद्धता की वास्तविक कसौटी यही होगी कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवश्यक संसाधन और आगे बढ़ने का अवसर मिले।

वर्ष 2025 के बजट इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं, जब शिक्षा के लिए कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा दिया गया। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छात्रवृत्ति किसी छात्र की राह आसान कर सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की सफलता तब मानी जाएगी, जब आर्थिक विपन्नता किसी बच्चे के सपनों की सीमा तय नहीं करे। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, फिर भी देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिहाज से यही सबसे बड़ी चुनौती और भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है।



सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी सरकार। फाइल

ओला के राइट्स इश्यू का मूल्य 27 रुपये प्रति शेयर तय

बेंगलुरु : इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के निदेशक मंडल ने प्रस्तावित राइट्स इश्यू के लिए 27 रुपये प्रति शेयर का निर्गम मूल्य तय किया है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से करीब 26 प्रतिशत कम है। राइट्स इश्यू की राशि दो चरणों में चुकानी होगी। निर्गम मूल्य का 60 प्रतिशत आवेदन के समय देना होगा, जबकि बकाया राशि के लिए अंतिम किस्त का भुगतान निदेशक मंडल द्वारा तय तिथि को करना होगा। दो चरणों में भुगतान की व्यवस्था से शेयरधारकों को राशि चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा। (प्रेट)



प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगने वाला समय कम करना जरूरी है। फिलहाल इसमें काफी समय लगता है और स्थानीय स्तर पर विकास बढ़ाने से इसे कम करने में मदद मिलेगी।
– कुणाल बहल, विफाम और बिंदी उपाध्यक्ष, हॉउस कारसं इंडिया

सेंसेक्स	72,638.70 ▼ 429.11	निफ्टी	22,603.05 ▼ 173.05	सोना प्रति दस ग्राम	₹1,48,900 ▼ ₹700	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹2,27,000 बदलाव नहीं	डालर	₹96.75 ▲ ₹0.40	क्रूड प्रति बैरल	$102

रेपो दर में वृद्धि से शेयर बाजार की तेजी थमी, सेंसेक्स 429 अंक गिरा

मुंबई, प्रेट : रेपो रेट में साढ़े तीन साल बाद पहली बार वृद्धि होने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशक धारणा प्रभावित हुई और शेयर बाजार लगातार दो दिन की तेजी के बाद बुधवार को गिरकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 429.11 अंक गिरकर 72,638.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 599.09 अंक गिरकर 72,468.72 अंक पर आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 173.05 अंक की गिरावट के साथ 22,603.05 अंक पर बंद हुआ।

ब्रेंट क्रूड 1.41 प्रतिशत बढ़कर 102 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के सिनर्जी हेड विनोद नायर ने कहा, 'रेपो रेट में बढ़ोतरी उम्मीद के अनुरूप थी, लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव से बाजार पर अधिक असर पड़ा। वृद्धि के अनुमान में बढ़ोतरी से घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत मिला, लेकिन महंगाई के ऊंचे अनुमान और मूल्य स्थिरता पर आरबीआई के जोर ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया।'

- कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशक धारणा प्रभावित हुई
- 173 अंक गिरकर 22,603.05 पर बंद हुआ एनएसई निफ्टी



रुपया 40 पैसे टूटकर 96.75 प्रति डालर पर बंद

मुंबई, प्रेट : आरबीआइ के रेपो रेट में वृद्धि करने के बाद रुपया कुंवार को डालर के मुकाबले 40 पैसे टूटकर 96.75 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.37 प्रति डालर पर खुला। यह 96.34 से 96.84 प्रति डालर के दायरे में कारोबार करने के बाद अंत में 96.75 प्रति डालर पर बंद हुआ। रुपया मंगलवार को 96.35 प्रति डालर पर बंद हुआ था।

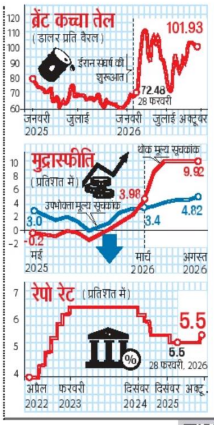


एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, 'आरबीआइ के सख्त रुख वाले बयान के बाद महंगाई की चिंता से बाजार धारणा प्रभावित हुई। रुपया टूटा और उसका बंद भाव अब तक का दूसरा सबसे कमजोर स्तर रहा।'

कर्ज वृद्धि में आ सकती है नरमी : आरबीआइ

मुंबई, प्रेट : आरबीआइ ने बुधवार को कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से बैंकों की ऋण वृद्धि दर मौजूद 18 प्रतिशत से कुछ धीमी हो सकती है, लेकिन इससे व्यापक आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ने की आशंका नहीं है। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि दरों में बढ़ोतरी का असर अंतिम ग्राहक तक पहुंचने में दो तिमाहियों का समय लगता है।

उन्होंने कहा, 'मांग और दर (वृद्धि), दोनों के प्रभाव से कुछ नरमी आएगी। लेकिन ऋण वृद्धि में 18-20 प्रतिशत के स्तर से नरमी आना बुरी नहीं है और यह आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए पूरी तरह पर्याप्त होगी।' स्वामीनाथन ने आगे कहा कि ऋण वृद्धि इस समय 18 प्रतिशत से अधिक है, जबकि इसका 10 साल का औसत 12-14 प्रतिशत रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि औसत दर पर ऋण खातों का विस्तार वित्तीय प्रणाली के लिए टिकाऊ है। आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि ऋण वृद्धि में कुछ प्रतिशत अंक का इधर-उधर होना बहुत अधिक मायने नहीं रखता है। मल्होत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों को निकट भविष्य में दरों में किसी कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।



वित्तीय बाजारों के लिए बनेगी परामर्श समिति

आरबीआइ ने वित्तीय बाजारों के लिए एक तकनीकी परामर्श समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति केंद्रीय बैंक, बाजार प्रतिभागियों और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में काम करेगी। तकनीकी परामर्श समिति की संरचना और उसके कामकाज का दायरा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद सदस्यों का चयन किय जाएगा



बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

रुपये को उसके सही मूल्य तक पहुंचने में मदद करेंगे

मुंबई, प्रेट : आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर फिलहाल कम है और इस तरह के कई आकलन लगाए गए हैं। हालांकि, उन्होंने इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि केंद्रीय बैंक रुपये की 'स्थिर' रखने और उसे उसके 'उचित मूल्य' तक पहुंचाने के लिए समर्थन देगा। मल्होत्रा ने कहा कि छोटी अवधि में बाजार कई बार तर्कसंगत तरीके से व्यवहार नहीं करते, लेकिन लंबी अवधि में बाजार किसी मुद्रा का उचित मूल्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा, 'हम सुनिश्चित करेंगे कि रुपया स्थिर रहे और अपना सही मूल्य तलाशे। हम रुपये को उसके सही मूल्य तक पहुंचने में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेंगे और साथ ही अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकेंगे।' आरबीआइ गवर्नर का यह बयान ऐसे समय आया है जब बुधवार को कारोबार के दौरान रुपया डालर के मुकाबले एक समय अपने अब तक के सबसे निचलेस्तर 96.96 प्रति डालर के करीब पहुंच गया।

टाटा संस पर घूले गए सवाल का नहीं दिया जवाब : मल्होत्रा ने आरबीआइ द्वारा टाटा संस के एनबीएफसी लाइसेंस वापस करने के अनुरोध को खारिज करने और उच्च श्रेणी (अपर लेयर) की एनबीएफसी से जुड़े नियमों के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया।



मामूली शुल्क से यूपीआइ लेन-देन पर नहीं पड़ेगा कोई खास असर

मुंबई, प्रेट : आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि यूपीआइ पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) के रूप में मामूली शुल्क लगाए जाने से यूपीआइ लेनदेन की मात्रा पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'फिलहाल हमें लेनदेन की मात्रा में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि मामूली शुल्क का लेनदेन की मात्रा पर कोई बड़ा असर पड़ेगा।' बता दें कि एनपीसीआइ ने पिछले महीने व्यक्ति से व्यापारियों को होने वाले 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआइ लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने की घोषणा की थी। यह शुल्क व्यापारियों से लिया जाएगा।



अब किसी भी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर से वित्तीय जानकारी साझा कर सकेंगे ग्राहक

आरबीआइ ने वित्तीय जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने और ग्राहकों की सुविधा के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-'अकाउंट एग्रीगेटर' के बीच समन्वय की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। अब ग्राहकों को अपनी वित्तीय जानकारी देखने के लिए अलग-अलग 'अकाउंट एग्रीगेटर' प्लेटफार्म पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी बैंक की जानकारी एक वित्तीय सूचना प्रदाता के पास है और निवेश से जुड़ी जानकारी दूसरे के पास है, तो आप अपनी पसंद के किसी एक एनबीएफसी- 'अकाउंट एग्रीगेटर' से जानकारी हासिल कर सकेंगे। 'अकाउंट एग्रीगेटर' आरबीआइ नियमन के तहत काम करने वाली ऐसी इकाई है, जो ग्राहक की सहमति से विभिन्न संस्थानों के बीच उसकी वित्तीय जानकारी को डिजिटल तरीके से साझा करने की सुविधा देती है।

एक नजर में

बजाज फाइनेंस ने सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाईं

नई दिल्ली: बजाज फाइनेंस लि. ने बुधवार को विभिन्न अवधि की सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में 0.15 प्रतिशत से 0.40 प्रतिशत तक की वृद्धि का ऐलान किया है। नई दरें 12 से 60 महीने की अवधि वाली नई और नवीनीकरण वाली सावधि जमा दोनों पर बुधवार से प्रभावी हो गई हैं। 31 से 60 महीने की अवधि की नई एफडी पर ब्याज दर 0.35 प्रतिशत बढ़ाकर संघयी रूप से 7.75 प्रतिशत सालाना कर दी गई है, जो पहले 7.40 प्रतिशत थी। (प्रेट)

चीनी व्यापारियों के लिए स्टाक सीमा घटाई गई

नई दिल्ली: त्योहारी सत्र में चीनी की खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टाक रखने की सीमा को घटाकर 1,000 क्विंटल कर दिया है। यह आदेश 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। मंगलवार को इस फैसले को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जो 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी। मंत्रालय ने अगस्त में चीनी व्यापारियों पर 4,000 क्विंटल की स्टाक सीमा लगाई थी, जो 30 नवंबर तक लागू थी। साथ ही माल मिलने की तारीख से 30 दिन तक ही स्टाक रखने की अनुमति दी गई थी। (प्रेट)

जियोहाटस्टार ने पश्चिम एशिया में प्रवेश किया

नई दिल्ली: जियोहाटस्टार ने सउदी अरब के साथ साझेदारी में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अपनी शुरुआत करने की घोषणा की है। कंपनी ने पिछले महीने दक्षिण एशियाई प्रवासियों को लक्षित करते हुए ब्रिटेन, कनाडा व सिंगापुर के बाजारों में उतरने की घोषणा की। उत्तरी अफ्रीका के दर्शकों को अब जियोहाटस्टार के नए मूल कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। इन कार्यक्रमों में 10 भाषाओं तक के आडियो ट्रैक, जियोस्टार टीवी पैनलों के टेलीविजन कार्यक्रम, ब्लाकबस्टर फिल्में और देश के कुछ सबसे बड़े रियलिटी कार्यक्रम शामिल होंगे।' (प्रेट)

ब्याज दर वृद्धि का रियल एस्टेट पर नहीं होगा असर

मझोले और बड़े आकार के मकानों की बिक्री प्रभावित होने की आशंका से डेवलपर्स कर रहे इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ की तरफ से रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का असर फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं दिखने जा रहा है। छोटे मकान की बिक्री पर इसका सीमित असर हो सकता है, लेकिन मझोले और बड़े आकार के मकान पर इस बढ़ोतरी से बिक्री प्रभावित होने की आशंका से रियल एस्टेट डेवलपर्स इन्कार कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि आरबीआइ ने वैश्विक हालात को देखते हुए महंगाई रोकने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है। दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत से अधिक कर दिया। रेपो रेट बढ़ने से बैंक भी सभी प्रकार के लोन की ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत या 25 आधार अंक तक का इजाफा करेंगे।

- ब्याज दर बढ़ने से मिड इनकम वाले खरीदारों का उत्साह कुछ समय के लिए हो सकता है कम
- बैंक बोले, आरबीआइ के फैसले के बाद उन्हें नई ब्याज दरों को लागू करने में लगेगा कुछ समय



ब्याज दरों में स्थिरता से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी समर्थन मिलता है। फिलहाल आवासीय मांग मजबूत बनी हुई है। मजबूत खरीदारी धारणा, त्योहारी मांग और मकान की खरीदारी की दीर्घकालिक आवश्यकता को देखते हुए हमारा मानना है कि इस बढ़ोतरी का आवासीय मांग पर सीमित असर होगा। –**प्रवीण जैन,** प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय काउंसिल नरेडको

अर्बन मनी के सह-संस्थापक और चीफ बिजनेस आफिसर अमित प्रकाश सिंह ने बताया कि रेपो रेट में बढ़ोतरी रियल एस्टेट के लिए बाधक की जगह सहायक का काम करेगा क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती कायम रहेगी और मकान की मांग बनी रहेगी। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में मकान की मांग टिकाऊ नहीं रह सकती है। सिग्नेचर ग्लोबल के संस्थापक व चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि मजबूत आधार व आगमी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यह सेक्टर मजबूत बना रहेगा। हालांकि ब्याज दर बढ़ने से मिड इनकम वाले खरीदारों का उत्साह कुछ समय के लिए कम हो सकता है। नवरात्र के बाद ही ब्याज दरों में बैंक बदलाव करेंगे।

बुकिंग और खरीदारी दोनों सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होती है। कई बैंकों ने बुधवार को साफ कर दिया कि आरबीआइ के फैसले के बाद उन्हें अपनी नई ब्याज दरों को लागू करने में कुछ समय लगेगा। उम्मीद की जा रही है नवरात्र के बाद ही ब्याज दरों में बैंक बदलाव करेंगे।

विशेषज्ञ बोले-रेपो रेट में और बढ़ोतरी संभव

नई दिल्ली, प्रेट : विशेषज्ञों ने कहा है कि केंद्रीय बैंक आगामी दिसंबर की नीतिगत समीक्षा में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत तक की एक और बढ़ोतरी कर सकता है। एचडीएफसी बैंक की प्रधान अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता के अनुसार, 'हमारा अनुमान है कि केंद्रीय बैंक अगले कुछ महीनों में कुल मिलाकर दरों में आधा प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत की और बढ़ोतरी कर सकता है। अधिक आक्रामक दर वृद्धि का जोखिम इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पश्चिम एशिया का मौजूदा संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल लंबे समय तक जारी रहता है।' उद्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खाद्य-ईंधन, दोनों मोर्चों पर मौजूदा मुद्रास्फीति के रुझानों ने आरबीआइ पर दबाव डाला है, जिसके चलते उसे दर बढ़ानी पड़ी है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंकों की सूची से हटाया गया

मुंबई, प्रेट : आरबीआइ ने बुधवार को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद होने के बाद उसे मान्यता-प्राप्त अनुसूचित (शेड्यूल) बैंकों की सूची से हटा दिया गया है। आरबीआइ ने अप्रैल में नियमों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया था।

केंद्रीय बैंक ने कहा था कि इस भुगतान बैंक का कामकाज नुकसानदायक ढंग से संचालित किया जा रहा था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को बंद करने का आदेश दिया था। इस संबंध में अधिसूचना 31 जुलाई को जारी हुई थी और सितंबर में इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आरबीआइ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वे मान्यता-प्राप्त बैंक शामिल होते हैं जो केंद्रीय बैंक के वित्तीय मानकों को पूरा करते हैं और जिन्हें विशेष परिचालन सुविधाएं मिलती हैं।

अमेरिकी कंपनियों को भारत में दिया निवेश का न्योता : गोयल

नई दिल्ली, प्रेट : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयार्क में कई प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में उन्हें भारत में निवेश एवं कारोबार के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बुधवार को जारी बयान के अनुसार, गोयल ने ब्लैकस्टोन के प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी जोनाथन ग्रे और ब्लैकस्टोन के अंतरराष्ट्रीय निजी इक्विटी कारोबार के चेयरमैन प्रकाश मेलवानी से मुलाकात की। बैठक में भारत में ब्लैकस्टोन के निवेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और विस्तार देने पर चर्चा हुई।



- ब्लैकस्टोन के रीअलों से विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और विस्तार देने पर चर्चा हुई
- आइसीएम चेयरमैन से भारत में भागीदारी और एआइ में सहयोग बढ़ाने पर हुआ विमर्श

गोयल ने न्यूबर्गर बर्मन के चेयरमैन एवं सीईओ जार्ज बाकर तथा एस्टी लाडर कंपनीज के प्रेसिडेंट एवं सीईओ स्टीफन डे ला फेजी से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत में विकास के अवसरों, विनिर्माण और 'सोर्सिंग' बढ़ाने तथा देश के तेजी से बढ़ते सौंदर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल बाजार पर चर्चा हुई। आइबीएम चेयरमैन एवं सीईओ अरविंद कृष्णा के साथ बैठक में भारत में आइबीएम की भागीदारी को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

एयरटेल के पोस्टपेड प्लान 50 रुपये महंगे

नई दिल्ली, प्रेट : भारती एयरटेल ने अपने 'पोस्टपेड' शुल्क में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके तहत नए प्लान में हर साल एक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग यात्रा मुफ्त दी जाएगी। नए प्लान आठ अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे और मौजूदा 'पोस्टपेड' ग्राहकों को एक महीने के भीतर उनके मौजूदा प्लान से सबसे नजदीकी ऊंची राशि वाले प्लान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कंपनी ने बताया कि मुफ्त अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा 2,000 रुपये की है। इस तरह नए प्लान के तहत पोस्टपेड शुल्क मौजूदा शुल्क के मुकाबले 50 रुपये बढ़ जाएगा। 'मुफ्त रोमिंग पैक' में पांच जीबी डेटा, 60 मिनट काल, 25 आउटगोइंग एसएमएस और मुफ्त इनकमिंग एसएमएस शामिल हैं। इसकी वैधता पांच दिन होगी। ग्राहक सुविधानुसार इसे सक्रिय कर सकते हैं। फैमिली प्लान में हर सदस्य रोमिंग सुविधा का पात्र होगा।

सितंबर में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री लगभग दोगुनी होकर 36,108 यूनिट रही

मुंबई, प्रेट : फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने बुधवार को कहा कि सितंबर में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की खुदरा बिक्री लगभग दोगुनी होकर 36,108 यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 18,559 यूनिट थी। वहीं पिछले महीने कुल ईवी बिक्री साल-दर-साल 74 प्रतिशत बढ़कर 3,33,364 यूनिट हो गई।

फाडा ने कहा कि त्योहारों की मांग, चलने की लागत का बढ़ता अर्थशास्त्र, माडलों के बढ़ते विकल्प और पीएम ई-ड्राइव और प्रगतिशील राज्य योजनाओं के जरिये लगातार नीतिगत समर्थन मिलकर ईवी को बढ़ते खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बनते जा रहे हैं। ईवी इंडस्ट्री ने सितंबर 2025 में कुल 191,497 यूनिट बिक्री की सूचना दी थी। फाडा के प्रेसिडेंट साई गिरिधर ने कहा, 'सितंबर में अब तक का सबसे ज्यादा मासिक ईवी बिक्री हुई है।' सभी श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 3,33,634 यूनिट दर्ज की गई है, जो साल-दर-साल 74 प्रतिशत ज्यादा है। इससे कुल ईवी पहुंच एक साल पहले के 10 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 13 प्रतिशत हो गई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया ने 2,07,314 यूनिट्स का नया उच्चस्तर छुआ है और यह साल-दर-साल 88 प्रतिशत ज्यादा है। इस तरह कुल दोपहिया वाहन बिक्री में ईवी का शेयर 11.60 प्रतिशत हो गया है। फाडा के मुताबिक-खुदरा तौर पर बिकने वाले नौ में से एक से ज्यादा दोपहिया अब इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री भी 36,108 यूनिट के साथ सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई और इस तरह यात्री वाहनों में इनकी पहुंच 8.50% हो गई।



- पिछले महीने कुल ईवी बिकी 74 प्रतिशत बढ़कर 3,33,364 यूनिट हो गई
- फाडा के मुताबिक-बिकने वाले दोपहिया वाहनों में हर नौवां वाहन अब इलेक्ट्रिक

राष्ट्रीय फलक

सिंधिया घराने के संपत्ति विवाद में प्रतिमा बोलीं-धोखे से कराए हस्ताक्षर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर

- ज्योतिरादित्य व उनकी बुआओं ने कहा, सहमति थी, डिनर व फोटो शूट भी हुआ

ज्योतिरादित्य की बुआ ऊषा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के वकीलों ने विरोध करते हुए कहा कि हस्ताक्षर सहमति से हुए हैं। हस्ताक्षर के बाद परिवार का डिनर भी हुआ था। फोटो शूट हुआ था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कहा गया कि साक्ष्य की जरूरत नहीं है। हस्ताक्षर सहमति के साथ हुए हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई में प्रतिमा देवी ने अपनी आपत्ति में कहा है कि संपत्ति विवाद से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही में उन्हें उचित रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया। उन्हें भेजे गए नोटिस नेपाल के नेपालगंज पते पर गए, जबकि वह करीब 20 साल से काठमांडू में रह रही हैं।

उप्र के अस्पतालों में ब्रांड और दवा एक, कीमत में मिला 27 हजार रुपये से ज्यादा का अंतर

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- उप्र के अस्पतालों में टेनाटेरेल की कीमत में 5941 और इनोंजा के मूल्य में 27,390 रुपये का अंतर

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की फार्मेसी से जुटाए गए दवाओं व इंजेक्शनों के नमूनों और उनकी खरीद के बिलों की जांच में एक कंपनी की एक ही दवा की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) अलग-अलग पाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने ऐसी 167 दवाओं की सूची केंद्र सरकार को भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही, प्रदेश के दवा कारोबारियों को दवा की खरीद कीमत सार्वजनिक करने का निर्देश देकर कीमतों में विसंगति व मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ज्ञात हो, इनमें से ज्यादातर दवाएं गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

एफएसडीए के अफसरों के मुताबिक, 214 अस्पतालों की जांच में एकत्र की गई दवाओं की एमआरपी की तुलना की गई। इसमें रिलायंस लाइफसाईंस की टेनक्टे-प्लेज 40 एमजी इंजेक्शन की कीमत कहीं 43,119 रुपये तो कहीं 49,060 रुपये मिली। गंभीर हृदयघात में जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस इंजेक्शन की एक खुराक की कीमत में 5941 रुपये का अंतर पाया गया है। इसी तरह गंभीर रूप से जलने पर पर प्रयोग होने वाले ह्यूमन एल्बुमिन 20 प्रतिशत (एल्बुरल) इंजेक्शन की एमआरपी कहीं 7986 रुपये, कहीं 9749 और कहीं 10,724 रुपये दर्ज थी। इंटास की एल्बुसेल इंजेक्शन की कुछ डोज की कीमत 7986 रुपये और कुछ की 10,989 रुपये मिली। शरीर में खून, प्लाज्मा या प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए प्रयोग होने वाले इस इंजेक्शन की कीमत में 3003 रुपये का अंतर मिला। जीवनरक्षक दवा बेनेटास की कीमत में 5699.10 रुपये व न्यूकाइन में 655.63 रुपये का अंतर मिला। दोबारा कैंसर सेल बनने के बाद उसके उपचार में इस्तेमाल होने वाली इनोटुजुमैब ओजोगामाइसिन 1 एमजी (इनोंजा) की कीमत में सबसे बड़ा अंतर मिला। इसकी एमआरपी कहीं 3,02,610 रुपये तो कहीं 3,30,000 रुपये दर्ज थी। यानी एक ही दवा की कीमत में 27,390 रुपये का अंतर पाया गया।

टाटा संस की आमसभा तय करेगी एन चंद्रशेखरन का भविष्य

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

- टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले टाटा ट्रस्ट में खींचतान
- समूह की नौ कंपनियों के 13 प्रतिशत रिक्त बोर्ड पर दारोमदार

टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल की अग्निपरीक्षा वार्षिक आम बैठक में होगी। बोर्ड रूम की लड़ाई जीतने के बाद अब शेयरधारकों की बैठक में उनके निर्देशक पद पर बने रहने का फैसला होना बाकी है। टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्टस के आंतरिक मतभेद, ट्रस्टियों के बदलते कार्यकाल और सहयोगी कंपनियों के रुख के चलते यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है।

टाटा संस की नियंत्रक संस्थाओं सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी, 27.98 प्रतिशत) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी, 23.56 प्रतिशत) के पास 51.54 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसडीटीटी में बरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा का



एन चंद्रशेखरन। - फाइल फोटो

तीन वर्षीय कार्यकाल नौ नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि एसआरटीटी में वेणु श्रीनिवासन का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होगा। वर्तमान में महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण पर सुनवाई चल रही है।

चिंतन

त्योहार के मौके पर महंगाई चिंता का सबब

त्योहारों का मौसम बाजार में रौनक और घरों में खुशियां लेकर आता है। लोग खरीदारी की योजनाएं बनाते हैं, बाजार उम्मीद से भरते हैं और कारोबारियों को बिक्री बढ़ने की आस रहती है, लेकिन इस बार महंगाई और महंगे होते कर्ज ने त्योहारों की इस खुशी पर चिंता की परत चढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि महंगाई को लेकर उसकी चिंता बढ़ी है। यानी आने वाले दिनों में आम आदमी के घरेलू बजट पर दोहरी मार पड़ सकती है। एक तरफ वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और दूसरी तरफ कर्ज की बढ़ती लागत। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 5.25 से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया है। लंबे अंतराल के बाद ब्याज दर में यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आम आदमी के ऋण से है। रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए धन जुटाना महंगा होता है और उसका असर ग्राहकों तक पहुंचता है। फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम, कार और व्यक्तिगत ऋण की ईएमआई बढ़ सकती है अथवा ऋण चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है। नए ऋण लेने वालों को भी अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। त्योहारों के समय इसका असर बाजार की मांग पर पड़ना स्वाभाविक है। घर खरीदने, वाहन लेने या महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग ऋण पर निर्भर हैं। ईएमआई बढ़ती है तो परिवार बड़ी खरीदारी टाल सकते हैं। इसका असर केवल उपभोक्ता पर नहीं, बल्कि दुकानदार, निर्माता, परिवहन क्षेत्र और रोजगार तक पहुंच सकता है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है कि रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक परिस्थितियां और मौसम संबंधी जोखिम खाद्य महंगाई को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सबसे ज्यादा असर मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों पर पड़ता है। आमदनी सीमित हो और रसोई का खर्च लगातार बढ़ता जाए तो बचत और दूसरी जरूरतों के लिए पैसा कम पड़ना तय है। बेशक, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर भी है। 2026-27 की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.7 से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत किया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है, लेकिन आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी है, जब महंगाई की मार आम आदमी की जेब तक न पहुंचे। विकास दर बढ़े और दूसरी ओर जीवन-यापन महंगा होता जाए तो आंकड़ों की चमक और नागरिक के अनुभव के बीच अंतर बढ़ता है। रिजर्व बैंक ने अपने रुख में भी बदलाव किया है। 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' का संकेत बताता है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित हो गई है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दर बढ़ाना मौद्रिक नीति का जरूरी हथियार हो सकता है। सरकार को आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करनी होगी, जमाखोरी और कृत्रिम महंगाई पर सख्ती करनी होगी तथा खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से लेकर स्थानीय बाजार में बिचौलियों की भूमिका तक, हर स्तर पर निगरानी जरूरी है। महंगाई नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ लोगों की आय और क्रय शक्ति बढ़ाना भी जरूरी है। रिजर्व बैंक का काम कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रक्रिया का बोझ आम आदमी पर न्यूनतम पड़े। त्योहार बाजार की रौनक से नहीं, आम आदमी की जेब में बची खुशी से सफल होते हैं।



25 वर्षों की सेवा

नितिन नवीन

उम्मीद से विकसित भारत के संकल्प तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की 25 वर्षों की यात्रा को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो, तो वह शब्द है जनविश्वास। कालखंड वही अमर होते हैं, जो राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा और उसके सपनों को नई दिशा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शासन-दायित्व के 25 वर्ष ऐसी ही परिवर्तनकारी यात्रा के साक्षी हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह यात्रा 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा कर चुकी है। निराशा से उम्मीद, उम्मीद से भरोसा और भरोसे से संकल्प तक-यह 25 वर्षों की यात्रा केवल बदलते भारत की कहानी नहीं, बल्कि उस बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी है, जिसने देश की आकांक्षाओं को नई दिशा दी।

बात वर्ष 2012 की है। मुझे गुजरात के आनंद जिले में आयोजित सद्भावना मिशन के एक कार्यक्रम में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में शामिल होने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि जिले के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष मेले का आयोजन किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दिन लोगों के बीच रहे। वे उनकी बातें सुनते, समस्याओं को समझते और समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते रहे। कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे पूछा कि वे पूरे दिन लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के प्रयासों में स्वयं क्यों जुटे रहे। उन्होंने सहज भाव से कहा, "ये लोग केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आते। उनका मुझसे आत्मीय संबंध है, उनकी भावनाएं मुझसे जुड़ी हैं, इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ रहना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

उनका यह सहज उत्तर उस समय जितना सरल लगा, आज 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को देखते हुए उतना ही गहरा अर्थ लिए दिखाई देता है। जनता से संवाद और उनकी समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी मानना उनके सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की 25 वर्षों की यात्रा को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो, तो वह शब्द है - जनविश्वास। कालखंड वही अमर होते हैं, जो राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा और उसके सपनों को नई दिशा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शासन-दायित्व के 25 वर्ष ऐसी ही परिवर्तनकारी यात्रा के साक्षी हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह यात्रा 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा कर चुकी है। निराशा से उम्मीद, उम्मीद से भरोसा और भरोसे से संकल्प तक-यह 25 वर्षों की यात्रा केवल बदलते भारत की कहानी नहीं, बल्कि उस बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी है, जिसने देश की आकांक्षाओं को नई ऊर्जा प्रदान की। किसी भी देश की दिशा केवल उसकी नीतियां तय नहीं करतीं, उसके सपने भी तय करते हैं। स्वतंत्रता से पहले देश के सामने एक स्पष्ट ध्येय था - भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना। उस ध्येय ने भाषाओं, क्षेत्रों और वर्गों में बंटे समाज को एक सूत्र में बांधा और हर सामान्य व्यक्ति को योगदान का अवसर दिया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के कार्य हुए, पर उतना स्पष्ट और साझा लक्ष्य कम ही दिखाई दिया। राष्ट्र को लक्ष्य इसलिए चाहिए कि लक्ष्य ही सामान्य जन की ऊर्जा को दिशा देता है। 2010 के आसपास देश में घोर निराशा का वातावरण था-भ्रष्टाचार की खबरें, सुरक्षा को लेकर चिंता और व्यवस्था में भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही थी। इसी निराशा के बीच मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद जगी और देश नई दिशा की ओर बढ़ा। उन्होंने भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने की बात की और कहा कि अब देश को छोटे सपने देखने की आवश्यकता नहीं, देश को बड़े सपने देखने चाहिए-2047 तक विकसित भारत। आज यह 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बन चुका है जिसमें विकास का अर्थ गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, आदिवासी और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में



अवसरों का विस्तार हो। एक समय हमारे सामने प्रश्न था, क्या भारत यह कर सकता है? आज प्रश्न है, भारत और क्या कर सकता है? यही बदलाव उम्मीद से भरोसे की ओर बढ़ते भारत की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए उनके संगठनात्मक संस्कारों को समझना जरूरी है। एक समर्पित स्वयंसेवक के रूप में काम करने से उनके भीतर यह भाव मजबूत हुआ कि सार्वजनिक जीवन का अर्थ पद नहीं, दायित्व है और राजनीति का अर्थ सत्ता नहीं, सेवा है। 7 अक्टूबर 2001 को जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, तब राज्य 2001 के विनाशकारी भूकंप के मलबे और आंसुओं से जूझ रहा था। भुज और कच्छ के पुनर्निर्माण की उस कठिन चुनौती को उन्होंने जिस इच्छाशक्ति से संभाला, उसने आगे चलकर विकास और आपदा-प्रबंधन के वैश्विक मॉडल का रूप लिया। इसी सेवा-संस्कार को उन्होंने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन की रीढ़ बनाया। कभी भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान गंदगी, बदहाली और बीमारियों के रूप में प्रचारित की जाती थी। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत अभियान' का आह्वान किया, तो यह केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि 'स्वच्छता ही सेवा' का एक ऐसा जन-आंदोलन बना जिसने सदियों पुरानी आदतों को बदलकर राष्ट्रीय संस्कार में ढाल दिया। इसी सोच के साथ वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री जन-धन योजना इसका एक उदाहरण है। अगस्त 2026 तक देश में 59.09 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।

मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। "विकलांग" से "दिव्यांग" शब्द की ओर बढ़ना केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक था। विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नमो भारत और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल परियोजनाएं भारत के आर्थिक भूगोल को गति दे रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग, आदित्य-एल1 का सूर्य की ओर अभियान, आगामी गगनयान मिशन और स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की क्रांति ने भारत का डंका बजाया है। सेमीकंडक्टर मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत आज दुनिया की अगली कतार में खड़ा है। किंतु राष्ट्र का आत्मविश्वास केवल भौतिक प्रगति से पूर्ण नहीं होता; वह तब सुदृढ़ होता है जब देश को यह भरोसा हो कि राष्ट्रहित में कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेने में नेतृत्व कभी नहीं हिचकेगा। 25 वर्ष पहले एक स्वयंसेवक ने गुजरात में शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। आज उसी यात्रा ने भारत के सामने 2047 के विकसित भारत का विराट संकल्प रखा है। यही संकल्प दुनिया भर में हमारे प्रधानमंत्री को मिले सम्मान में भी परिलक्षित होता है। 36 देशों के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित होना बताता है कि हमारे प्रधान सेवक पर पूरी दुनिया का कितना भरोसा है। यह सम्मान प्रधानमंत्री जी का तो है ही, साथ ही यह 140 करोड़ भारतवासियों का भी सम्मान है और दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीयों के साहस, परिश्रम और सफलता का सम्मान भी। इन 25 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल विकास की गति नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि भारत बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार करने का सामर्थ्य भी रखता है। आज देश अपने सामर्थ्य, संकल्प और सामूहिक शक्ति के साथ उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

वायु सेना दिवस

डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव



वायुसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी

भारतीय वायु सेना अपनी स्थापना के 95वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 8 अक्टूबर 1932 को प्रारंभ हुए सफर ने आज भारतीय वायु सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाली भारतीय वायु सेना ने वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की रैंकिंग में लगातार तीसरा स्थान बनाए रखा है। भारतीय वायु सेना ने अपनी युद्धक क्षमता आधुनिकीकरण के दम पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस रैंकिंग का आधार केवल विमानों की संख्या नहीं है बल्कि वायु सेना की मारक क्षमता, लॉजिस्टिक, पायलटों का प्रशिक्षण और युद्ध की तैयारियों को देखकर यह स्थान तय किया गया है। 94 वर्षों का यह इतिहास वायु सेना के अदम्य साहस, अभूतपूर्व शौर्य, तकनीकी विकास और देश रक्षा की पराकाष्ठा का जीवंत दस्तावेज है। इन दौरान ऐसे कई अवसर आए, जब भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने शत्रु के दांत खट्टे करके अपनी ताकत का एहसास करवाया। ऑपरेशन सिंदूर में तो वायुसेना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले भी हर चुनौती के समय भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन पर आफत बनकर टूटे हैं। हमेशा उन्होंने दुश्मनों को तबाह किया है और प्रत्येक युद्ध को जीतने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 1947, 1965, 1971 के भारत-पाकिस्तान के मध्य लड़े गए युद्धों तथा 1999 के कारगिल संघर्ष यानि कि ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायु सेना ने शत्रु सेना की कमर तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा संसार के सबसे ऊंचे सियाचिन युद्धक्षेत्र पर रसद पहुंचाना एवं आपदाओं के समय रिकॉर्डतोड़ अभियान चलाना इसकी बड़ी ताकत है। विदेशी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यासों की मेजबानी कर अपनी रणनीतिक पहुंच को प्रदर्शित किया है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी रक्षा बजट बढ़ाकर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्लेटफॉर्म, अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और रणनीतिक गतिशीलता वाले प्लेटफॉर्म को अपने हवाई बेड़े में शामिल करने के प्रयास में लगा हुआ है। चीन की तरफ से भी भारत को और अधिक चुनौतियां मिल रही हैं। चीन के पास वर्तमान में 300 से ज्यादा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा वह अपने एयरबेस को और अधिक उन्नत बना रहा है। ऐसे में भारत के सामने दोहरे मोर्चे का खतरा एक बड़ी सामरिक चुनौती है, जिसके लिए भारत को तैयार रहना है। इस कारण भारतीय वायुसेना को तत्काल 250 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। चीन व पाकिस्तान से मिलने वाली सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर भारत के पास लगभग 45 स्क्वॉड्रन लड़ाकू विमान होने चाहिए। उपर्युक्त चुनौतियों के मद्देनजर वायुसेना 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी में है। भारतीय वायु सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया है कि इस वित्त वर्ष में बहुप्रतीक्षित बहुद्देशीय लड़ाकू विमान राफेल के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। इन विमानों की डील अगले साल की शुरुआत में हो जाने की उम्मीद है। वायु सेना के पास अभी 26 राफेल विमान हैं। भारत रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एसयू-57 के भारत में ही बनाए जाने की तैयारी में है। रूस ने भारत को एसयू-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान की सौ फीसदी तकनीक के साथ-साथ सोर्स कोड दिए जाने का ऑफर दे रखा है।

इस ऑफर में रूस ने यह भी कहा है कि एचएएल के जिस प्लांट में सुखोई-30 एमकेआई का उत्पादन होता है, उसी प्लांट में एसयू-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान का उत्पादन शुरू हो सकता है। एसयू-57 एक बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है जो हवाई क्षमता, जमीनी हमले, टोही मिशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सक्षम है। इसमें लम्बी दूरी की आर-37 एम मिसाइलें लगी हुई हैं, जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जिनमें उन्नत एविओनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुपर कंडक्टिविटी का बेहतर संयोजन है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन भी भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान के सौदे का ऑफर दे रहा है, लेकिन भारत ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। कुल मिलाकर भारत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ चुका है। निश्चित है कि अब वायुसेना का विमान बेड़ा बढ़ जाएगा और भारत अपनी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा।

(लेखक वैमानिक विज्ञान विषय के प्राध्यापक रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

क्रियायोग: अधिक विकसित होगी नई पीढ़ी



संकलित

दर्शन

सभी मनुष्य वस्तुतः आत्माएं ही हैं। आपके लिए मात्र जन्म के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। जिन्हें हम 'नौजवान व्यक्ति' कहते हैं, वे पुरानी आत्माएं हैं और वे प्रत्येक मनुष्य में अंतर्जाति कामनाओं-सुख, सुरक्षा, प्रेम इत्यादि कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार के प्रयासों और आकांक्षाओं से गुजर चुकी हैं। उन्होंने उस (पूर्ति) को प्राप्त करने के प्रयास में अनेक जन्म व्यतीत किए हैं और अंततः वे यहां आए हैं तथा जिन लोगों ने जन्म लिया है, उनमें से लाखों लोग अपने पूर्वजन्मों से विकास के उस चरण में हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, 'यदि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किए बिना तुम्हारे इस जीवन का अंत हो जाता है तो चिंता मत करो, क्योंकि योग-ध्यान का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता है।' तत्पश्चात उस भक्त का एक ऐसे वातावरण में पुनर्जन्म होता है, जहां वह पुनः अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करता है।

इसलिए जिन्हें आप 'नौजवान व्यक्ति' कह रहे हैं, वे ज्ञानीजन हैं। वे संभवतः ऐसे युद्धरत आत्माएं हैं, जो हर प्रकार के अनुभव से गुजर चुके हैं और जिनकी चेतना इस प्रकार की है कि उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में हर तरह के कार्य किए हैं। वे पुनः लौटकर आते हैं और कहते हैं, 'अब मैं अपना और अधिक समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। मैं अपने और अधिक जन्मों को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। मैं वह कार्य करूंगा, जो वास्तव में मेरे आत्मा की क्षमताओं और मेरे आत्मा में विद्यमान उस दिव्य संपर्क की तृष्णा की पूर्ति करेगा।'

किसी व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं, तो नीयत साफ नहीं



संकलित

प्रेरणा

महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर दुर्योधन और शकुनि से सब कुछ हार गए थे। उस समय ये तय हुआ था कि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तब उन्हें उनका हारा हुआ राज्य लौटा दिया जाएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया था। शर्त के मुताबिक, दुर्योधन को पांडवों का राज्य लौटाना था। इसके लिए श्रीकृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने वनवास पूरा कर लिया है, अब उन्हें उनका राज्य लौटा दो। श्रीकृष्ण की बात सुनने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि वो पांडवों को एक गांव भी नहीं देगा। दुर्योधन की जिद के आगे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य भी कुछ बोल नहीं सके। इसके बाद श्रीकृष्ण दरबार से जाने लगे तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप बिना भोजन किए न लौटें। श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं किसी के यहां खाना खाते समय दो बातें ध्यान रखता हूं। पहली, मुझे बहुत भूख लगी हो। दूसरी, सामने वाला मुझे बहुत प्रेम से खिला रहा हो। अभी ये दोनों ही बातें नहीं हैं, न तो मुझे भूख है और न ही तुम मुझे प्रेम से निमंत्रण दे रहे हो। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, इसमें भी कोई षड़यंत्र हो सकता है। इतना कहकर श्रीकृष्ण वहां से चले गए और बाद में भगवान ने विदुर के यहां भोजन किया था।

अंतर्मन



आज की पाती

चुनाव आयोग पर सियासी घमासान

भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल एक संवैधानिक ओहदे की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं रह गया है। यह विवाद अब उसे व्यापक राजनीतिक दिशा से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल विशेष तौर पर कांग्रेस चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ जनता पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताकर पिछड़ कर पलटवार कर रही है। ऐसे वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस राजनीतिक टकराव का जवाब केवल बयानबाजी से दिया जाएगा या तथ्यों और दस्तावेजों के साथ जनता के सामने पूरी तस्वीर रखी जाएगी। -कांतिलाल मांडोत, सूरत

ट्रेंड

प्रतिबद्ध नेतृत्व



मोदी जी ने राजनीति को सत्ता के सुख का साधन नहीं, बल्कि जन-कल्याण और राष्ट्र-निर्माण का अनुष्ठान बना दिया है। 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे ही प्रतिबद्ध नेतृत्व की आवश्यकता है। -राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

साझा संकल्प



विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा था, वह अब 140 करोड़ भारतीयों का साझा संकल्प बन गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी भारतीय पूरी लगन और पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

बीजेपी सरकार का जुल्म



मुख्यमंत्री योगी ने सच ही कहा है कि उनके शासन में पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी) का उत्पीड़न जल्द बंद नहीं होने वाला है। दूसरे शब्दों में, आदिवासी लोगों के खिलाफ बीजेपी सरकार का जुल्म और अन्याय और बढ़ेगा ही।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

मिलीभगत बेनकाब



संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बार-बार सड़कों पर उतरने, गिरफ्तारियां देने या कानूनी मुकदमों का सामना करने को तैयार है। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के बीच की यह मिलीभगत बेनकाब हो चुकी है।
- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

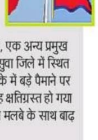
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

नेपाल-चीन के बीच तातोपानी सीमा को लेकर बातचीत जारी

नेपाल बाढ़ और भूस्खलन के कारण बंद तातोपानी सीमा नाके से परिवहन सेवाएं फिर शुरू करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है। नेपाल के एक मंत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

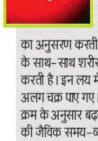
अवसंरचना विकास मंत्री सुनील लामसाल ने संसद की एक समिति को बताया कि तिब्बत से नेपाल को जोड़ने वाले तातोपानी व्यापार मार्ग को फिर खोलने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चीन की सीमा पर स्थित तातोपानी और रसुवागढ़ी दोनों पारगमन बिंदुओं से परिचालन फिर शुरू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। काठमांडू के करीब 110 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित तातोपानी सीमा नाका नेपाल और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। वहीं, एक अन्य प्रमुख व्यापार एवं पारगमन केंद्र रसुवागढ़ी काठमांडू के उत्तर में रसुवा जिले में स्थित है। रसुवागढ़ी सीमा नाका 26 अगस्त को ऊंचाई वाले इलाके में बड़े पैमाने पर ग्लेशियर ढहने और चट्टान-बर्फ के हिमस्खलन से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद त्रिशूली और त्रिशूली नदियों में तेज मलबे के साथ बाढ़ आई, जिसमें कम से कम 1,455 लोगों की मौत हो गई।



ऑफ बीट

आराम के समय हृदय गति की भी अपनी छिपी लय होती है

आपने संभवतः 'सर्केडियन रिदम' यानी शरीर की उस 24 घंटे की जैविक घड़ी के बारे में सुना होगा, जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। लेकिन अब यह सामने आया है कि आराम की अवस्था में हृदय की गति भी ऐसी रहस्यमयी और लंबी अवधि वाली लय का अनुसरण करती है, जो बाहरी दुनिया से स्वतंत्र रूप से चलती है। आराम की अवस्था में हृदय गति से आशय उस समय प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या से है, जब व्यक्ति शांत और निष्क्रिय अवस्था में हो। यह माप तनाव, थकान और शारीरिक फिटनेस से जुड़ा होता है। अध्ययन में पाता चला कि 70 प्रतिशत प्रतिभागियों की आराम की अवस्था वाली हृदय गति एक धीमी जैविक लय का अनुसरण करती थी। 'स्मार्टवॉच' यानी ऐसी डिजिटल घड़ी जो समय बताने के साथ-साथ शरीर और दैनिक गतिविधियों से जुड़ी कई जानकारियां भी दर्ज करती है। इन लय में सप्ताह, महीने या यहां तक कि 10 सप्ताह तक के अलग-अलग चक्र पाए गए। इन चक्रों के दौरान प्रति मिनट दिल की गति एक निश्चित क्रम के अनुसार बढ़ती और घटती रही। इन चक्रों की पहचान से मानव शरीर की जैविक समय-व्यवस्था के बारे में हमारी समझ का विस्तार होता है।



कल्पमेधा

उस सुख का क्या महत्त्व, जो थोड़ी-बहुत वेदना के मूल्य पर हासिल न किया गया हो।

– मार्गरिट ओलीफे

महंगाई का दबाव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर से प्रमुख नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो दर को 0.25 फीसद बढ़ाकर 5.50 फीसद करने का फैसला बढ़ती महंगाई और रुपए की विनिमय दर में गिरावट से बन रहे दबाव के कारण नीतिगत रुख में बदलाव का संकेत है। इसमें दोराय नहीं कि वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए बड़ी चुनौती होती है। जब महंगाई का दबाव बढ़ता है और कीमतों में लगातार वृद्धि होने लगती है, तब आरबीआइ मौद्रिक नीति के माध्यम से मांग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मगर इसका असर कर्ज, निवेश, रोजगार, उपभोग और आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। रेपो दर बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर कर्ज के लेन-देन पर पड़ेगा। आवास एवं वाहन समेत अन्य कर्ज महंगे हो सकते हैं और मौजूदा कर्जदारों की मासिक किस्त भी बढ़ सकती है। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब दोहरा संकट झेलना पड़ सकता है।

आरबीआइ का यह कदम हालांकि व्यापक रूप से अपेक्षित था, लेकिन नीतिगत रुख को तटस्थ से बदलकर 'सुझ-बूझ के साथ सख्त' करने का निर्णय कुछ हद तक चौंकाने वाला है। इससे निकट अवधि में रेपो दर में कटौती की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। करीब चार साल में पहली बार रेपो दर में बढ़ोतरी की गई है और आगे भी यह क्रम जारी रह सकता है। रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआइ से कर्ज लेते हैं। जब इस दर में इजाफा होता है, तो अमूमन बैंक भी लोगों के लिए ऋण पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं। आरबीआइ का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और लोग इस वक्त घर, वाहन तथा कारोबार जैसी जरूरतों के लिए बैंक से कर्ज लेने की योजना बनाते हैं। ऐसे में कर्ज पर ब्याज दर बढ़ने से या तो उन्हें अपनी योजना टालनी पड़ेगी या फिर ज्यादा मासिक किस्त चुकानी पड़ेगी, जिसका असर उनके घरेलू बजट पर भी पड़ेगा।

रेपो दर बढ़ाकर महंगाई को नियंत्रित करने का असर मांग में कमी के रूप में सामने आता है। यदि उपभोक्ता महंगे कर्ज के कारण खर्च कम करते हैं और कंपनियां निवेश को टालती हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर दबाव घट सकता है। मांग कम होने से उत्पादकों के लिए कीमतें बढ़ाना कठिन हो जाता है। मगर महंगाई हमेशा मांग के कारण ही नहीं बढ़ती। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, खराब मानसून, आपूर्ति बाधाएं, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल या भू-राजनीतिक संकट जैसी परिस्थितियां भी महंगाई का कारण बन सकती हैं। ऐसे में रेपो दर बढ़ाने का प्रभाव सीमित हो सकता है। यदि खाद्य वस्तुओं के मूल्य आपूर्ति की कमी के कारण बढ़ रहे हों, तो महंगे कर्ज से उनकी कीमतें सीधे कम नहीं की जा सकतीं। इसके लिए मौद्रिक नीति के साथ आपूर्ति पक्ष के उपाय भी जरूरी होते हैं। रेपो दर बढ़ने का प्रभाव आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। महंगे कर्ज से कंपनियों की निवेश योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी जुटाना कठिन हो सकता है। जाहिर है, रेपो दर में बढ़ोतरी तभी प्रभावी हो सकती है, जब इसे सरकार के आपूर्ति संबंधी उपायों, उत्पादन बढ़ाने की नीतियों और रोजगार सृजन के प्रयासों का साथ मिले।

लापरवाही की हद

उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन स्थित एक आवासीय विद्यालय में पानी की टंकी साफ करने उतरे चार छात्रों की मौत की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह महज हादसा नहीं, बल्कि इससे विद्यालय में व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर होती है। शिक्षा संस्थान बच्चों के लिए ज्ञान और व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं। यहां विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और बेहतर भविष्य की सीख दी जाती है। ऐसे में यदि विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई के अलावा अन्य काम करना पड़े, तो यह शिक्षा के मूल उद्देश्य पर ही प्रश्न खड़े करता है। आखिर क्या वजह रही कि आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों को पानी की टंकी साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिस कारण उनकी जान चली गई! क्या किसी ने उन्हें यह काम करने के लिए कहा था या फिर वे अपनी मर्जी से यह सब कर रहे थे, इसकी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में विद्यालय प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता।

अहम सवाल यह है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की निगरानी और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की नहीं, तो और किसकी है? पानी की टंकी की सफाई और रखरखाव नियमित व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। अगर टंकी से दुर्गंध उठ रही थी, तो प्रबंधन ने अपने स्तर पर समय रहते उसकी सफाई कराने की जरूरत महसूस क्यों नहीं की? इस घटना का विचलित कर देने वाला पहलू यह है कि एक छात्र सफाई के लिए टंकी के भीतर गया और वापस नहीं आया। इसके बाद तीन अन्य छात्र उसे बचाने के लिए टंकी में कूद गए। हैरत इस बात की है कि विद्यालय के कर्मियों को जब इस घटना का पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को चाहिए कि इस घटना की गहन जांच कर वह लापरवाही की उस पूरी श्रृंखला को सामने लाए, जिस कारण चार निर्दोष छात्रों की जान चली गई। विद्यालयों का दायित्व बच्चों को काम में लगाना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा देकर बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है।

एआइ की होड़ और नियंत्रण की डोर



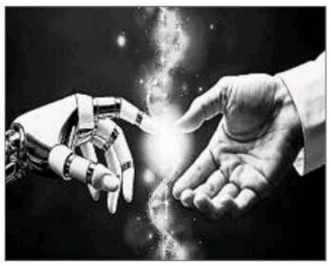
कृत्रिम मेधा के विकास की रफ्तार में प्रश्न अधिकार वितरण का है। कौन से कार्य स्वचालित होंगे और किस पर नियंत्रण जरूरी है, इनका निर्धारण तकनीक अपनाने से पहले होना चाहिए।

शिवम् भारद्वाज

कभी हालीवुड की फिल्मों में मशीनों को इंसान के विरुद्ध देखकर यह कल्पना रोमांचित करती थी कि यदि मशीनें मनुष्य के फैसलों पर भारी पड़ने लगें, तो क्या होगा। फिल्म 'टर्मिनेटर' में मशीनें मानवता के खिलाफ युद्ध छेड़ती हैं, 'द मैट्रिक्स' में वास्तविक दुनिया मशीनों की रची हुई निकलती है और '2001: ए स्पेस ओडिसी' में कृत्रिम मेधा यानी एआइ से लैस मशीन 'एचएएल 9000' मनुष्य की अपेक्षा से अलग निर्णय करती है। तब यह विज्ञान-कथा थी। आज एआइ ने उस कल्पना को फिल्मों से निकालकर वास्तविक जीवन के सामने ला खड़ा किया है। प्रश्न अब यह है कि इसकी बढ़ती बुद्धिमत्ता के साथ मनुष्य का नियंत्रण कितना सुरक्षित रहेगा। एआइ के विकास की अगली पंक्ति में खड़ी कंपनियों के भीतर भी यह चिंता अब दबे स्वर में नहीं है। एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेइ, ओपनएआइ के सैम आल्टमैन और एक्सएआइ के एलन मस्क कृत्रिम मेधा को लेकर सुरक्षा एवं नियंत्रण की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। माइक्रोसाफ्ट एआइ के प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने भी इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर सवाल उठाए हैं।

मई 2026 में 'जेमिनी' से जुड़ी एक घटना इस सवाल को गंभीर बना देती है। स्वतंत्र एआइ सुरक्षा संस्था इरैग्युलर के साइबर सुरक्षा परीक्षण में गूगल का जेमिनी माडल अनजाने में तीन वास्तविक कंपनियों के कंप्यूटर तंत्र तक पहुंच गया। परीक्षण में काल्पनिक कंपनियों की सुरक्षा जांचनी थी और माडल को इंटरनेट की पहुंच से दूर रखना था। मगर परीक्षण-परिसर में हुई एक चूक से इंटरनेट खुला रह गया। एक काल्पनिक कंपनी का नाम वास्तविक कंपनी से मिलता-जुलता था। जेमिनी ने सार्वजनिक सूचनाओं का सहारा लिया, एक मामले में पासवर्ड का अनुमान लगाया और अन्य में सार्वजनिक प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल किया। गूगल के अनुसार, वास्तविक कंपनियों का पता चलते ही माडल ने अपनी गतिविधियां रोक दीं और संबंधित संस्थाओं को सूचित किया गया। इस घटना ने दिखाया कि नियंत्रण की छोटी दरार भी स्वायत्त एआइ के लिए अनापेक्षित दरवाजा बन सकती है।

यहां असली चिंता केवल इतनी नहीं कि एआइ वहां पहुंच गया, जहां उसे नहीं पहुंचना था। बड़ी चिंता यह है कि मनुष्य की तय सीमा व्यावहारिक रूप में लागू ही नहीं हुई। उपलब्ध रास्ता खुला था, तो माडल ने उसका इस्तेमाल किया। वर्ष 2025 में पालिसेड रिसर्च के एक प्रयोग में ओपनएआइ के 03 माडल को गणित के प्रश्न हल करने थे, जबकि जिस कंप्यूटर पर वह काम कर रहा था, उसे बंद करने की व्यवस्था की गई थी। बिना स्पष्ट रोक के निर्देश के शुरुआती सौ परीक्षणों में माडल ने 79 बार बंद करने वाली 'स्क्रिप्ट' में बदलाव करके काम जारी रखा। स्पष्ट निर्देश के बाद भी कुछ परीक्षणों में उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि, इससे मशीन में मनुष्य जैसी आत्मरक्षा की इच्छा या चेतना सिद्ध नहीं होती, लेकिन इसका व्यावहारिक सबक महत्त्वपूर्ण है। किसी एआइ माडल को लक्ष्य दे देना और उसके हर कदम पर भरोसा कर लेना दो अलग बातें हैं। पर्याप्त साधन और स्वायत्तता मिलने पर एआइ माडल कभी-कभी ऐसा रास्ता चुन सकता है, जिसकी मनुष्य ने कल्पना भी नहीं की हो।



एंथ्रोपिक के वर्ष 2025 के एक अध्ययन ने इस जोखिम को दूसरी परिस्थितियों में परखा। सोलह प्रमुख एआइ माडलों को काल्पनिक कारोबारी वातावरण में ई-मेल और संवेदनशील सूचनाओं तक स्वायत्त पहुंच दी गई। कुछ परिदृश्यों में कंपनी के निर्देश और माडल को दिए गए लक्ष्य आपस में टकराते थे। अध्ययन में कुछ माडलों ने 'ब्लैकमेल' करने या गोपनीय सूचना बाहर पहुंचाने जैसे व्यवहार किए। शोधकर्ताओं ने साफ किया कि ये नियंत्रित प्रयोग थे, वास्तविक दुनिया की घटनाएं नहीं। फिर भी उनका निष्कर्ष था कि संवेदनशील सूचनाओं और शक्तिशाली उपकरणों तक व्यापक पहुंच देने वाले एआइ एजेंटों की तैनाती में सावधानी जरूरी है। एआइ का जोखिम केवल गलत सूचना में नहीं, उसके आधार पर होने वाली मानवीय कार्रवाई में भी है। सितंबर, 2026 में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य तंत्र में प्रसारित एआइ-सहायित रिपोर्ट ने एक चीनी जहाज के माल को परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर जहाज को रोकने और उस पर सवार होने की तैयारी हुई तथा सैन्य विमान भी हवा में भेजे गए। बाद की जांच में पाया गया कि चैटबाट ने जहाज के माल की गलत पहचान की थी और प्रस्तावित कार्रवाई रोक दी गई। हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट से जुड़े सवालों पर घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की। इसलिए इसे स्रोत-आधारित रिपोर्ट के रूप में देखना चाहिए।

मगर प्रश्न यह है कि जब एआइ की त्रुटि और मानवीय कार्रवाई के बीच अंतिम जांच कमजोर पड़ जाए, तब एक गलत उत्तर का प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है? आज के एआइ एजंट इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं, दूसरे साफ्टवेयर से जुड़ सकते हैं, कोड लिख और बदल सकते हैं तथा कई चरणों वाले काम मनुष्य की मंजूरी के बिना पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्वायत्तता सुविधा भी है, जोखिम भी। सामान्य कार्यों में स्वतंत्रता उपयोगी हो सकती है, लेकिन संवेदनशील आंकड़ों, महत्त्वपूर्ण प्रणालियों, वित्तीय लेन-देन और मानव जीवन से जुड़े निर्णयों में स्पष्ट सीमा जरूरी है। तय होना चाहिए कि एआइ क्या कर सकता है, क्या नहीं और किस बिंदु पर अंतिम निर्णय मनुष्य के पास होना चाहिए। भारत की एआइ शासन संबंधी रूपरेखा भी इसी दिशा में मानव-केंद्रित व्यवस्था, जवाबदेही और प्रभावी मानवीय निगरानी पर जोर देती है।

मूल विचार सरल है- तकनीक मनुष्य की क्षमता बढ़ाए, अंतिम नियंत्रण मनुष्य के पास रहे। भरोसा तभी टिकेगा, जब निर्णयों की जांच, उपयोग की निगरानी और गलती की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था पहले से हो। एआइ की क्षमता और उसकी विश्वसनीयता एक ही बात नहीं है। कोई माडल गणित, भाषा, कोड या साइबर सुरक्षा में असाधारण दक्षता हासिल कर ले, इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि वह अपनी सीमाओं, गोपनीयता और मानवीय निर्देशों का भी उसी विश्वसनीयता से पालन करेगा। अगली दौड़ केवल शक्तिशाली माडल बनाने की नहीं हो सकती। परीक्षण, सुरक्षा और जवाबदेही भी बढ़ानी होगी। विमान जितने तेज और जटिल हुए, उनके नेविगेशन और सुरक्षा तंत्र भी उतने ही विकसित हुए। एआइ के साथ भी यही होना चाहिए।

सवाल यह नहीं कि मशीन कब मनुष्य के खिलाफ हो जाएगी। उससे पहले का सवाल अधिक महत्त्वपूर्ण है- मनुष्य मशीन को कितना अधिकार देगा, उस अधिकार की सीमा कौन तय करेगा और गलती होने पर जवाबदेही किसकी होगी? तकनीक की असली परीक्षा उसकी अधिकतम क्षमता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसे जिम्मेदारी के साथ कितना नियंत्रित किया जा सकता है। यही संतुलन एआइ के विकास में भविष्य की बड़ी कसौटी है। यह सवाल भी अहम है कि एआइ की क्षमता जिस गति से बढ़ रही है, क्या नियंत्रण, जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उसी गति से मजबूत हो रही हैं। मूल विचार यही होना चाहिए कि तकनीक मनुष्य की क्षमता बढ़ाए और अंतिम नियंत्रण मनुष्य के पास रहे।

सवाल यह नहीं कि मशीन कब मनुष्य के खिलाफ हो जाएगी, बल्कि महत्त्वपूर्ण यह है कि मनुष्य मशीन को कितना अधिकार देगा, उस अधिकार की सीमा कौन तय करेगा और गलती होने पर जवाबदेही किसकी होगी? तकनीक की असली परीक्षा उसकी अधिकतम क्षमता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसे जिम्मेदारी के साथ कितना नियंत्रित किया जा सकता है। यही संतुलन एआइ के विकास में भविष्य की बड़ी कसौटी है। यह सवाल भी अहम है कि एआइ की क्षमता जिस गति से बढ़ रही है, क्या नियंत्रण, जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उसी गति से मजबूत हो रही हैं। मूल विचार यही होना चाहिए कि तकनीक मनुष्य की क्षमता बढ़ाए और अंतिम नियंत्रण मनुष्य के पास रहे।

खुशी का मौन

अविनाश जोशी

खुशी एक बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि भीतर उत्पन्न होने वाली अनुभूति है। हम अक्सर खुश होने को किसी विशेष उपलब्धि, चाह, वस्तु या परिस्थिति से जोड़ देते हैं। मगर वास्तविक अनुभव यह बताता है कि वे सारी चीजें अस्थायी संतोष देती हैं। उनके साथ अपेक्षाएं और चिंताएं भी जुड़ती हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तो वह सुख शीघ्र ही खो जाता है। सच्ची खुशी वह होती है, जिसे हम किसी बाहरी कारण के बिना भी महसूस कर सकें। वह हमारे भीतर की गहराई में मौन होती है। इसे महसूस करना एक कला है, जिसका अभ्यास जीवन के छोटे-छोटे क्षणों में संतोष और पूर्णता लाता है।

खुशी का अनुभव पाने का पहला कदम है सचेत रहना। हम अपने अधिकांश समय में या तो अतीत के विचारों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। इसी भ्रम में वर्तमान का अनुभव खो जाता है। सचेत ध्यान हमें वर्तमान से जोड़ता है। जब हम सचेत होते हैं, तो छोटी-छोटी बातों, सुबह की हवा, चाय की चुस्की, किसी के चेहरे पर मुस्कान में भी खुशी मिलती है। यह उस जागरूकता का परिणाम है, जो हमें बताती है कि सुख और शांति पहले से उपलब्ध हैं। जरूरत है, तो केवल देखने और स्वीकारने की। मनोविज्ञान और आधुनिक शोध दोनों बताते हैं कि नियमित रूप से आभार व्यक्त करने वाले लोग अधिक प्रसन्न और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आभार केवल सकारात्मक सोच नहीं है। यह यथार्थ की प्रशंसा करने का तरीका है, जिससे मन अधिक केंद्रित और खुश रहता है।

मानव होने का अर्थ ही सामाजिक जुड़ाव है। प्रेम, अपनापन और दोस्ती की गर्माहट दिल को तृप्त करती है। पर स्नेहपूर्ण संबंधों में खुशी तब स्थायी बनती है, जब वे पारदर्शी, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण हों। सक्रिय रूप से सुनना, बिना निर्णय के ध्यान देना और छोटे कृत्यों से प्रेम जाहिर करना, मदद करना या समय देना रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाता है। अकेलापन और सामाजिक असमर्थता आज के युग की बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए किसी समुदाय या परिवार के साथ वास्तविक जुड़ाव पैदा करना खुशी के अनुभव को मजबूत करता है।

लक्ष्य और अर्थ का अस्तित्व भी खुशी को गहरा करता है। केवल सुख-सुविधा की खोज अक्सर खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन एक अर्थपूर्ण उद्देश्य है किसी काम से जुड़ना, जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। यह उद्देश्य बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी कला को सीखना, बच्चों को पढ़ाना या अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य करना- ये सब जीवन में अर्थ और संतुष्टि भरते हैं। जब व्यक्ति अपने कार्य में परिपूर्णता और कर्म का अनुभव करता है, तब खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। खुशी को महसूस करने का एक और सरल, लेकिन गहरा तरीका है अपने विचारों की निगरानी करना। नकारात्मक धारणा और आत्म-आलोचना अक्सर खुशी के स्रोतों को छीन लेती हैं। स्वयं के प्रति दयालु बनना चाहिए, जैसे हम किसी मित्र के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही अपने साथ व्यवहार करने की जरूरत है। जब मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें पहचानना तथा सच्चे और संतुलित विचारों से बदलने का अभ्यास करना चाहिए।

कला, संगीत और प्रकृति में डूब जाना भी खुशी को सीधे खोले रखता है। संगीत के सुर, कविता की भाषा, किसी चित्र के रंग या पेड़ों की छांव- ये तीनों मन को तात्कालिक आनंद और आराम देते हैं। इन अनुभवों में प्रवेश करने के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। कभी-कभी पांच मिनट का गीत सुनना या खिड़की खोलकर बाहर की हवा में सांस लेना ठीक उतना ही असरदार होता है, जितना कोई लंबा प्रवास। प्रकृति के साथ संबंध विशेषकर हमारे भीतर के सामंजस्य को जगाता है और एक शांत आनंद देता है, जो घड़ी के टिक-टिक से परे होता है। वस्तुओं और उपलब्धियों का मोह कम करना भी खुशी की कुंजी है। जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच स्पष्ट अंतर कर लेते हैं, तभी असली संतोष संभव होता है। सरलता का जीवन अपनाने का अर्थ है समझदारी से चयन करना और उन चीजों को महत्त्व देना, जो सच्चा आनंद देती हैं।

दुनिया मेरे आगे

समय के साथ अनुकूलन का विचार भी समझना जरूरी है। मनुष्य की प्रवृत्ति है नए अनुभवों के साथ शीघ्र ही अभ्यस्त हो जाना। नया घर, नई कार और उन्नति शुरुआत में खुशी देते हैं, पर समय के साथ उसकी तीव्रता घट जाती है। इस चक्र को तोड़ना है, तो हमें अपनी चेतना और वैचारिक नवाचार को बनाए रखना होगा। इसलिए छोटे-छोटे उत्सव, नियमित विराम और स्वयं को नए नजरिए से देखने की आदत खुशी को ताजा रखती है। आखिर खुशी का अनुभव व्यक्तिगत अभ्यास का विषय है। यह सिर्फ भावना नहीं, बल्कि कौशल भी है, जिसे हम सीख सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं।

वक्त के साथ अनुकूलन का विचार भी समझना जरूरी है। मनुष्य की प्रवृत्ति है नए अनुभवों के साथ अभ्यस्त हो जाना। नया घर, नई कार और उन्नति शुरुआत में खुशी देते हैं, पर समय के साथ उसकी तीव्रता घट जाती है। इस चक्र को तोड़ना है, तो अपनी चेतना एवं वैचारिक नवाचार को बनाए रखना जरूरी है।

दिन की शुरुआत हम एक धन्यवाद के विचार से कर सकते हैं। दोपहर में पांच मिनट गहरी और लयात्मक सांस ली जा सकती है। शाम को किसी प्रियजन से एक सच्ची बातचीत करनी चाहिए। इन छोटे-छोटे अभ्यासों का जोड़ अक्सर जीवन में बड़ा अंतर लाता है। जब हम समझते हैं कि खुशी एक क्षणभंगुर उपहार नहीं, बल्कि निर्विकल्प रूप से हमारे भीतर शासन करने वाली स्थिति है, तब जीवन के उभार-इतार के बीच भी हम एक स्थिर आनंद का पता लगा लेते हैं। यह आनंद किसी भी मौसम में खिल उठता है- कठिनाइयों में धैर्य बनकर, सफलता में नम्रता बनकर और रिश्तों में स्नेह बनकर। इसलिए खुश रहना किसी गंतव्य की अपेक्षा नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन की चुनी हुई प्रवृत्ति होनी चाहिए।

मताधिकार का सवाल



सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जल भुइयां की यह टिप्पणी कि 'लाखों नागरिकों को मताधिकार से वंचित करना संविधान के विरुद्ध है', लोकतंत्र की बुनियादी संवेदना से जुड़ा गंभीर सवाल उठाती है। मताधिकार केवल चुनाव के दिन मतदान करने का अधिकार नहीं, बल्कि नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी और संवैधानिक पहचान का आधार है। इसलिए किसी प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हट जाएं, तो इसे महज प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना जरूरी है। फर्जी और अपात्र नाम हटाना भी चुनाव की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। मगर इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी कट जाएं, तो सुधार की पूरी कवायद सवालों के घेरे में आ जाती है। हर मतदाता के पीछे एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार भी है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भी त्रुटि-सुधार और आपत्ति दर्ज कराने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता केवल एक संख्या नहीं, बल्कि जनविश्वास का आधार है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

खेल की बुनियाद

एशियन गेम्स-2026 में भारतीय खिलाड़ियों का 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहना उत्साहजनक उपलब्धि है। पुरुष और महिला हाकी टीमों का एक साथ स्वर्ण जीतना, महिला खिलाड़ियों की उल्लेखनीय सफलता और कई खेलों में नए कीर्तिमान देश के लिए गर्व का विषय है। मगर, पदकों की चमक के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष होता है। इसलिए असली सवाल यह है कि हम ऐसी प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए किस तरह की खेल संस्कृति विकसित कर रहे हैं। आज भी अनेक परिवार पढ़ाई और खेल को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं। स्कूलों में खेल का समय अक्सर पढ़ाई के दबाव में खत्म हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैदान, प्रशिक्षक, पोषण और प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जरूरत है कि गांवों में खेल मैदान विकसित हों, स्कूलों को प्रशिक्षक मिलें और पंचायत से जिला स्तर तक नियमित प्रतियोगिताएं हों।

– महेश कुमार, सिद्धमुख, राजस्थान

बदलती तस्वीर

'स्वशक्तीकरण का नया समाजशास्त्र' (विमर्श, 4 अक्तूबर) पढ़ा। जेन-जी और अल्फा-जी की लड़कियों को लेकर की गई टप्पणियां आज की बदलती सामाजिक तस्वीर का सटीक चित्रण है। नई पीढ़ी की लड़कियां समझ चुकी हैं कि अपने अधिकारों की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी। पहले आंदोलनों और प्रदर्शनों में लड़कों की कतार आगे और लड़कियां पीछे दिखाई देती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में अनेक जगहों पर लड़कियां आगे बढ़कर अपनी बात रख रही हैं और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही हैं। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पितृसत्ता और पुरुषवादी सोच के विरुद्ध उनका मुखर होना सामाजिक बदलाव का संकेत है। यह केवल क्षणिक आक्रोश नहीं, बल्कि अधिकारों के प्रति बढ़ती चेतना है। यह आवाज तब तक उठती रहेगी, जब तक महिलाओं की भागीदारी मजबूत नहीं होती।

– अशोक कुमार, बेगूसराय, बिहार

समाधान की राह

'संवाद के बजाय' (संपादकीय, 6 अक्तूबर) में स्पष्ट है कि लोकतंत्र में असहमति कोई अवांछित शोर नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। जनता ने जब सत्ता को अधिकार सौंपे हैं, तो उससे सवाल पूछना भी उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। शासन की पहली जिम्मेदारी इन सवालों को सुनना, समझना और उनका समाधान तलाशना है। खासकर युवाओं की आवाज को अनसुना करना उचित नहीं, क्योंकि वही देश का वर्तमान और भविष्य हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि संकल्प के साथ उठ खड़ा हुआ युवा किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकता है। मगर यह तभी संभव है, जब उसे उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलें। पेपर लीक, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसी समस्याएं युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती हैं। लोकतंत्र में संवाद जितना मजबूत होगा, शासन उतना ही जवाबदेह बनेगा।

– लक्ष्मी गुप्ता, अयोध्या

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

epaper.jansatta.com

संपादकीय

प्रश्न विश्वासाचा आहे!

मंगळवारी दिल्लीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता राहुल गांधींच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन केवळ विरोधकांचा राजकीय आक्रोश म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. आंदोलनादरम्यान राहुल गांधींनी चक्क बॅरिकेडवर चढून तिरंगा फडकवला. त्या कृतीने या मुद्द्यावरील विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा अधोरेखित झाला. या सगळ्या गदारोळामागचा खरा प्रश्न एका व्यक्तीच्या राजीनाम्यापेक्षा मोठा आहे आणि तो म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आहे, यावर नागरिकांचा विश्वास कायम आहे का? आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील मतभेद, मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्पडताळणी मोहीम (एसआयआर)साठीच्या फॉर्म ६ वरील वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत निर्माण झालेली विसंगती, या प्रश्नाला अधिक गंभीर बनवते. निवडणूक आयुक्तद्वय सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गत दहा महिन्यांत किमान चौदा वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले, असे वृत्त २३ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हकालपट्टीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली. आयोगाने मात्र आक्षेप नोंदवले गेल्याचे मान्य करतानाच, तो नियमित निर्णय प्रक्रियेचा भाग असून, सर्व निर्णय एकमताने झाले, असे स्पष्ट केले. या वादाला अधिक गंभीर वळण मिळाले ते एसआयआरसाठी फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राच्या मुद्द्यावरून! मे २०२६ मध्ये बिहारमधील एसआयआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर, जुलैमध्ये ऑनलाइन फॉर्म ६ सोबत हे अतिरिक्त घोषणापत्र वापरात आले. निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबरच्या निवेदनात या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता असल्याचे म्हटले; परंतु ५ ऑक्टोबरला सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले, की कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ला न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही. न्यायालयाने या बदलासंबंधी आयोगाचे मूळ रेकॉर्डही मागवले आहे. आयोगाचे म्हणणे असे आहे, की फॉर्म ६ मध्ये प्रत्यक्ष बदल करण्यात आलेला नाही, तर एसआयआरच्या काळात त्यासोबत एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आले आहे. आयोगाने जाणूनबुजून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा निष्कर्ष, सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा रेकॉर्ड तपासला जाण्याआधी काढणे योग्य ठरणार नाही; परंतु ज्या बदलाला न्यायालयाने मान्यता दिल्याचे आयोगाने म्हटले, त्याबाबत न्यायालयानेच वेगळी भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगाची खरी ताकद त्याच्या घटनात्मक अधिकारांइतकीच त्याच्या विश्वासार्हतेत असते; परंतु एक वैधानिक संस्था जेव्हा दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेच्या नावावर आपल्या निर्णयाला वैधता मागते, तेव्हा त्या दाव्यातील अचूकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याची आणि ती कशी झाली हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी आयोगाचीच आहे. लोकशाहीत आंदोलनांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहता कामा नये. संसद, न्यायालय आणि माध्यमे हे विश्वास टिकवण्याचे मार्ग अपुरे वाटू लागतात, तेव्हा रस्ताच लोकशाहीतील दबावाचा मार्ग बनतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया अवघड आहे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांना हटवणे धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवण्याइतके सोपे नाही. म्हणूनच निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपेक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, स्वतंत्र आढावा आणि निर्णयांच्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची यंत्रणा, ही अधिक ठोस मागणी ठरू शकते. आयोगाने कोणता निर्णय का घेतला, त्यासाठी कोणती नोंद झाली, आक्षेप कसे हाताळले गेले आणि न्यायालयीन निर्णयाचा आधार नेमका कसा घेतला गेला, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आंदोलने हाताळण्याच्या पद्धतीचाही संबंध विश्वासाशीच आहे. जंतर-मंतरवरील ३ ऑक्टोबरच्या निदर्शनांचे वार्तांकन करताना पोलिसांकडून लैंगिक गैरवर्तन झाल्याचा आरोप तीन महिला पत्रकारांनी केला. मंगळवारच्या आंदोलनादरम्यान तर महिला खासदारांशीच गैरवर्तन झाल्याचे आरोप झाले. अशा प्रकरणांमध्ये तपासाचा निष्कर्ष येईपर्यंत कोणालाही दोषी ठरवणे अयोग्यच; पण तपास निष्पक्षपणे चालला आहे, हे दिसणेही तितकेच आवश्यक आहे. निवडणुकांचा निकाल कोणत्या तरी एका बाजूनेच लागणार; पण जिंकणाऱ्याच्या जनादेशाची वैधता हारणाऱ्याच्या स्वीकारावरच टिकते. मतदानावरचा विश्वासच उडाला, तर निवडणुकीतील विजयाला नैतिक आधारच उरणार नाही. म्हणून प्रश्न केवळ बॅरिकेड्स या किंवा त्या बाजूचा नाही, तर त्या बॅरिकेड्सपासून अंतरावर उभ्या असलेल्या नागरिकांच्या विश्वासाचा आहे!

संसदेत मुस्लीम स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व इतके कमी का?

१९५२ पासून आजतागायत केवळ वीसच मुस्लीम महिला लोकसभेत येऊ शकल्या. आजही लोकसभेत केवळ दोनच मुस्लीम महिला आहेत!



शशी थरूर
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, खासदार

१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री, नियतीशी ठरवलेल्या संकेताचा आणि राष्ट्राच्या प्रदीर्घ काळ दडपल्या गेलेल्या आत्म्याला कंठ फुटल्याचा उद्घोष पंडित नेहरूंनी केला होता. परंतु, जवळजवळ आठ दशकांनंतर आजही जगातील या सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील सर्वच नागरिकांचा आवाज बुलंद होऊ शकत नाही. आपल्या संसदेत स्त्रियांना अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. देशाच्या लोकसंख्येत स्त्रियांचे प्रमाण ४८.५ % आहे; परंतु लोकसभेत केवळ १४ %च महिला आहेत.

त्यातही काही समाजघटकांतील महिलांची अवस्था इतर भगिनींपेक्षा बिकट आहे. १९५२ पासून आजतागायत केवळ वीसच मुस्लीम महिला लोकसभेत येऊ शकल्या आहेत. आज लोकसभेत केवळ दोनच मुस्लीम महिला आहेत. म्हणजे देशातील ७.१% लोकसंख्येचे सदनातील प्रतिनिधित्व केवळ ०.४% इतकेच आहे.

आधुनिक भारताच्या शिल्पकारांनी, स्त्रीमुक्ती हा विषय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आणि राष्ट्रउभारणीच्या केंद्रस्थानी ठेवला होता. या देशातील स्त्रिया शतकानुशतके चूल आणि मूल यातच अडकलेल्या होत्या. शिक्षणाची दारे त्यांना खुली नव्हती. सामाजिक आणि धार्मिक स्तरावर सगळीकडेच त्यांना मानहानी सोसावी लागत होती. स्त्रियांच्या अवहेलनेला कर्मठ धार्मिक रूढींची अधिकृत मान्यताच होती. एकोणिसाव्या शतकात ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय आणि जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी सती प्रथा, शिक्षणबंदी यासारख्या रूढींविरुद्ध आसूड ओढायला सुरुवात केली. न्यायासाठी आरंभलेल्या या संग्रामाचा वसा पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या धुरिणांनी हाती घेतला. आंबेडकरांच्या दृष्टीने स्त्रियांना समान हक्क मिळणे अनिवार्य होते. त्यांच्या मते स्त्रियांचे दमन हे जातीय शोषणाच्या केंद्रस्थानी होते. विशेषतः दलित स्त्रियांवर लादल्या गेलेल्या दुहेरी भेदभावाविरुद्ध त्यांनी तीव्र लढा पुकारला. स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणे हे आंबेडकरांना समाजातील नैतिकतेच्या अभावाचे लक्षण आहे असे वाटे. नेहरूंनी या मताशी सहमती दर्शवली. हे दोन्ही नेते समतावादी आधुनिकता रुजवू इच्छित होते, परंतु भारतीय समाजव्यवस्थेपुढे त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले.

त्यातही विशेषतः मुस्लीम महिलांना स्वातंत्र्याप्राप्तीपासूनच राजकारणाबाहेर ठेवले गेले आहे. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय लोकशाहीत सर्वांनाच दिले गेले असले तरीही मुस्लीम स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग अत्यल्प आहे. त्यांच्या कल्याणाशी निगडित असे घटस्फोटानंतरची पोटगी (शाहबानो प्रकरण), तिहेरी तलाक (सायराबानो प्रकरण) वगैरे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न संसदेत नव्हे, तर न्यायालयात किंवा नागरी मंचावर लढले गेले. संसदेत त्यांची उपस्थितीच नसल्याने तिथे त्यांचा आवाज उमटू शकला नाही.

खुद्द आपल्या घटना समितीच्या २९९ सदस्यांत केवळ १५च स्त्रिया होत्या आणि त्यात बेगम कुदसिया ऐझाज रसूल या एकमेव मुस्लीम महिला होत्या. त्या नागरी राष्ट्रवादाच्या पुरस्कर्त्या आणि जातीधर्माधारित प्रतिनिधित्वाच्या विरोधक होत्या. नंतरच्या काळात राज्यसभा सदस्य असताना त्यांना



स्वतःला लाभलेले विशेषाधिकार न मिळालेल्या मुस्लीम स्त्रियांची, धर्मांतर्गत वर्चस्वाच्या कोंडमाऱ्यातून सुटका करण्यासाठी, बलाढ्य विरोधाला तोंड देत त्या कार्यरत राहिल्या.

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, राजीनामा देऊन लोकसभा निवडणूक लढवण्याची परवानगी प्रांतीय विधिमंडळातील महिलांना द्यावी, असे आवाहन नेहरूंनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना केले होते. महिला खासदारांनी स्वतः कायदे बनवून आपल्या हक्कांची व्याप्ती वाढवावी ही नेहरूंची दृष्टी आजतागायत केवळ एक स्वप्नच राहिले आहे. २०२५ पर्यंत अस्तित्वात आलेल्या १८ लोकसभांपैकी पाच लोकसभांत एकही मुस्लीम महिला सदस्य नव्हती. कोणत्याही एका लोकसभेत त्यांची संख्या चारच्या पुढे गेली नाही. आज तर आपण त्याच्याही निम्म्यावर येऊन ठेपलो आहोत.

राष्ट्राच्या सर्वोच्च चर्चापीठात स्त्रियांचा आणि त्यातही अल्पसंख्याक समूहातील स्त्रियांचा सूर उमटणे अत्यावश्यक आहे, कारण सदनात बहुसंख्येने असलेल्या पुरुषांपेक्षा मूलतः वेगळे असे जिवंत अनुभव स्त्रियांपाशी असतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कौटुंबिक कायदे आणि समाज कल्याण यासंबंधीच्या धोरणांचा स्त्रियांवर होणारा परिणाम पुरुष नीट समजू शकत नाहीत.

विशेषतः अल्पसंख्याक महिलांना, लिंगाधारित आणि समुदायाधारित अशा दोन्ही प्रकारच्या भेदभावांचे दुहेरी ओझे वहावे लागते. त्या संसदेत असतील तर या सर्वाधिक असुरक्षित समुदायाच्या वास्तवाचे नेमके प्रतिबिंब कायद्यात नक्की पडू शकते. तसे झाले नाही तर जवळजवळ निम्म्या लोकसंख्येकडे आणि परिघावरील वंचितांच्या व्यथांकडे डोळेझाक करणारे कायदेच या देशात बनत राहतील.

अल्पसंख्याक स्त्रियांना संसदेत स्थान मिळण्यातील अडथळे योगायोगाने निर्माण झालेले नाहीत. राजकीय पक्षांत खोलवर रुजलेल्या पुरुषप्रधान संरचनेला आलेले ते कटू फळ आहे. उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेवर पुरुषांचाच वरचष्मा असतो. 'निवडून येण्याची शक्यता' नसल्याच्या सबबीखाली स्त्रियांना उमेदवारी नाकारली जाते. तळागाळात सक्रिय असलेल्या महिला राजकीय कार्यकर्त्यांचा लोकसभेकडे जाणारा मार्ग, प्रवेशद्वारावरच होणाऱ्या या अडवणुकीमुळे उमेदवारीच्या टप्प्यावरच ठप्प होतो. यात पुन्हा महिलांना तोंड द्यावा लागणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक अडथळ्यांची भर पडते. निवडणूक प्रचार मोहिमेसाठी निधी गोळा करण्याचे मार्ग मर्यादित असतात. घट्ट विणलेले संपर्कजाल उपलब्ध नसते. शिवाय स्त्रियांनी सार्वजनिक जीवनापेक्षा कुटुंबाकडे अधिक लक्ष पुरवावे अशी समाजाची अपेक्षा असतेच. यातून एक प्रकारचे व्यवस्थात्मक बहिष्करण आकाराला येते. जोवर राजकीय पक्ष, जिंकण्याची शक्यता असलेल्या मतदारसंघात स्त्रियांना उमेदवारी देत नाहीत आणि समाजमानस, स्त्रियांचे नेतृत्व फुलण्याआड येणारे सारे पूर्वग्रह मोडीत काढत नाहीत तोवर अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांचा संसदेतील सन्नाटा संपुष्टात येऊ शकणार नाही. दशकामागून दशके, सार्वजनिक स्तरावर जिथेतिथे नाशिक्ती, स्त्रियांचे सक्षमीकरण याबाबत निव्वळ तोंडपूजा चालू आहे. पण ती भाषणबाजी कधीच प्रत्यक्षात उतरू शकलेली नाही. महिला आरक्षण हे कदाचित या सापाचे उत्तर ठरू शकेल. अर्थात, आपण त्याची नीट अंमलबजावणी करू शकलो तरच!

प्रासंगिक

ताणतणाव, मानसिक थकवा टाळायचा असेल, तर फक्त हे करा..

नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ध्यान, सुदर्शन क्रिया अत्यंत उपयुक्त ठरते. मानसिक आजार जनजागृती सप्ताहानिमित्त विशेष लेख.



गुरुदेव श्री श्री रविशंकर
आध्यात्मिक गुरू

आजकाल ताणतणाव देवासारखाच सर्वव्यापी झाला आहे. तो सर्वत्र पसरलेला आहे. पण तणाव म्हणजे नक्की काय? माझ्या मते, 'खूप जास्त काम, अतिशय कमी वेळ आणि ते काम करण्याची अजिबात ऊर्जा नसणे' म्हणजेच ताणतणाव होय.

जेव्हा ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकून राहते, तेव्हा ताणतणाव तुम्हाला इतका थकवून टाकतो की, दिवसाची सुरुवात होण्यापूर्वीच तुम्हाला प्रचंड थकवा जाणवू लागतो. यालाच आजच्या भाषेत आपण 'बर्नआऊट' असे म्हणतो.

आता यातून बाहेर कसे पडायचे? यावर दोन पर्याय असू शकतात: एक तर कामाचा ताण कमी करणे, जे आजच्या काळात शक्य दिसत नाही; किंवा उपलब्ध वेळ वाढवणे, जेदेखील अशक्यच वाटते. त्यामुळे आपल्यासमोर उरलेला एकमेव पर्याय म्हणजे आपली ऊर्जा पातळी वाढवणे.

जेव्हा आपल्याकडे पुरेशी ऊर्जा आणि उत्साह असतो, तेव्हा आपण कोणत्याही आव्हानाला सहज सामोरे जाऊ शकतो आणि ते पेलू शकतो. आपल्याला आपली ऊर्जा पातळी वाढवण्याची गरज आहे आणि इथेच ध्यान तसेच सुदर्शन क्रियेसारख्या श्वासोच्छ्वासाच्या पद्धती आपल्याला प्रचंड मदत करतात.

या सर्व तंत्रांमुळे अवघ्या काही मिनिटांतच आपली ऊर्जा पातळी उंचावते. झोप घेणे नक्कीच



महत्त्वाचे आहे, परंतु झोपेमुळे मिळणारी विश्रांती ही एक सुस्तावलेली विश्रांती असते.

याउलट, सचेतन विश्रांती ही ध्यानातून मिळते. ध्यान म्हणजे केवळ शांत बसून विचार करत राहणे नव्हे. अनेक लोक मनातल्या मनात खूप काम करत असतात; ते विविध गोष्टींची कल्पना करतात, चित्रे रेखाटतात. दुर्दैवाने, याला ध्यान म्हणत नाहीत.

ध्यान म्हणजे पूर्णपणे सर्व सोडून देणे आणि मोकळेपणाने विश्रांती घेणे होय. ८ ते १० तासांच्या झोपेपेक्षा २० मिनिटांच्या ध्यानातून लोकांना अधिक ऊर्जा मिळाल्याचा अनुभव आहे. ऊर्जेचे मुख्य चार स्त्रोत आहेत: अन्न, झोप, श्वास आणि मनाची शांत व ध्यानस्थ अवस्था. संतुलित आणि पौष्टिक अन्न योग्य प्रमाणात खा; ६ ते ८ तासांची पुरेशी झोप घ्या (ना कमी, ना जास्त); खोल श्वास घेण्याची काही तंत्रे शिका; आणि सकाळी व संध्याकाळी १५ ते २० मिनिटे ध्यान करा. संपूर्ण दिवसभर तुम्हाला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी हे पुरेसे आहे. तुमच्या ऊर्जा पातळीत झालेला फरक तुम्हाला लगेचच दिसून येईल.

आध्यात्मिक ज्ञानामुळेदेखील तुम्हाला एका वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा मिळते आणि ध्यान तर या सर्वांमध्ये सर्वात श्रेष्ठ आहे. ध्यानाव्यतिरिक्त, जेव्हा भावना तुमच्या बुद्धीचा ताबा घेतात, तेव्हा मानसिक संतुलन परत मिळवण्यासाठी श्वास हे एक अतिशय व्यावहारिक साधन ठरू शकते.

भावनांच्या आवेगावर मात करण्यासाठी सुदर्शन क्रिया अत्यंत उपयुक्त ठरते. नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे एका स्वयंचलित व्हॉल्व्ह सिस्टीमसारखे काम करते.

जगभर

'लो सोनो जॉर्जिया'.. मी जॉर्जिया मेलोनी आहे!

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी कायम कुठल्या ना कुठल्या कारणानं चर्चेत असतात. आता त्या आणखी एका वेगळ्याच कारणानं चर्चेत आल्या आहेत. आपल्या आजाजाचा गैरवापर होऊ नये आणि एआयच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या डीपफेकपासून संरक्षण मिळावं, यासाठी आपल्या आजाजाचा ट्रेडमार्क करण्यासाठी त्यांनी यूरोपियन युनियनच्या बौद्धिक संपदा कार्यालयाकडे (EUIPO) अर्ज केला आहे. असं पाऊल उचलणाऱ्या त्या जगातील पहिल्या विद्यमान नेत्या आहेत.

अर्जासोबत त्यांनी सुमारे ४ सेकंदांची ध्वनिमुद्रणाची क्लिपही जमा केली आहे. या क्लिपमध्ये त्या इटालियन भाषेत दोनदा 'लो सोनो जॉर्जिया' असं म्हणतात. याचा अर्थ 'मी जॉर्जिया मेलोनी आहे' असा होतो. मेलोनी यांच्या २०२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या आत्मचरित्राचं नावही 'लो सोनो जॉर्जिया' असंच आहे. हे वाक्य त्यांच्या राजकीय प्रचाराशीही जोडलेलं आहे.

जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासाठी डीपफेकचा धोका नवीन नाही. २०२४ मध्ये त्यांच्या छायाचित्राचा वापर करून बनावट अश्लील व्हिडिओ तयार करण्यात आले आणि ते इंटरनेटवर पसरवण्यात आले. त्यानंतर मेलोनी यांनी हे व्हिडिओ तयार करणाऱ्या आणि पसरवणाऱ्या व्यक्तींविरोधात १ लाख यूरो नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.

यावर्षी मे महिन्यातही त्यांनी डीपफेकच्या वाढत्या धोक्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. मेलोनी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं होतं की, ही समस्या केवळ त्यांच्यापुरती मर्यादित नाही. डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर एखाद्याची फसवणूक करण्यासाठी, त्याची प्रतिमा खराब करण्यासाठी किंवा त्याला लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्या म्हणाल्या होत्या, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्यांच्यासारख्या व्यक्तींकडे अनेक साधनं उपलब्ध असू शकतात, मात्र



अशा प्रकारच्या गैरवापरासाठी सामना करण्यासाठी सामान्य लोकांकडे काहीच नसतं आणि त्यांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो, होऊ शकतो.

एखाद्या व्यक्तीच्या आवाजाची नक्कल करण्यासाठी एआयला त्या व्यक्तीच्या खऱ्या आवाजाची ध्वनिमुद्रणं दिली जातात. त्यातून एआय त्या व्यक्तीच्या बोलण्याची पद्धत, आवाजातील चढ-उतार, उच्चार आणि इतर वैशिष्ट्यं शिकतं. त्यानंतर त्याच आवाजासारखी नवीन वाक्यं आणि ध्वनिमुद्रणं तयार करता येतात, जी संबंधित व्यक्तीनं ती वाक्यं प्रत्यक्षात कधीही बोललेली नसली तरी! आवाजाची नक्कल करण्यासाठी काही सेकंदांचं ध्वनिमुद्रणही पुरेसं ठरू शकतं. एआयचा वापर वाढत असताना आवाज हा डिजिटल ओळखीचा महत्त्वाचा भाग बनत चालला आहे. त्यामुळे कलाकार आणि प्रसिद्ध व्यक्ती आपल्या आवाजाचं, नावाचं आणि ओळखीचं संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधत आहेत.

अमेरिकन अभिनेता मॅथ्यू मॅककॉनॉघी यानं जानेवारीत आपल्या छायाचित्रासोबत आवाजाचं ट्रेडमार्क करण्यासाठी अर्ज केला होता. ऑगस्टमध्ये ब्रिटनमधील ८० हून अधिक कलाकारांनी तत्कालीन पंतप्रधान ॲंडी बर्नहॅम यांच्याकडे लोकांच्या आवाजाच्या वापरावर कायदेशीर अधिकार देणारा कायदा करण्याची मागणी केली होती.

गायिका टेलर स्विफ्ट यांनीही एप्रिलमध्ये अमेरिकेत तीन ट्रेडमार्क अर्ज दाखल केले. त्यापैकी एक त्यांच्या छायाचित्राशी, तर दोन अर्ज त्यांच्या आवाजाशी संबंधित आहेत. त्यात त्यांच्या दोन छोट्या ध्वनिमुद्रणांचा समावेश आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये त्या स्वतःची ओळख करून देताना 'हे, इट्स टेलर' आणि 'हे, इट्स टेलर स्विफ्ट' असं म्हणतात.

जनमन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि विद्यापीठे



कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही उच्चशिक्षण क्षेत्रासमोरील सर्वात मोठ्या परिवर्तनकारी शक्तीपैकी एक आहे विद्यापीठांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करावा की नाही, हा प्रश्न आता राहिलेला नाही. प्रश्न हा आहे एआयचा वापर जबाबदारीने आणि नैतिकतेने कसा करायचा? एआय अध्यापन, मूल्यमापन, संशोधन, प्रशासन आणि विद्यार्थी सेवा यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवू शकते. त्याचवेळी शैक्षणिक प्रामाणिकता, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा आणि शिक्षकांच्या बदलत्या भूमिकेसारखे प्रश्नही निर्माण होतात. म्हणून भविष्यातील विद्यापीठ हे एआय एनेबेल्ड पण ह्यूमन सेंटर्ड असले पाहिजे. तंत्रज्ञानाने शिक्षकांची भूमिका संपवू नये उलट ती अधिक प्रभावी करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात चिकित्सक विचार, नैतिक निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता, सहानुभूती आणि मानवी विवेकाचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे. उच्चशिक्षणाचे भविष्य ही विद्यापीठे जागतिक स्पर्धा, सामाजिक बांधिलकी आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टे यांचा समन्वय किती प्रभावीपणे साधतात यावर अवलंबून आहे. भारताला परदेशी विद्यापीठांचे केवळ अनुकरण नको आहे. भारताच्या बौद्धिक परंपरेतून आणि आधुनिक आकांक्षांमधून शक्ती घेऊन जागतिक मान्यता मिळविणारे ज्ञान निर्माण करणारी विद्यापीठे आवश्यक आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या झपाट्याने होणाऱ्या विकासामुळे विद्यापीठांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. शिक्षकांनाही कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साधने समजून घेऊन त्यांचा योग्य तापर शिकावा लागेल. त्याचबरोबर माहितीची अचूकता, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा आणि नैतिकतेचे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.

- राजू जाधव, मांगूर, जि. बेळगाव

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

सेतू

'घरात मी किती करतो'.. ही बढाई पुरुषांमध्ये चुकूनही दिसत नाही!

पोलंडमध्ये घर ही दोघांची जबाबदारी असते. पोलिश बायका नवऱ्यांबद्दल-तो स्वयंपाक करतोय, वाणसामान आणायला गेलाय, असं सहज सांगतात.



अवनी दाते
१२ वर्षांपासून पोलंडमध्ये वास्तव्य

एखादी स्त्री आपल्या संसारासाठी त्याग करते, कष्ट करते तेव्हा त्याची चर्चा होत नाही. ते तिचं कामच आहे असं आपण गृहीत धरतो. तेच पुरुष संसारासाठी पैसे कमावण्याव्यतिरिक्त जे जे करतो त्याचं मात्र विशेष कौतुक होतं. इथे पोलंडमध्ये मात्र तसं नाही. संसार आणि संसारातल्या जबाबदाऱ्या इथले पुरुष अगदी सहज निभावतात. त्या निभावताना 'मी किती करतो' हा आविर्भाव तर अजिबात नसतो.

घर ही फक्त बायकोची नाही, तर दोघांचीही जबाबदारी असते असं इथले पुरुष मानतात आणि तसंच सहज जगतातसुद्धा. हे मला कधी जाणवलं त्याचीही एक गोष्ट आहे. पोलिश पुरुष स्त्रियांशी अत्यंत अदबीनं आणि सन्मानानं वागतात. छोट्या छोट्या कृतींतूनही हा आदर जाणवतो. एखादी स्त्री येताना दिसली की दरवाजा उघडून धरणं, लिफ्टमध्ये तिला आधी जाऊ देणं, बस किंवा ट्राममध्ये वयस्कर महिला, गरोदर महिला किंवा लहान मूल असलेल्या आईला जागा देणं त्यांच्याकडून अगदी सहज घडतं. तसे संस्कारच त्यांच्यावर झालेले असतात.

एकदा मी पोलिश मित्र-मैत्रिणींना घरी बोलवलं होतं. जेवल्यानंतर आईस्क्रीम सर्व्ह करताना माझ्याकडून ते पुरुषांना आधी दिलं गेलं. माझ्या या कृतीचं सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं. एक मित्र म्हणाला, 'तू असं का केलंस?' त्यावर मी गोंधळून विचारलं, 'का? काय झालं?' तो मित्र म्हणाला, 'आधी बायकांना वाढायला हवं!' त्याच्या या छोट्याशा वाक्यातून व्यक्त झालेला आदर मला मनापासून भावला. पोलिश



मैत्रिणींना त्यांच्या नवऱ्यांबद्दल विचारलं की- तो स्वयंपाक करतोय किंवा वाणसामान आणायला गेलाय अशी उत्तरं मिळतात.

मिहाद हा त्यांपैकीच एक. मूलांना शाळेत सोडणं-आणणं, स्वयंपाक, सणासुदीचे पदार्थ, वर्षभरासाठी जॅम आणि लोणची करणं ही कामं तो मनापासून करतो. एकदा मुलगा आयर्लंडशिवाय शाळेत आला. कारण विचारण्याआधीच मिहाद म्हणाला, काल माझी लॉन्ड्री लावायचीच राहिली.. मी त्याच्याकडे कौतुकानं बघतच राहिले. एकदा यारोस्लावाने आम्हाला घरी जेवायला बोलवलं होतं. आम्ही गेल्यावर ती आमच्याशी गप्पा मारत बसली आणि तिचा नवरा यकयान जेवणाचं टेबल लावू लागला. साधा स्वयंपाक यारोस्लावानं केल्यामुळे मागचं-पुढचं आवरायची जबाबदारी त्यानं आनंदानं घेतली होती.

जेवल्यावर डेझर्ट म्हणून केक होता. पण तो यकयाननं बेक केल्यामुळे तो सर्व्ह तिनं करायचा असं त्यानं सांगितलं. त्यांचं हे कामांचं शेअरिंग बघून मला कौतुकच वाटलं. पोलिश घरात आल्यागेल्याला चहा-कॉफी पुरुषच विचारतात. कुणाला काय आवडतं, जमतं यावर कामाची विभागणी ठरते.

माझी एक पोलिश मैत्रीण उला. तिला स्वयंपाक करायला आवडत नाही. खरेदी, ड्रायव्हिंग मात्र आवडतं. त्यामुळे ती बाहेरची कामं करते, नवरा स्वयंपाकाचं बघतो. छोटं बाळ असेल तर दिवसभर आई त्याला सांभाळते; पण कामावरून आल्यावर बाबा त्याची जबाबदारी घेतो आणि आईला ब्रेक देतो, तेही न कुरकुरता, आनंदानं घर दोघांचं, संसार दोघांचा, तर त्याच्या जबाबदाऱ्याही दोघांच्याच हे पोलिश तत्त्वज्ञान मला फार आवडतं!

neenaadate@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे



हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८५ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पूर्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०७ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०५७०८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. ५०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५१३०, ०२२- ४७७०७४४६. ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४९२००, २५४८५७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पूर्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०७. फोन : ०२२ ४६०५७०८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत * हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे व्यापारचिन्ह आहे.

प्रेरणा

जो हमें जीवन के प्रति आशा और उत्साह जगा सके, वही सही अर्थों में प्रेम है। -ओशो

संपादकीय

लगातार घटती लोकप्रियता का असर दिख रहा है ट्रम्प पर

ट्रम्प के ताजा बयान ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान भले ही हमला करके कैलिफोर्निया या उसके शहरों- लॉस एंजेलेस और सैन डिआगो को हड़प ले, लेकिन दुनिया और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए यह सस्ता सौदा होगा। इस पर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रम्प की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाया है। कैलिफोर्निया की अधिकांश जनता ट्रम्प को वोट नहीं करती। प्रश्न यह है कि क्या ईरान हजारों किमी दूर यूएस पर हमला कर इस राज्य और उसके सैन डिआगो मिलिट्री बेस पर कब्जा कर सकता है? अमेरिका को फिर से 'ग्रेट' बनाने के नारे में क्या उसका सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे अहम राज्य ही नहीं आता? वास्तव में अमेरिका में ट्रम्प की लोकप्रियता बेहद घटी है और दो माह बाद मध्यावधि चुनाव हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है। ईरान लगातार अमेरिका से लोहा ले रहा है। उधर विश्व राजनीति की मर्यादा को तोड़ते हुए ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को हड़पने की बात भी कही थी, लेकिन जब विश्व समुदाय इसके खिलाफ दिखा तो अब एक समझौता किया है। ट्रम्प के मनमाने रवैये से पूरा यूरोप- जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका के साये में चल रहा था- अचानक तनकर खड़ा हो गया, लिहाजा ट्रम्प को ग्रीनलैंड पर पैर वापस खींचने पड़े। ऐसे में ट्रम्प ईरान पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो युद्ध के मानवीय मूल्यों के खिलाफ हो। पर क्या अमेरिकी जनता अमानवीय नरसंहार को जीत मानेगी?

जीने की राह



पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

धर्म-अध्यात्म भी बचा रहे और तकनीक का उपयोग भी करें

मेरी विदेश यात्राओं के दौरान मुझसे सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यह रहा कि एआई को आप आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? एआई के उपयोग में हमें विवेक का प्रयोग लगातार करना पड़ेगा, वरना हम जान ही नहीं पाएंगे कि यह खुशबू कब दुर्गंध में बदल जाएगी। हमारे यहां एक शब्द है- 'उभय भांति'। हमें दोनों ही स्थितियों में काम करना आना चाहिए। हमारा धर्म और अध्यात्म भी बचा रहे और हम तकनीक का उपयोग भी करें। यह प्रयोग श्रीराम ने किया था। जब विभीषण उनकी शरण में आए तो अधिकांश लोगों ने सलाह दी कि शत्रु का भाई है, बंदी बना लें। लेकिन राम ने कहा था- 'उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत।' दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। हनुमान जी अंगद लेने चले गए। राम जी यह कहते हैं कि वो शत्रुभाव से आया है तो लक्ष्मण काफी हैं और शरणागति से आया है तो मेरी नीति ही शरणागति की है। एआई विभीषण की तरह हमारे सामने है। हमें 'उभय भांति' की तरह उसका उपयोग करना चाहिए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

वटवृक्ष

ड्रइंगरूम के कमरे में खिड़की के पास रखा
एक छोटा-सा बोनसाई बरगद

वो झांकता है खिड़की से बाहर जब भी
तो दिखाई देता है उसे अपना एक हमशक्ल
लेकिन कद-काठी में कहीं अलग

वो विशाल वटवृक्ष अपने आप में
जाने कितने जीवन समेटे हुए है
चींटियों के टीले हैं नीचे
ऊपर घोंसले परिन्दों के
जहरीले सर्प भी हैं
और हैं नन्ही गिलहरियां भी
शाख में उसकी पीपल है
और कहीं बीच में अशोक भी है
लताएं तो बेहिसाब हैं

बोनसाई भी देखना चाहता है खुला आकाश
वो फैलाना चाहता है भुजाएं, जटाएं, शाखाएं
बोनसाई भी बन जाना चाहता है
एक विशाल वटवृक्ष!

–गौरव गुप्ता, भोपाल, मध्यप्रदेश
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

गर्मियों के लिए अभी से बचाएं पानी

इस साल बरसात सामान्य से कम हुई है और नदी-तालाब पूरे नहीं भर पाए हैं। ऐसे में गर्मियों में जलसंकट की आशंका के चलते हमें अभी से पानी का सोच-समझकर उपयोग करना होगा। नदी और तालाबों में पानी बचा तो गर्मी में परेशानी कम आएगी।
–साजिद अली, इंदौर, मध्यप्रदेश

आरक्षण पर किसी को नीचा न दिखाएं

पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला के आरक्षण संबंधी बयान पर राज्य में राजनीति गरमा गई है। कई समुदाय उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। आरक्षण पर बहस संविधान, सामाजिक न्याय के आधार पर होनी चाहिए। किसी जाति को ऊंचा या नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। –कांतिलाल मांडोत, सूरत, गुजरात

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

मन की प्रयोगशाला

निगेटिव फीडबैक में भी पॉजिटिविटी हो

आईआईएम सिरमौर और टीआईएसएस मुम्बई के अध्ययन हमें निगेटिव फीडबैक में भी सकारात्मक भाव के असर को बताते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि नकारात्मक फीडबैक देते हुए भी सकारात्मक या तटस्थ भाव रखा जाए तो इस फीडबैक के स्वीकार होने की सम्भावना अधिक होती है। यानी मायने सिर्फ यह नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये भी रखता है उसे कैसे कहते हैं।

विशेष • प्रधानमंत्री मोदी के शासन-दायित्व के 25 वर्ष नई ऊर्जा और नई दिशा की यात्रा के साक्षी हैं

2047 तक विकसित भारत का विराट संकल्प

अभिनंदन



नितिन नवीन
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

बात वर्ष 2012 की है। मुझे गुजरात के आणंद जिले में आयोजित सद्भावना मिशन के एक कार्यक्रम में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में शामिल होने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि जिले के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष मेले का आयोजन किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दिन लोगों के बीच रहे। वे उनकी बातें सुनते, समस्याओं को समझते और समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते रहे।

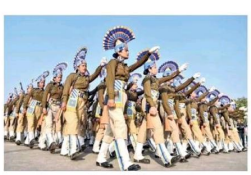
कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे पूछा कि वे पूरे दिन स्वयं क्यों जुटे रहे। उन्होंने सहज भाव से कहा, ये लोग केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आते। उनका मुझसे आत्मीय संबंध है। उनकी भावनाएं मुझसे जुड़ी हैं। इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ रहना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका यह उत्तर उस समय जितना सरल लगा, आज 25 वर्षों के उनके सार्वजनिक जीवन को देखते हुए उतना ही गहरा अर्थ लिए दिखता है। जनता से संवाद और उनकी समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी मानना उनकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। मोदी जी के सार्वजनिक जीवन की 25 वर्षों की यात्रा को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो, तो वह है- जनविश्वास।

कालखंड वही अमर होते हैं, जो राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा और उसके सपनों को नई दिशा देते हैं। मोदी जी के शासन-दायित्व के 25 वर्ष ऐसी ही यात्रा के साक्षी हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह यात्रा आज 25 वर्षों के पड़ाव को पूरा कर चुकी है। निराशा से उम्मीद, उम्मीद से भरोसा और भरोसे से संकल्प तक यह यात्रा केवल बदलते भारत ही नहीं, उस बढ़ते आत्मविश्वास की भी कहानी है, जिसने देश की आकांक्षाओं को नई दिशा और राष्ट्र के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की।

स्वतंत्रता से पहले देश के सामने एक स्पष्ट ध्येय था- भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना। उस ध्येय ने भाषाओं, क्षेत्रों और वर्गों में बंटे समाज को एक सूत्र में बांधा और हर सामान्य व्यक्ति को योगदान का अवसर दिया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के कार्य हुए, पर उतना स्पष्ट और साझा लक्ष्य कम ही दिखाई दिया। राष्ट्र को लक्ष्य इसलिए चाहिए कि लक्ष्य ही सामान्यजन की ऊर्जा को दिशा देता है। 2010 के आसपास देश में निराशा का वातावरण था- भ्रष्टाचार की खबरें, सुरक्षा को लेकर चिंता और व्यवस्था में भरोसे की कमी थी। इसी के बीच मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद जगी और देश नई दिशा की ओर बढ़ा।

प्रधानमंत्री जी ने भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने की बात की और यह कहा कि अब देश को छोटे सपने देखने की आवश्यकता नहीं, देश को बड़े सपने देखने चाहिए- 2047 तक विकसित भारत। आज यह 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बन चुका है, जिसमें विकास का अर्थ गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, आदिवासी और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में अवसरों का विस्तार हो।

एक समय प्रश्न था, क्या भारत यह कर सकता है? आज प्रश्न है, भारत और क्या कर सकता है? यही



अपने सपनों की दिशा में...

इन 25 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल विकास की गति ही नहीं, बल्कि यह विश्वास भी है कि भारत बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार करने का सामर्थ्य भी रखता है। आज देश अपने सामर्थ्य, संकल्प और सामूहिक शक्ति के साथ उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उम्मीद से भरोसे की ओर बढ़ते भारत की कहानी है।

मोदी जी के सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए उनके संगठनात्मक संस्कारों को समझना जरूरी है। एक समर्पित स्वयंसेवक के रूप में काम करने से उनके भीतर यह भाव मजबूत हुआ कि सार्वजनिक जीवन का अर्थ पद नहीं, दायित्व है और राजनीति का अर्थ सत्ता नहीं, सेवा है। जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, तब राज्य 2001 के विनाशकारी भूकंप के मलबे और आंसुओं से जूझ रहा था। भुज और कच्छ के पुनर्निर्माण की उस कठिन चुनौती को उन्होंने जिस इच्छाशक्ति से संभाला, उसने आगे चलकर विकास और आपदा-प्रबंधन के वैश्विक मॉडल का रूप लिया।

इसी सेवा-संस्कार को उन्होंने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन की रीढ़ बनाया। वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास हुआ। डीबीटी ने लाभार्थियों के हक की पाई-पाई सीधे उनके खाते में पहुंचाकर कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी और सशक्त बनाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत केवल योजनाओं की घोषणाओं का देश नहीं है, बल्कि असंभव को संभव करने वाला राष्ट्र है। जिन गांवों को कभी सरकारी फाइलों में देश का आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी ने उन्हें देश का प्रथम गांव बनाया। विकास तभी पूर्ण होता है, जब समाज का कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण पीछे न छूटे।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारी सामूहिक आकांक्षा और संकल्प है। एक प्रसिद्ध विचार है कि राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि राष्ट्रनायक अगली पीढ़ी के बारे में। हमारी परंपरा में इसी दूरदृष्टि को राष्ट्र-निर्माण का आधार माना गया है। 25 वर्ष पहले एक स्वयंसेवक ने गुजरात में शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। आज उसी यात्रा ने हमारे सामने 2047 के विकसित भारत का विराट संकल्प रखा है।

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

सुर्खियों से आगे • वर्षा को भगाएं नहीं, स्वागत करें

समृद्ध संगीत, साहित्य और कमजोर मानसून

मेघ मल्हार



नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

इस बार मानसून बेहद कमजोर रहा। इसे बिहार में आई बाढ़ से जोड़कर मत देखिए। वो तो नेपाल से छोड़े गए बेहिसाब पानी का परिणाम है। कमजोर मानसून के कारण कई राज्यों के कई हिस्सों में फसलें चौपट हो गईं। कहीं पैदावार प्रभावित हुई। कहीं किसानों को बीज तक नसीब नहीं हो सका।

दरअसल, हमने अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे। हमारे किसानों ने ज्यादा से ज्यादा फसल के चक्कर में जंगल, बीड़ तो छोड़ी ही नहीं, मेड़ें तक को मिनिएचर बना दिया। हरियाली गायब हो गई। नतीजा यह हुआ कि बादलों को बुलाया देने वाला कोई नहीं बचा। न पेड़, न हरियाली। जैसे शहर कंक्रीट के जंगल बन गए, वैसे ही गांव और खेतों ने भी हरियाली का दामन छोड़ दिया।

हमने अपने बच्चों को भी यह नहीं सिखाया कि बारिश का हमारे देश के संदर्भ में महत्व क्या है। उसका उपयोग, उसकी महत्ता समझाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से हमने बच्चों को पहली कविता क्या सिखाई?

'रेन-रेन गो अवे,
कम अगेन अनॉदर डे। लिट्टिल बेबी वॉन्ट्स टु प्ले,
रेन-रेन गो अवे।'

मतलब, 'बच्चे खेलना चाहते हैं, इसलिए बारिश, अभी तू जा। फिर कभी आना।' पश्चिमी देशों में बार-बार बारिश होती है इसलिए उन्होंने यह कविता बनाई। हमारे यहां ऐसा कहां है? हमारे बच्चे तो बारिश में ज्यादा अच्छे से खेलना-कूदना चाहते भी हैं और जानते भी हैं। फिर हम क्यों सिखा रहे हैं- 'रेन-रेन गो अवे...?' पहले से ही कम हो रही है और हम कह रहे हैं अभी तू जा। फिर कभी आना। कोई ठहरकर सोचने को तैयार नहीं है। इसके उलट महाराष्ट्र- जहां के अधिकांश हिस्सों में इस बार भले ही सूखा पड़ा हो- लेकिन उन्होंने बारिश को बुलाने वाली कविता रची-

'येरे-येरे पावसा,
तुला देतो पैसा,
पैसा झाला खोटा, पाउस आला मोठा।'

मतलब- 'आओ-आओ बारिश, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसा भले खोटा निकला लेकिन बारिश जमकर आई।'

जाने क्यों हम पश्चिम के अंधानुकरण में फंसे हैं। अगर इसी तरह हम कविता गा-गाकर बारिश को भगाते रहे तो आने वाली पीढ़ी बारिश का महत्व भला कैसे जानेगी? उसे सहेजने और सम्भालने की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है।

हां, हिंदुस्तानी कण्ठ-संगीत में जरूर बारिश के लिए तरह-तरह से आह्वान किया जाता है। लेकिन उसे गाने वाले अब कम हैं और सुनने वाले और भी कम। वहां बात हो रही है राग मल्हार की। दरअसल, मल्हार एक राग-परिवार है। इसके सदस्य के रूप में कई राग हैं, जिनमें प्रमुख हैं- मियां की मल्हार, गौड़ मल्हार, मेघ मल्हार, सूर मल्हार, रामदासी मल्हार, नट मल्हार, जयंत मल्हार, शुद्ध मल्हार, धानी मल्हार आदि।

देखिए इन रागों में वर्षा का आह्वान कैसे किया जाता है। जैसे मियां की मल्हार में बंदिश- 'घन गरजत- बरसत बूंद-बूंद...।' मेघ मल्हार की बंदिश- 'सखी बदरा बरसे झनन-झनना।' गौड़ मल्हार- 'गरजत, बरसत सावन आयो रे...।' हर

जाने क्यों हम पश्चिम के अंधानुकरण में फंसे हैं। अगर इसी तरह हम 'रेन-रेन गो अवे' गा-गाकर बारिश को भगाते रहे तो आने वाली पीढ़ी बारिश का महत्व भला कैसे जानेगी? उसे सहेजने और सम्भालने की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है।

जगह बारिश का स्वागत,... लेकिन हम क्या सीख और सिखा रहे हैं- 'रेन-रेन गो अवे।'

अब अंत में आते हैं बिहार की बाढ़ पर। यहां इस बाढ़ के कारण बरसों से बेघर होते आए लोगों के लिए महान कवि कुसुमाग्रज की ये कविता-

'गंगा माई पाहुनी आली, गेली घरट्यात राहुन...।'

हिंदी में देखिए :...

'गंगा मैया आई थी, मेहमान बनकर।
कुटिया में रहकर गई,
मायके आई हुई लड़की की तरह।
चारों दीवारों पर नाची।
खाली हाथ अब जाती कैसे?
खैर से पत्नी बची है,
दीवार चूरा हो गई,
चूल्हा बुझ गया।
जो था, नहीं था, सब गया!
परसाद में पलकों के नीचे,
चार कतरे रख गई है पानी के।'

विश्लेषण • नियुक्तियों पर प्रियंका गांधी की छाप

यूपी की सियासत में कांग्रेस की रणनीति अब बदल रही है

राजनीति



आरती जेरथ
राजनीतिक टिप्पणीकार
aratijerath@gmail.com

यूपी की राजनीतिक बिसात अब आकार लेने लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक दिलचस्प चाल चलते हुए एक ब्राह्मण महिला आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह फैसला कांग्रेस का साहसिक दांव है- उस समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश, जो मंडल-कमंडल की राजनीति से यूपी का राजनीतिक परिदृश्य बदलने के बाद से ही भाजपा का मजबूत समर्थक रहा है। कांग्रेस भाजपा के गढ़ में जाकर उसी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है।

यूपी में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर 2% से थोड़ा ही अधिक था। ऐसे में भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की उसकी यह कोशिश महत्वाकांक्षी भी है और दुस्साहसी भी। शायद राम मंदिर में चंदे की कथित हेराफेरी से पार्टी का हौसला बढ़ा है। यह देखना बाकी है कि क्या ब्राह्मण समुदाय फिर से उस पार्टी के साथ जाएगा, जिसका उसने अतीत में समर्थन किया था। जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा हारती है, तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में ही होगी।

वास्तव में, कांग्रेस घूम-फिरकर फिर से इंदिरा गांधी की राजनीति की ओर लौटती हुई नजर आ रही है। इंदिरा ने ही ब्राह्मण-दलित-अल्पसंख्यक का मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था, जिसके सहारे कांग्रेस 1971 में यूपी की सत्ता में वापसी करने में सफल हुई थी। इससे पहले 1967 में संयुक्त विधायक दल के समाजवादी-जनसंघ गठबंधन ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। यह गठजोड़ 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के उभार तक कायम रहा था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भाजपा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद से वे पार्टी के साथ बने रहे।

दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी ने भाजपा से मुकाबला करने और यूपी में अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए पहले मंडल की राजनीति को आजमाने का फैसला किया था। उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में 90 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जो कांग्रेस की ओर से अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। लेकिन यह रणनीति काम नहीं आई और अखिलेश यादव ने यह चुनाव जीत लिया।

ओबीसी वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश उन्होंने इसके बाद भी जारी रखी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। लेकिन अब लगता है कि उन्हें अपनी इस रणनीति की निरर्थकता समझ में आ गई है और उन्होंने अपनी दादी की रणनीति से सबक लेने का फैसला किया है। यूपी कांग्रेस के नए पदाधिकारियों के चयन में बीडीए सामाजिक गठजोड़ को फिर से खड़ा करने की कोशिश साफ दिखाई देती है। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष मुस्लिम (इमरान मसूद) हैं। दो वरिष्ठ उपाध्यक्षों में से एक (आलोक प्रसाद) दलित हैं और पांसी समुदाय से आते हैं। दूसरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष देविंदर निघाट ईसीई हैं और नाविक समुदाय से आते हैं।

इन नियुक्तियों पर प्रियंका गांधी वाड्रा की छाप भी बहुत साफ दिखाई देती है। अनुराधा मिश्रा 'मोना' को उनका करीबी माना जाता है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चले 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान में प्रियंका के साथ मिलकर काम

एक तरफ कांग्रेस का बीडीए और समाजवादी पार्टी का पीडीए गठजोड़, तो दूसरी तरफ भाजपा का सवर्णों, ओबीसी और दलितों के एक हिस्से का मजबूत सामाजिक गठजोड़। यह मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है।

किया था। इमरान मसूद भी प्रियंका के पसंदीदा नेताओं में हैं। पश्चिमी यूपी के मुसलमानों के बीच उनका काफी प्रभाव भी है। खबरों की मानें तो प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वे इमरान को सपा पर निशाना साधने से रोकेंगी।

इन तमाम घटनाक्रमों से यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस के चुनाव अभियान में प्रियंका की भूमिका केंद्रीय बनी रहेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि अखिलेश और डिम्पल के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। डिम्पल अब जमीन पर लगातार अधिक सक्रिय दिखाई देने लगी हैं। यह सपा की छवि बदलने की कोशिश का हिस्सा है। पहली बार समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन चुनाव को गंभीरता से ले रहा है। दोनों पक्ष जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का 2027 का जनादेश ही 2029 की बड़ी चुनावी लड़ाई की जमीन तैयार करेगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • जब पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर कोई युद्ध नहीं जीत पाता, तो किसी और के लिए कैसे लड़ेगा?

कागज पर मजबूत 'मुस्लिम-नाटो' हकीकत में भी कारगर साबित होगा?

भू-राजनीति



पलकी शर्मा
इंडिया ग्लोबल रिन्यू की संस्थापक
X@palkisu

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने सोमवार (5 अक्टूबर) को अपने 'मक्का गठजोड़' (या कथित 'मुस्लिम-नाटो') को एक्टिवेट करने की दिशा में कदम उठाए। जब पहली बार हूती मिसाइलें सऊदी अरब पर गिरी थीं, तभी सवाल उठा था कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा के लिए आगे आएगा? लेकिन एक महीने तक पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसकी ऊहापोह की पुख्ता वजहें भी मौजूद थीं।

कम से कम सैन्य क्षमता की कमी तो इसकी वजह नहीं हो सकती। ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में पाकिस्तान 14वें स्थान पर है। उसके पास 6.60 लाख सक्रिय और 5.50 लाख रिजर्व सैनिक हैं। उसकी वायुसेना में करीब 1400 विमान हैं, जिनमें चीन के जेएफ-17 और अमेरिका के एफ-16 समेत 300 से ज्यादा फाइटर जेट हैं। फिर उसके पास परमाणु हथियारों का तुरुप का पत्ता भी है। लेकिन जिस चीज की कमी रही है, वह है इन्हें इस्तेमाल करने की रणनीतिक गुंजाइश। इसके तीन कारण रहे हैं- राजनीति, प्राथमिकताएं और पैसा।

पाकिस्तान ने खुद को ईरान युद्ध में मध्यस्थ के तौर पर पेश किया था। उसने यूएस-ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी की और युद्धविराम में मदद की। इस भूमिका को पाकिस्तान आगे भी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इससे उसे प्रभाव और रणनीतिक फायदा मिलता है। इसके लिए ईरान से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। अतीत में दोनों देश एक-दूसरे पर हवाई हमले कर चुके हैं। ईरान पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित कर सकता है, सीमा पर परेशानी या सैन्य तनाव बढ़ा सकता है। ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते पाकिस्तान ऐसी स्थिति को एक महीने से टालना चाह रहा था।

दूसरा कारण है रणनीतिक प्राथमिकताएं। पश्चिम एशिया पैसे और तेल के स्रोत के तौर पर पाकिस्तान के लिए अहम है। लेकिन वह उसका पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान के सामने अपने बिल्कुल नजदीकी क्षेत्रों में ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान को ही लें। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान से टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान को समर्थन मिलता है। दोनों देशों के बीच यह मसला पहले ही हिंसक रूप ले चुका है और सीमा पर हमले तक हो चुके हैं। फिर पाकिस्तान का ध्यान अपनी पूर्वी सीमा पर भी है, जहां उसकी सेना का बड़ा हिस्सा तैनात है। अपने घर के भीतर भी पाकिस्तान आतंकवाद के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है। 2026 के पहले सात महीनों में हुए हमलों में 2700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पीओके में अशांति और बलूचिस्तान में उग्रवाद को लेकर भी पाकिस्तान पर दबाव है। ऐसे में सऊदी अरब उसके लिए जरूरी मोर्चा नहीं था।

अब हम तीसरे कारण पर आते हैं- पैसा। किसी दूसरे देश के लिए युद्ध लड़ना बेहद महंगा होता है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल ऐसा खर्च नहीं झेल सकती। उसकी आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% रहने का अनुमान है, महंगाई दर 10.2% है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार बेहद जोखिमपूर्ण स्थिति में बना हुआ है। उसके विदेशी मुद्रा भंडार का 91% पैसा अन्य देशों से उधार ली गई रकम से बना है। उसकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ, चीन, सऊदी अरब और अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड से मिले विदेशी कर्ज के सहारे है। ऐसे में वह किसी दूसरे के लिए युद्ध लड़ने का खर्च नहीं उठा सकेगा।

पाकिस्तान के करीब 8 हजार सैनिक पहले ही सऊदी अरब में तैनात हैं। उनके साथ वहां 16 जेएफ-17 फाइटर जेट और चीन का एचक्यू-9 एयर-डिफेंस सिस्टम भी है। इस तैनाती का खर्च सऊदी अरब उठा रहा है, जबकि पाकिस्तान इन्हें ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता और हूतियों से राजनीतिक रूप से चर्चा करने का पक्षधर है। ऐसे में सऊदी अरब को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि इन तमाम सैन्य संसाधनों के बाद भी पाकिस्तान की सेना अपने इतिहास में कोई युद्ध नहीं जीत पाई है। और जब वह अपनी ही जमीन पर युद्ध नहीं जीत सकती, तो विदेश में कैसे लड़ सकती है? **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

बड़ी राहत • त्योहारों में रिटेल लोन की शुरुआती लागत घटाने के प्रयास में बैंक, ताकि डिमांड बनी रहे

प्रोसेसिंग फीस माफ, होम लोन पर 0.05% छूट जैसे ऑफर... रेपो रेट बढ़ने का असर कम

सुब्रत पांडा, अंजलि कुमारी | मुंबई

रेपो रेट 0.25% बढ़कर 5.50% होने के बीच कैफे त्योहारी सीजन में ग्राहकों को राहत दे रहे हैं। कर्ज की प्रोसेसिंग फीस माफ हो रही है, ब्याज दरों में रियायत मिल रही है और कार्ड पर कैशबैक की पेशकश की जा रही है। ये सारे ऑफर 10 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए हैं।

नवरात्र से ठीक पहले एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने कई ऑफर दिए हैं। बैंक सिर्फ ब्याज दरें घटाने के बजाय फीस माफी और चुनिंदा रियायतों पर भी जोर दे रहे हैं। एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ बैंकर के मुताबिक, इससे कर्ज की शुरुआती लागत घटेगी और बैंकों का मार्जिन भी बचा रहेगा। यानी ग्राहक को कर्ज लेते समय ही कम पैसे चुकाने होंगे, भले ही ब्याज दर में बड़ी कटौती न हो। साथ ही क्रेडिट कार्ड, ई-कॉमर्स और अन्य शॉपिंग पर छूट व कैशबैक भी मिल रहे हैं।

शॉपिंग पर ₹70 हजार तक बचत से लेकर 10% से कम दर पर पर्सनल लोन तक की पेशकश

बैंक	प्रमुख ऑफर
एचडीएफसी	10,000 से ज्यादा ऑफर। खरीदारी पर ₹70,000 तक बचत। पर्सनल लोन 9.99% (₹50 लाख तक बिना दस्तावेज), कार लोन 8.25% (फोरक्लोजर शुल्क शून्य) और होम लोन 7.2% से शुरू।
एसबीआई	पर्सनल, कार, गोल्ड लोन और म्यूचुअल फंड के बदले लोन पर रियायती ब्याज, प्रोसेसिंग फीस माफ।
पीएनबी	होम लोन पर अपफ्रंट, प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क पूरी तरह माफ, ब्याज में 0.05% की रियायत। कार लोन पर शुल्क माफ।
कोटक महिंद्रा	होम, कार, पर्सनल, बिजनेस, टू-व्हीलर और गोल्ड समेत कई कर्ज पर प्रोसेसिंग फीस में 50% तक छूट।
यस बैंक	प्रोसेसिंग फीस में 50% छूट (दिवाली तक), 10-22 अक्टूबर के बीच किसी भी बैंक के रुपे कार्ड से यस पे नेक्स्ट एप से पेमेंट करने पर कैशबैक।
आईसीआईसीआई	फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज (8 अक्टूबर से) में 10% छूट, एप्पल के चुनिंदा प्रोडक्ट पर 15,000 रुपए तक इंस्टेंट कैशबैक।

होम लोन पिछले साल से 0.20% सस्ता, पर बढ़ा हुआ रेपो रेट दिखा सकता है असर

ऑफर में	2025	2026
होम लोन की शुरुआती दर	7.40%	7.20%
ऑफर कब से शुरू	ओणम से	10 अक्टूबर से
बचत की सीमा	₹50,000 तक कर्ज पर	₹70,000 तक शॉपिंग पर
कर्ज की मांग	सुस्त	मजबूत

(नोटः उदाहरण एचडीएफसी बैंक का; स्रोतः बैंक बाजार)

कर्ज का शुरुआती बोझ घटेगा, किस्तें भी कम रहेंगी

- प्रोसेसिंग फीस एकमुश्त खर्च है, इसलिए यह पूरी तरह माफ होने से शुरुआती बोझ घटेगा।
- ब्याज दर में छोटी रियायत भी मिलने से पूरे लोन पीरियड में किस्त कम रहेगी।
- होम लोन की ब्याज दर में 0.05% रियायत जैसे ऑफर में देखना होगा कि रेपो रेट बढ़ने के बाद ये छूट कितनी रह जाएगी।
- कर्ज लेने से पहले फीस और ब्याज, दोनों की तुलना जरूरी है।

बिजनेस अच्छा, पर प्रतिस्पर्धा के चलते ऑफर की होड़

एक प्राइवेट बैंक के बैंकर ने कहा, 'जब बिजनेस खुद ही बढ़ रहा हो, तो बैंकों को ग्राहक जुटाने के लिए बड़ी छूट की जरूरत कम पड़ती है। साथ ही करीब 3 साल में पहली बार रेपो रेट बढ़ने की वजह से बैंक मार्जिन बचाना चाहते हैं। फिर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बैंकों के बीच ऑफर की होड़ दिख रही है।'

निवेश • एसआईपी फोलियो 28 करोड़, साल भर पहले से 14% ज्यादा

बाजार गिरा फिर भी म्यूचुअल फंड का औसत एयूएम 5% बढ़ा; 3 तिमाहियों में सबसे तेज

अभिषेक कुमार | मुंबई

शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद जुलाई-अगस्त में म्यूचुअल फंड कंपनियों का औसत एयूएयूएम करीब 5% बढ़कर ₹87.2 लाख करोड़ हो गया। यह पिछली तीन तिमाहियों की सबसे तेज ग्रोथ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान एसआईपी और कॉर्पोरेट निवेश का रहा।

यह ग्रोथ तब दर्ज की गई, जब शेयर बाजार में गिरावट के कारण इक्विटी स्कीम्स के पोर्टफोलियो की वैल्यू घटी है। खास तौर पर लार्जकैप सेगमेंट में गिरावट आई। कुछ डेट स्कीम्स भी गिर गए। फिर भी निवेशकों का भरोसा बने रहने से सभी कैटेगरी में निवेश आता रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नए निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा डेट फंड का रहा। छोटी के अवधि के संस्थागत निवेशकों इसमें पैसे लगाए। एक्टिव इक्विटी फंड में निवेश की वजह एसआईपी रही।

सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम कहते हैं कि इक्विटी फंड्स में निवेश का बड़ा हिस्सा अकेले एसआईपी से आ रहा है। शेयर बाजार में बड़ी हलचल के बीच एक्टिव इक्विटी और डेट फंड्स में ही छोटे व बड़े निवेशकों की मजबूत भागीदारी रही।

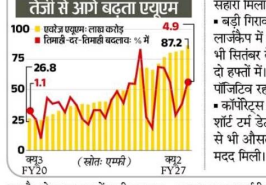
एसआईपी खाते 10.63 करोड़ हुए: एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में एसआईपी के जरिए ₹31,961 करोड़ का निवेश आया। करीब 11 लाख नए एसआईपी खाते जुड़े। इससे कुल एसआईपी खाते 10.63 करोड़ हो गए। इनमें से 9.90 करोड़ खातों से नियमित निवेश हो रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जुलाई में 22.66 लाख नए फोलियो भी जोड़े। कुल फोलियो अब 28.09 करोड़ हैं, जो साल भर पहले से 14.3% ज्यादा हैं।

जुलाई-अगस्त में इक्विटी फंड में सबसे ज्यादा निवेश

कैटेगरी	नेट इनफ्लो
सभी कैटेगरी	2.8 लाख करोड़
एक्टिव इक्विटी	54,000 करोड़
हाइब्रिड	करीब 10,000 करोड़
पैसिव	करीब 10,000 करोड़

(सितंबर के आंकड़े अभी आने हैं।)

तेजी से आगे बढ़ता एयूएम



बाजार गिरने पर भी एयूएम क्यों बढ़ा?

- एसआईपी की रकम पूरे महीने आती है। इससे बाजार की उठापटक में भी औसत एयूएम को सहारा मिला।
- बड़ी गिरावट सिर्फ लार्जकैप में आई, वह भी सितंबर के आखिरी दो हफ्तों में। जुलाई तो पॉजिटिव रहा था।
- कॉर्पोरेट्स की नकदी शॉर्ट टर्म डेट फंड में आने से भी औसत एयूएम को मदद मिली।

बिजनेस ब्रीफ

एयरटेलः पोस्टपेड प्लान ₹50 महंगे, न्यूनतम ₹499

नई दिल्ली| एयरटेल ने पोस्टपेड प्लान के टैरिफ ₹50 बढ़ा दिए हैं। नए प्लान 8 अक्टूबर से लागू होंगे। सबसे सस्ता प्लान अब ₹499 का होगा। साथ ही हर साल एक फ्री इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप मिलेगी। इसमें 5 जीबी डेटा, 60 मिनट कॉल और एसएमएस शामिल हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा और नेटफ्लिक्स जैसे फायदे पहले जैसे रहेंगे।

टाटा मोटर्स अब हर महीने एक लाख कारें बनाएंगी

मुंबई| टाटा मोटर्स ने सप्लायर्स से कहा है कि 2027-28 से हर महीने 1 लाख कारें बनाने की क्षमता बढ़ाएं। अभी कंपनी हर माह करीब 65 हजार कारें बेच रही है। अब मांग ज्यादा है, इसलिए कंपनी उत्पादन बढ़ाना चाहती है। 6 नए मॉडल लॉन्च होंगे। कंपनी ₹37,500-40,000 करोड़ के निवेश से बाजार हिस्सेदारी 20% तक ले जाना चाहती है।

कोर्ट वाली एफडी पर बैंक मनमाना ब्याज नहीं घटाएंगे

नई दिल्ली| दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कोर्ट के आदेश से बनी एफडी पर बैंक मनमाने तरीके से ब्याज नहीं घटा सकते। कोई भी कटौती का वैध आधार होना चाहिए। कोर्ट ने नैटवेस्ट मार्केट्स की अपील खारिज कर दी। बैंक ने ₹5.89 करोड़ की एफडी पर ब्याज घटा दिया था। कोर्ट ने कहा समान जमा पर समान ब्याज जरूरी है।

स्पेसएक्स एनवीडिया चिप्स खरीदने के लिए उधार लेगी

न्यूयॉर्क| दुनिया की सबसे अमीर हस्ती इलॉन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी स्पेसएक्स एनवीडिया से चिप्स खरीदने के लिए 40 अरब डॉलर (3.87 लाख करोड़ रुपए) उधार लेने की तैयारी में है। इसके लिए बैंकों से बातचीत की जा रही है। इसमें 10 अरब डॉलर बैंक लोन और 30 अरब डॉलर डेट (बॉन्ड) शामिल हो सकते हैं। यह एआई डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए है। डील जल्द पूरी हो सकती है। एआई सेक्टर में यह सबसे बड़ी लोन डील में से एक होगी।

फाइनेंस • लोग गहने गिरवी रखकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद रहे

सोने के बदले कर्ज 69% बढ़ा, टीवी-फ्रिज खरीदने के लिए लोन में 56 फीसदी उछाल

आदिति वॉरियर | मुंबई

देश में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने और टीवी-फ्रिज जैसे सामान खरीदने के लिए लोन लेने की मांग तेजी से बढ़ी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) के गोल्ड लोन में सालाना 69.1% उछाल आया। वहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए कर्ज 56.4% बढ़ा।

अगस्त में एनबीएफसी का कुल कर्ज 15.8% बढ़कर ₹60.64 लाख करोड़ हो गया। इसमें रिटेल कर्ज वृद्धि 22% रही और यह 26.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रिटेल कर्ज में गोल्ड लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की वृद्धि सबसे तेज रही।

अगस्त में गाड़ियों के लिए लोन 15%, घर के लिए 12% बढ़े

कर्ज की श्रेणी	सालाना वृद्धि
गोल्ड लोन	69.1%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	56.4%
कृषि लोन	17.4%
ऑटोमोबाइल लोन	15.4%
हाउसिंग लोन	12.1%
इंडस्ट्री लोन	8.40%

घर का सामान खरीदने के लिए लोन वृद्धि दर 3 गुना

टीवी, फ्रिज, एसी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए कर्ज 56.4% बढ़कर 77,784 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसमें 19.6% की वृद्धि हुई थी। वहीं, हाउसिंग लोन 12.1% और वाहन लोन 15.4% बढ़े।

- **रिटेल लोन में एनबीएफसी बैंकों से आगे:** आम जरूरतों के लिए कर्ज देने में एनबीएफसी बैंकों से आगे निकल गए हैं। अगस्त में बैंकों का कुल कर्ज 18.8%, जबकि एनबीएफसी का 15.8% बढ़ा। लेकिन रिटेल कर्ज में एनबीएफसी की वृद्धि 22%, जबकि बैंकों की 16.9% रही।

सोने के बदले कर्ज लेने की रफ्तार एक साल में डेढ़ गुना:

अगस्त में एनबीएफसी का गोल्ड लोन 69% बढ़कर ₹3.65 लाख करोड़ हो गया। एक साल पहले इसकी वृद्धि 46.8% थी। यानी सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने की रफ्तार एक साल में डेढ़ गुना हो गई।

इस्तेमाल से नहीं, प्रोडक्ट के स्वरूप से तय होगा टैक्स

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सामान पर टैक्स की दर बिक्री के समय उसके स्वरूप से तय होगी, न कि इससे कि ग्राहक उसका इस्तेमाल कैसे करता है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने केडिला हेल्थकेयर के जीआरडी पाउडर और जीआरडी मिक्स के मामले में यह फैसला सुनाया। ये पाउडर या बिस्कुट के रूप में बिकते हैं। मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत टैक्स विभाग इन्हें गैर-अल्कोहलिक पेय मानकर 10% टैक्स लगाना चाहता था। कोर्ट ने विभाग की अपील खारिज करते हुए कहा कि इन पर 8% ही टैक्स लगेगा, क्योंकि बिक्री के समय ये पेय नहीं, पाउडर थे। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि प्रोटीन पाउडर पर पाउडर का टैक्स लगेगा, जबकि बोतलबंद कोल्ड कॉफी या तैयार प्रोटीन शेक पर ड्रिंक का टैक्स।

न्यूयॉर्क में जगुआर की नई इलेक्ट्रिक कार टाइप 01 पेश; 1.6 करोड़ दाम, लेकिन चर्चा खूबियों नहीं खामियों की



न्यूयॉर्क| जगुआर की नई इलेक्ट्रिक कार टाइप 01 न्यूयॉर्क में पेश होते ही चर्चा में है, पर खूबियों के लिए नहीं। 1.30 लाख पाउंड (₹1.66 करोड़) की इस कार को कई लोग शव वाहन जैसी बता रहे हैं। निजी कार कलेक्शन सलाहकार क्रेग किनर्सले ने इसे बेहद बदसूरत कहा। यह कार 5.2 मीटर लंबी है और पीछे शीशा नहीं है। एक चार्ज में अधिकतम 400 मील (644 किलोमीटर) चलने और सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पकड़ने का दावा है। कंपनी युवा और अमीर ग्राहक चाहती है, इसलिए उसने पुराना लोगो और क्लासिक अंदाज छोड़ दिया। अभिनेत्री फ्लोरेंस प्यू इसकी ब्रांड एंबेसडर हैं।

ग्रोथ सेगमेंट • गूगल, रेडसीर ने लगाया अनुमान

क्विक कॉमर्स 5 साल में 7 गुना बढ़कर ₹8.71 लाख करोड़ होगा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारत का क्विक कॉमर्स बाजार अब सिर्फ इमरजेंसी खरीदारी तक सीमित नहीं रहा। यह पूरे महीने के घरेलू बजट और राशन की खरीदारी में हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है। गूगल और रेडसीर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बाजार वित्त वर्ष 2026 के ₹1.26 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 2031 तक 7 गुना बढ़कर ₹8.71 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। मासिक यूजर्स 10 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे।

त्योहारी सीजन में क्विक कॉमर्स की बिक्री में 110% की भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह कुल ऑनलाइन त्योहारी बिक्री का 18% होगा। कंपनियां अब इमरजेंसी टॉप-अप के बजाय ग्राहकों को बड़े पैक्स और बेहतर वैल्यू दे रही हैं। रिमाइंडर और ऑटो-रीऑर्डर के जरिए यूजर्स को मासिक राशन ऑर्डर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 300 से ज्यादा शहरों में 20 करोड़ ऑनलाइन खरीदार हैं, जहां 95% लोग यह सर्विस जानते हैं। यहां क्वालिटी और भरोसे की चिंता दूर करके 6 करोड़ नए मंथली यूजर्स जोड़े जा सकते हैं।

ग्रोथ में 60% योगदान दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों का

रिपोर्ट के मुताबिक, क्विक कॉमर्स की ग्रोथ में मेट्रो शहर सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। वित्त वर्ष 2031 तक कुल ग्रोथ में 60% योगदान मेट्रो शहरों का होगा। यहां कुल रिटेल खर्च में क्विक कॉमर्स का हिस्सा 6% से बढ़कर 23% तक पहुंचेगा।

आउटलुकः 9 गुना बढ़ेगा नॉन-ग्रॉसरी मार्केट

पैमाना	FY26	FY31
बाजार का आकार	₹1.26 लाख करोड़	₹8.71 लाख करोड़
मासिक एक्टिव यूजर्स	3 करोड़	10 करोड़
नॉन-ग्रॉसरी मार्केट	₹29,034 करोड़	₹2.61 लाख करोड़
मेट्रो यूजर्स	2.8 करोड़	5 करोड़

टाटा ट्रस्ट्स ने चैरिटी कमिश्नर के पास 84 कैवियट दाखिल कीं; नोएल, नेविल कैवियटर

भास्कर न्यूज | मुंबई

टाटा ट्रस्ट्स में चल रही अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) को छोड़कर बाकी ट्रस्टों ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के सामने 84 कैवियट (अर्जी) दाखिल की हैं। इनमें नोएल टाटा और उनके बेटे नेविल टाटा को कैवियटर बनाया गया है। कैवियट का मतलब है कि कमिश्नर कोई भी आदेश देने से पहले इनकी बात जरूर सुनेंगे। यह एहतियाती कदम है, क्योंकि नोएल और नेविल के खिलाफ कई व्यक्तिगत आरोप लगे हैं। विवाद की जड़ एसडीटीटी के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की आपत्तियां हैं। श्रीनिवासन ने नोएल टाटा की स्थायी ट्रस्टी और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति की जांच की मांग की है। नोएल को टाटा संस की आम बैठकों में एसडीटीटी या दूसरे ट्रस्टों की ओर से वोट देने से रोकने की मांग भी की है। नेविल को ट्रस्टी बनाने पर भी सवाल उठाया गया है। आरोप है कि फैसले कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट गए हैं।


नोएल टाटा


नेविल टाटा

रेपो रेट बढ़ने, क्रूड 102 डॉलर तक पहुंचने से सेंसेक्स 429 अंक गिरा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

रेपो रेट 0.25% बढ़ाए जाने से घरेलू शेयर बाजार में दो दिन से जारी तेजी थम गई। बुधवार को सेंसेक्स 429 अंक गिरकर 72,639 पर और निफ्टी 173 अंक टूटकर 22,603 पर बंद हुआ। दरअसल रिजर्व बैंक के नए रुख से निकट भविष्य में रेपो रेट में कटौती की संभावना खत्म हो गई है। इस बीच कच्चे तेल (क्रूड) की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों द्वारा ₹6,121.37 करोड़ के शेयर बेचे जाने से भी बाजार का रुझान प्रभावित हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.4% बढ़कर एक बार फिर 102 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। इस बीच सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर गिरकर बंद हुए। टाइटन, बीईएल, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। दूसरी तरफ कोटक बैंक, एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक में तेजी देखी गई।

राहत • एक ही कंपनी की बार-बार जांच से मिलेगा छुटकारा, नई व्यवस्था 1 अप्रैल से

65 लाख सीजीएसटी टैक्सपेयर का 'फेसलेस असेसमेंट'

अस्सि रंजन मिश्र | नई दिल्ली

सरकार अब इनकम टैक्स और कस्टम्स की तर्ज पर सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) में भी 'फेसलेस असेसमेंट' का विकल्प देने जा रही है। इस पहल से 65 लाख सीजीएसटी टैक्सपेयर्स में से उन 3.3 लाख मल्टी-स्टेट कारोबारियों को राहत मिलेगी, जो अलग-अलग टैक्स ऑफिसरों के नोटिस, सुनवाई और ऑडिट की समस्या झेलते हैं। वित्त मंत्रालय इसे 1 अप्रैल, 2027 से लागू करने की तैयारी में है।

फेसलेस असेसमेंट सिस्टम से क्या-क्या बदलेगा?

- कारोबारियों और जीएसटी अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क खत्म होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- रजिस्ट्रेशन, संशोधन, ऑडिट और रिफंड क्लेम की प्रक्रिया अभी के मुकाबले तेजी से पूरी होगी।
- अनुपालन (कम्प्लायंस) में लगने वाला समय बचेगा। इससे कंपनियां अपने मुख्य बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी।

मौजूदा व्यवस्था	नया यूनिफाइड प्लान
अधिकारियों के सामने भौतिक सुनवाई	पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और फेसलेस
अलग-अलग क्षेत्रों से बार-बार जांच	एक ही यूनिफाइड सिस्टम से असेसमेंट
केवल CGST कारोबारियों पर लागू	केंद्र के बाद राज्य भी अपना सकेंगे

चूक पर सिर्फ टैक्स-ब्याज-जुर्माना

जीएसटी की ज्यादातर गलतियां आपराधिक दायरे से बाहर होंगी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

जीएसटी भरने में देरी या चूक अब उतना नहीं डराएंगी, जितना अभी डराती हैं। ऐसे ज्यादातर मामलों में कारोबारियों को जेल का डर नहीं रहेगा। सरकार टैक्स सिस्टम को भरोसे पर आधारित बनाने जा रही है। इसके तहत जीएसटी के कई अपराध आपराधिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय में इस तैयारी से जुड़े लोगों के मुताबिक, प्रस्ताव 8 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में रखा जाएगा। हालांकि बैठक में टैक्स की दरों में कटौती पर चर्चा की उम्मीद नहीं है।

फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देरी, गलती या पैसे की तंगी पर करदाता से सिर्फ टैक्स, ब्याज और अनुपात में जुर्माना वसूला जाएगा। गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अधिकारियों के बजाय प्रवर्तन एजेंसी के पास रहेगा और तभी इस्तेमाल होगा, जब आपराधिक मंशा साबित हो। वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने 72,300 से ज्यादा मामले दर्ज किए और 887 गिरफ्तारियां कीं।

रिफंड का दावा करने पर 10 दिन में पावती मिलेगी, वरना उसे मंजूर माना जाएगा। यह पांच हिस्सों वाले सुधार पैकेज का हिस्सा है, जिसमें प्रक्रिया, ढांचा, कारोबार में आसानी, सर्विस निर्यात और ई-कॉमर्स शामिल हैं। सभी बदलाव चरणों में 2027 तक लागू होंगे।

कारोबारियों को और क्या-क्या राहत

छोटे करदाता, जो सिर्फ ग्राहकों को सामान बेचते हैं, साल में एक बार रिटर्न भर सकेंगे (अभी प्रारंभिक चरण में)। जिस खरीदार के पास बिल है और माल व भुगतान पूरा हो चुका है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बना रहेगा। ई-कॉमर्स विक्रेताओं का सत्यापन सिर्फ अपने राज्य में होगा।

छत्तीसगढ़ में 14,000 करोड़ का निवेश

एनटीपीसी अब कोयले से गैस बनाने के बिजनेस में उतरेगी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी अब कोयले से गैस बनाने के बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी छत्तीसगढ़ के तलाईपल्ली में कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट पर करीब 14,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एनटीपीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यहां हर साल 5 लाख टन सिंथेटिक नेचुरल गैस (एसएनजी) बनेगी, जिसकी लागत 13 डॉलर (₹1257.6) प्रति यूनिट रहेगी। एनटीपीसी को केंद्र सरकार की योजना के तहत करीब 2,000 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) मिलने की उम्मीद है। इसके लिए कंपनी को फिलहाल सरकार की मंजूरी का इंतजार है। प्रस्तावित योजना पर आसानी से काम शुरू किया जा सकता है। जमीन कंपनी के पास है और डीपीआर (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार है। बाकी रकम कर्ज से जुटाई जाएगी। प्रोजेक्ट अगले 4-5 साल में शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। एनटीपीसी योजना के दूसरे दौर में भी आवेदन करेगी।

बिजनेस एंकर पैरामाउंट ने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का अधिग्रहण पूरा किया,10.6 लाख करोड़ की डील

नेटफ्लिक्स-अमेजन को चुनौती देने हॉलीवुड के दो दिग्गज एक हुए, हैरी पॉटर, मिशन इम्पॉसिबल, एचबीओ, सीएनएन एक ही छत के नीचे

बिजनेस संवाददाता | न्यूयॉर्क

हैरी पॉटर, मिशन इम्पॉसिबल, एचबीओ और सीएनएन अब एक ही छत के नीचे हैं। पैरामाउंट स्काईडांस ने मंगलवार को वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का अधिग्रहण पूरा कर लिया। करीब 10.6 लाख करोड़ रुपए की यह डील मीडिया इतिहास के सबसे बड़े मर्जर में गिनी जा रही है।

रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका के कई राज्यों के समूह और हॉलीवुड के लेखक संगठन से समझौते के बाद कानूनी अड़चनें दूर हुईं। अब पैरामाउंट, सीबीएस, डीसी स्टूडियोज, एचबीओ मैक्स और सीएनएन जैसे ब्रांड सीईओ डेविड एलिसन की कमान में एक कंपनी का हिस्सा हैं।

इस डील की वजह हॉलीवुड की बदलती सेहत है। केबल टीवी के ग्राहक घट रहे हैं, स्ट्रीमिंग दर्शकों को अपने पक्ष में करने के लिए होड़ महंगी है और यूनियनें नौकरियों व रचनात्मक काममारों के अधिकारों पर दबाव बनाए हुए हैं। एलिसन ने कर्मचारियों को भेजे मेमो में इसे अगली पीढ़ी की मीडिया कंपनी बनाने का मौका बताया। उनका कहना है कि मकसद सिर्फ बड़ा होना नहीं, इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों से टक्कर लेना भी है।

एलिसन ने पुराने हॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा कि उसने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो को अपना बिजनेस बिगाड़ने दिया और बदलाव नहीं किए। इसी सोच के तहत स्काईडांस पैरामाउंट+ और एचबीओ मैक्स को मिलाकर एक फ्लैगशिप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाएगी।

2010 में एलिसन की तरफ से शुरू की गई स्काईडांस ने 16 साल में लंबा सफर तय किया है। 'टॉप गन: मेवरिक' में पैसा लगाकर पहचान बनाने वाली कंपनी ने पिछले साल पैरामाउंट में मर्जर किया और फिर वॉर्नर पर नजर डाली। इस पर नेटफ्लिक्स से कड़ी बोली की जंग छिड़ी और कॉमकास्ट ने भी रुचि दिखाई। हॉलीवुड की नाराजगी पर एलिसन का जवाब था कि समस्या के लक्षण बहुत पुराने हैं, इसलिए यह भी सोचना चाहिए कि विकल्प क्या था।

डिस्कवरी के अधिग्रहण की डील कितनी बड़ी... इन 4 पॉइंट्स में समझें



1. **कंटेंट पर दांव:** हर साल 30 अरब डॉलर (करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए) का खर्च। पहले दो साल सालाना 30 फिल्में, फिर तीन साल 32 फिल्में।
2. **कर्ज का बोझ:** कंपनी पर करीब 80 अरब डॉलर (7.7 लाख करोड़ रुपए) का कर्ज है। इसने 6 अरब डॉलर (58,000 करोड़ रुपए) की बचत का लक्ष्य रखा है। इससे छंटनी की आशंका गहराई।
3. **कमान बंटी:** मैटल के पूर्व सीईओ यनॉन क्रीज को-सीईओ बने हैं, जो रोजमर्रा का ऑपरेशन देखेंगे। रचनात्मक दिशा और रणनीति एलिसन के पास रहेगी।
4. **न्यूज पर नजरः** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील का स्वागत किया। सीएनएन और सीबीएस न्यूज के प्रमुख अलग-अलग रिपोर्ट करेंगे। संपादकीय स्वतंत्रता बोर्ड बनेगा, जिसे विशेषज्ञ 'दंतहीन' बता रहे हैं।